Uncorrected/Not for publication - 20.08.2010

AKG-PB/1a/11.00

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

प्रश्न संख्या - 381

श्री रुद्रनारायण पाणि : धन्यवाद सभापति महोदय। उड़ीसा में कृषि योग्य भूमि बड़े पैमाने पर उद्योगों को दी जा रही है। मेरे आज के इस महत्वपूर्ण सवाल में यह बात थी कि कृषि योग्य भूमि को औद्योगिक घरानों को दिए जाने से गाँवों से पलायन होता है। भले ही इस सरकार ने महात्मा गाँधी NREGA योजना शुरू की है, लेकिन फिर भी अगर बड़े पैमाने पर औद्योगिक घरानों को, SEZs को कृषि योग्य भूमि दी जाती है, जिससे गाँवों में जो उद्योग लगते हैं, उनमें रोजगार के अवसर बहुत कम होते हैं। फिर जो औद्योगिक घरानों का विकास होता है, जो उद्योगों का विकास होता है, उनके प्रदूषण का खेत पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण आसपास की खेती में भी कोई काम नहीं होता है।

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि : सर, सरकार ने माना है कि पलायन का कारण अलग-अलग है, लेकिन फिर भी कृषि योग्य भूमि को औद्योगिक घरानों को दिए जाने से भी पलायन होता है, सरकार ने ऐसा माना है। मेरा specific सवाल है कि क्या केन्द्र सरकार को यह पता है, क्या केन्द्रीय कृषि मंत्रालय को यह पता है कि उड़ीसा में लगभग एक लाख हेक्टेयर भूमि औद्योगिक घरानों को दे दी गई है और किसान उद्योगों को जो जमीन देते हैं, सरकार की R&R Policy के तहत पर्याप्त रूप से उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है?

श्री सभापति : पाणि जी, आपका सवाल हो गया।

श्री रुद्रनारायण पाणि : सर, सवाल यह है कि पर्याप्त रूप से मुआवजा नहीं दिया जाता है। जब किसान आन्दोलन करते हैं, तो उन पर लाठी-डंडा बरसाया जाता है।

श्री सभापति : आपका सवाल क्या है?

श्री रुद्रनारायण पाणि : सर, सवाल यह है कि औद्योगिक घरानों के कारण प्रदेश से पलायन हो रहा है, तो क्या सरकार को यह पता है और क्या सरकार उड़ीसा के किसानों को राज्य सरकार से पर्याप्त रूप से कुछ मुआवजा दिलाने के लिए प्रयास कर रही है?

PROF. K.V. THOMAS: Sir, according to our Constitution, the land management and agriculture are State subjects. But we have given some directives to all the States according to the National Policy for Farmers and according to the National Rehabilitation and Resettlement Policy. So, it is for the State Governments to follow our guidelines, and, Sir, in Orissa, the land acquisition takes place as per the Orissa Land Acquisition Amendment Act and Orissa Resettlement and Rehabilitation Policy. So, if there are some specific complaints, Sir, we will definitely look into them.

श्री सभापति : दूसरा सवाल पूछिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि : सभापति महोदय, केन्द्र सरकर ने माना कि उड़ीसा की R&R Policy में defect है और किसानों को ढंग से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है ... (व्यवधान) ... मैं बता सकता हूँ ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि : सर, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास सूचना है, तथ्य है कि वहाँ पर irrigated land को भी औद्योगिक घरानों को दिया जा रहा है? वहाँ पर एक "Rengali Irrigation Project" है, जिसका शिलान्यास श्रीमती इंदिरा गाँधी जी ने किया था और जिसका उदघाटन डा. संजीव रेड्डी जी ने किया था। इस प्रोजेक्ट में जो प्रस्तावित सिंचाई योग्य भूमि है, उसको सरकार ने GMR Energy नामक कम्पनी को दिया है। मेरा specific सवाल है कि औद्योगिक घरानों को जो irrigated land दिया जा रहा है, तो क्या भारत सरकार ने इसके बारे में राज्य सरकार से कुछ मामला उठाया है, बात की है?

(1बी/डीएस पर जारी)

Q. No. 381 (Contd.)

श्री रुद्रनारायण पाणि (क्रमागत): हम वर्ल्ड बैंक से करोड़ों रुपये लोन लेकर इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: पाणि जी, आप एक बात कहिए। ..(व्यवधान)..

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, मेरा सवाल स्पेसिफिक है। हम हजार करोड़ रुपये लागत लगाकर, वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर, इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स करते हैं, लेकिन उसमें हमारी दूरदृष्टि नहीं होती कि उन इरिगेटेड लैंड्स को औद्योगिक घरानों को देने का सरकार का क्या उद्देश्य है। केन्द्र को राज्यों के साथ यह मामला उठाना चाहिए। क्या उसने इसे उठाया है?

श्री सभापति: प्लीज़। देखिए, आपका भाषण कहाँ शुरू होता है, सवाल कहाँ शुरू होता है, यह कोई नहीं समझ रहा है। ..(व्यवधान)..

PROF. K.V. THOMAS: Sir, similar problems were raised a few days back in the Lok Sabha and the hon. Finance Minister had given a clear answer, stating that a comprehensive land acquisition Bill is being considered by a Group of Ministers. This is an important issue. After consultation with all the political parties and concerned people connected with this issue and the State Governments, Government of India proposes to bring a comprehensive land acquisition Bill. As I have said, if there are any specific cases in Orissa, they may be brought to our notice and we would follow them up with the State.

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, मैंने स्पेसिफिक क्वैश्चन पूछा था। ..(व्यवधान).. मैंने इरिगेटेड लैंड के बारे में पूछा था।..(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: No; No more. (Interruptions) Please, Pany*ji*. Shri Govindrao Wamanrao Adik.

SHRI GOVINDRAO WAMANRAO ADIK: Sir, as far as the land for SEZ is concerned, it has been said in the reply that the Government of India had issued certain guidelines or advice to the State Governments for acquiring certain types of land and not acquiring agricultural lands that are very productive. But I would like to know from the hon. Minister, when these guidelines are not strictly followed and advice is violated, what steps would the Government of India take against the States concerned?

PROF. K.V. THOMAS: Sir, as I have said in reply to the first question, this is primarily a State subject; we can only issue guidelines. But, in certain cases, like the Special Economic Zones, Government of India has taken a very strong step. We have intimated the State Governments that for allocation of land, for multi-product SEZ, when they acquire land, the fertile land should not be more than ten per cent of the total land acquired, and even when this ten per cent land is taken, non-fertile land to the same extent should be converted into agricultural land. So, this is the stand taken by the Government of India where we can take some decisions, in the case of Special Economic Zones.

SHRI GOVINDRAO WAMANRAO ADIK: Sir, my question has not been answered; I seek your protection. My question has not been answered. I had specifically asked the hon. Minister, what steps Government of India would take against the State Governments when these guidelines are not accepted by them, or, are violated?

PROF. K.V. THOMAS: Sir, as it is a federal system, we can only issue guidelines. It is for the State Governments to follow the guidelines.

SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, this is, indeed, a very important question and I have gone through the reply of the Government. It is a detailed reply, but, unfortunately, it does not address the real issue. The reply states that land has remained static and it has not increased, but agricultural production has increased; therefore, the fear that migration has led to decreased agricultural production is not true. The real issue is, over the years, land holdings have become fragmented. Agriculture, for marginal farm owners, has become economically unviable. That is why, there is need to establish industries that can generate employment. Take, for instance, the States of Punjab, Haryana, Kerala; there is not an inch of land with low biological potential, arid, uncultivable, land affected by salinity or acidity or degraded land.

(Contd. at 1c/hk)

SHRI ASHWANI KUMAR (CONTD.): What do we do? Our agriculturists feel that economic activity in these States is economically unviable. You need industries. The question for the hon. Minister is: What kind of a holistic policy prescription are you coming up with so that while fertile agriculture land is put to agricultural use yet States are not deprived of industrial activity because industry has to be set up on land? One-sided policy prescription is not going to reduce poverty.

PROF. K.V. THOMAS: Sir, I am confined to the main question. The policy of the Government is that as far as possible the fertile land should be used only for agricultural purpose. If any State Government wants some fertile land for industrial purposes because of certain reasons, it has to find out equivalent non-fertile land for agricultural purpose. This is a confined policy of the Government of India. I understand that we need industries, but those industries should be on non-fertile land. ...(Interruptions)...

SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, my question is not answered. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: No supplementaries on supplementaries. ...(Interruptions)...

श्री विनय कटियार : माननीय सभापति जी, यह बात ठीक है कि कृषि योग्य ज़मीन का सवाल किसी एक राज्य का नहीं है। पूरे देश के अंदर सरकारें मनमाने तरीके से उनका अधिग्रहण करती हैं और बड़े-बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये ज़मीनें दी जाती हैं। चाहे उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो, इन सभी राज्यों में आए दिन कई-कई हज़ार एकड़ ज़मीनें आप बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दे देते हैं। उन पर कौन सा कानून लगता है? राज्य सरकार तो कभी वन विभाग के कानून का बहाना बनाकर या कोई और बहाना बनाकर इसे रोक भी सकती है, लेकिन आपकी केन्द्र सरकार तुरन्त रातों-रात उनको clearance दे देती है। क्या इसके कारण नक्सलवाद बढ़ रहा है? आज जो बेरोज़गारी हो रही है, जंगलों का कटान हो रहा है, उसके कारण .... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप सवाल पूछिए।

श्री विनय कटियार : उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में बहुत पहले पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए ज़मीन का अधिग्रहण हुआ था, लेकिन आज तक पावर प्रोजेक्ट नहीं लगा। क्या उस ज़मीन को आप किसानों को वापस दिलाएंगे?

PROF. K.V. THOMAS: Sir, every State in the country has got its own land acquisition rules and amendments. In Orissa, there is Orissa Land Acquisition Amendment and in Kerala there is Kerala Land Utilisation Order. What we can do is that we can give guidelines. We can interfere when permissions are sought for multiple zones by the State Governments. There we can impose some restrictions. This is the only way by which the Government of India can interfere. ...(Interruptions)...

श्री विनय कटियार : क्या आप उत्तर प्रदेश की ज़मीन वापस कराएंगे? ... (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं ... (व्यवधान) कटियार जी, आप बैठ जाइए ... (व्यवधान)

श्री विनय कटियार : सभापति जी, मैंने जो बेसिक प्रश्न पूछा है ... (व्यवधान) जहां जमीनों का उपयोग ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not agitate in the House. ...(Interruptions)... आप बैठ जाइए ... (व्यवधान) This is not going on record. ...(Interruptions)....

श्री विनय कटियार : *

MR. CHAIRMAN: Q.No.382

(समाप्त)

---

* **Not recorded**

SHRI TARINI KANTA ROY: Sir, the reply given is "Bhopal-New Delhi Shatabdi Express had a late start of 5 minutes from Bhopal on account of delay in boarding of the train by some passengers." Who were those passengers? Trains like Shatabdi and Rajdhani are prestigious trains. For whom it was delayed should be known to the House.

(Contd. by 1d/KSK)

-NB/VNK-KSK/1d/11:15

SHRI TARINI KANTA ROY (CONTD): This august House has a right to know that for whom prestigious trains like *Shatabdi* and *Rajdhani* are being delayed. The delay may be of two minutes or five minutes. But, there was delay. I want to know from the Minister for whom, this train was delayed.

SHRI E. AHAMMED: Mr. Chairman, Sir, in this particular matter, the train took five minutes extra to start from Bhopal to help some last-minute foreign tourists to board the train. They arrived at the railway platform and the Railway people had helped them to board the train. They were all foreign tourists. That was the reason for five-minute delay.

SHRI TARINI KANTA ROY: Sir, it has been reported in the media that the passengers were from America, and for those Americans, the train was delayed. But, I would like to mention that the train was delayed as per the directions given from the Railways Headquarters in New Delhi. I want to know whether it is true or not.

KM. MAMATA BANERJEE: Sir, first of all, the hon. Member should appreciate that the country's prestige comes first. We always give hospitality to foreigners. They are our guests, whether they are from America, Russia, or, China. They had given the prior information that they were 15 minutes late because of some traffic jam or something like that. They crossed the foot over-bridge. So, they had taken permission not from the Railways Headquarters at New Delhi; it was from the Divisional Headquarters in consultation with the Station Master and the Divisional Control. They had requested for fifteen passengers. And, I would like to inform the House that this train was not delayed. It started five minutes late, but it reached Delhi only eight minutes late. In our official system, if it is a delay of less than fifteen minutes, it is considered punctual.

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान भी दिलाना चाहता हूँ और उनसे पूछना भी चाहता हूँ कि बहुत सी ट्रेनें बहुत ज्यादा लेट हो रही हैं, जो ट्रेनें लेट हो रही हैं, उनको सही समय पर लाने के लिए आपने कौन सी नई योजना बनाई है और क्या निर्देश जारी किए हैं? दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बंगाल और बिहार से होकर जितनी भी ट्रेनें आती हैं, वे सारी ट्रेनें बहुत ज्यादा लेट आती हैं। जितनी भी ट्रेनें लखनऊ पहुंचती हैं, वे सारी ट्रेनें दो-तीन घंटे लेट पहुंचती हैं। क्या माननीय मंत्री जी इसके लिए कोई ऐसा उपाय करेंगे, जिससे बंगाल और बिहार से होकर उत्तर प्रदेश में आने वाली ट्रेनें समय पर पहुंचे, ताकि यात्रियों को असुविधा न हो? साथ ही साथ, रेलवे प्रणाली के सिस्टम में ट्रेनों के आने और जाने के समय के बारे में जानकारी दी जाती है, उसमें हर समय कहा जाता है कि सही समय पर है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: देखिए, सवाल एक ट्रेन का है ...(व्यवधान)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवालः श्रीमन्, मैंने ट्रेन लेट पर ही सवाल पूछा है, कोई दूसरा सवाल नहीं पूछा है। ..(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आप सवाल पढ़िए ...(व्यवधान)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवालः श्रीमन्, मैंने पढ़ लिया है, मैंने पूरे सिस्टम पर पूछा है कि ट्रेनें जो लेट हो रही हैं, उसके लिए क्या उपाय सोचा है? ...(व्यवधान)... मैंने वही पूछा है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आप इसके लिए दूसरा सवाल दीजिए। ...(व्यवधान)..

कुमारी ममता बनर्जीः सर, मैं Member की आभारी हूँ कि उन्होंने एक अच्छा प्रश्न पूछा है। Though it is not related to this question, but in general interest, मैं जानकारी देना चाहूंगी और हाउस को भी इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। सर, बहुत सारी ट्रेनें लेट होती हैं, क्योंकि "रास्ता रोको" किया जाता है, "रेल रोको" किया जाता है, Obstruction किया जाता है, रेल को रोक दिया जाता है ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्यः कौन करता है?

कुमारी ममता बनर्जीः बहुत सारी political parties भी करती हैं...(व्यवधान)... Don't ask me and don't insist me; I am not going to name. (interruption)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवालः उसको क्लीयर कर दीजिए। ...(व्यवधान)...

KM. MAMATA BANERJEE: I may fight my battle politically outside the House, and not inside. I always maintain the dignity of this House. Sir, with your kind permission, I want to inform that sometimes, because of some flood, natural disaster, the trains may be late. But, Sir, nowadays, because of road blockade, rail blockade, delay of trains has increased like anything. In eleven per cent

cases, delay of trains is due to these blockades. This is horrible thing. I will appeal to all my countrymen that don't delay the trains.

(continued by 1e - ysr)

YSR-MP/11.20/1E

कुमारी ममता बनर्जी (क्रमागत) : अगर वह पश्चिमी बंगाल में रुकती है तो बिहार के लिए लेट हो जाती है because train passes through one State to another. देखिए, बिहार से पश्चिमी बंगाल जाते हैं, पश्चिमी बंगाल से बिहार जाते हैं। जब दिल्ली आते हैं, तो बिहार, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, सब जगह घूमकर ट्रेन आती है। ....(व्यवधान)...

श्री सभापति : प्लीज़....प्लीज़.... (व्यवधान)...

श्री ब्रजेश पाठक : महोदय, यह नहीं पता चला कि माननीय मंत्री महोदया किस पर आरोप लगा रही हैं? ..(व्यवधान)... कौन ट्रेन रोक रहा है?

KM. MAMATA BANERJEE: Because railway is the lifeline of the nation. (Interruptions)

श्री सभापति : पाठक जी, प्लीज़...

KM. MAMATA BANERJEE One train passes throughout the country. (Interruptions) If any problem arises in any State, it affects the whole system और whole system अगर affect होता है, तो उसमें controlling loss होता है। We are really sorry for that. This time we are maintaining record. (Interruptions)

श्री ब्रजेश पाठक : कौन लोग जिम्मेदार हैं?

MR. CHAIRMAN: Please. (Interruptions) Thank you.

KM. MAMATA BANERJEE: Sir, just one minute. We are maintaining the punctuality, which is 75 per cent. This time we are keeping actual, fool-proof

record. Because of *Rail rocko*, obstruction, sabotage and all these things we are losing 11 per cent. Even then we are maintaining our level of punctuality, which is 75-80 per cent.

श्री राजनीति प्रसाद : सर, मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि ट्रेन तो स्टेशन के बाहर right time पर पहुंच जाती है, लेकिन स्टेशन पर पहुंचने में outer पर उसे आधा घंटा लग जाता है, तो यह ...(व्यवधान)... बोलने दीजिए, हमें बहुत कम चांस मिलता है। जब आधा-आधा घंटा ट्रेन वहां रुकती है, तो हमें बहुत तकलीफ होती है, तो क्या आप स्टेशन पर कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगी कि जो गाड़ियां समय से आ रही हैं, वे समय से स्टेशन पर पहुंच जाएं? यही मेरा सवाल है।

KM. MAMATA BANERJEE: Sir, though this question is not related to this question, यह जनरल क्वेश्चन है, लेकिन तब भी मैं कहना चाहूंगी कि earlier 1.8 million passengers used to travel by the Railways. अभी पैसेंजर्स बहुत बढ़ गए हैं जो कि 2 करोड़ 20 लाख हो गए हैं। अब पैसेंजर्स की संख्या बहुत बढ़ गई है, लगभग 1 करोड़ और हमारा infrastructure इतना नहीं बढ़ा लेकिन जो भी अपग्रेडेशन हमने किया है, congestion बहुत है। Everybody is asking for train. I think that if you observe it, you will realize that our infrastructure needs upgradation, modernization. We need more infrastructure. Sometimes it also affects the system. If you ask for more stoppage, we are willing to give it, but you have to see it from the operational point of view. There is some congestion. We are trying to increase more and more infrastructure so that people don't suffer.

श्री अनिल माधव दवे : सभापति जी, चाहे Union Carbide का Anderson हो या फिर शताब्दी में जाने वाले अमेरिकन हों, भोपाल में हम इन सबको विशेष privilege देते ही हैं और दिल्ली के आदेश पर देते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : सवाल पूछिए।

श्री अनिल माधव दवे : सवाल मैं यह पूछ रहा हूं, मेरा रेलवे से related एक प्रश्न है और वह भोपाल से है कि भोपाल की सेंट्रल रेलवे में जब भी कोई वेस्टर्न रेलवे से ट्रेन आती है, particularly उज्जैन और इंदौर की तरफ से, तो वह वहां पर आधा-आधा घंटा रुक जाती है। जब वह वहां रोक दी जाती है, तो उसके दोनों ओर रेलवे की भूमि पर इतना अतिक्रमण है कि इसके कारण पैसेंजरों को अत्यधिक परेशानी होती है। लोग उसमें चढ़कर पानी भरते हैं और अंदर जो महिलाएं होती हैं, उनके साथ बदतमीज़ी भी होती है। तो इसको लेकर, रेलवे भूमि पर हुए अतिक्रमण के संबंध में, कोई इसकी सुरक्षा या चिंता है क्योंकि अगर वोटों की तरफ देखेंगे तो कभी भी इसका निर्णय नहीं हो सकता है?

कुमारी ममता बनर्जी : सर, क्या होता है कि अभी कोई ट्रेन time पर चलती है, लेकिन अगर road blockade हो गया और मान लीजिए कि एक ट्रेन को 10.10 बजे cross करना है लेकिन वह लेट हो गई और दो trains एक साथ आ गईं तो यह तो ऑपरेशनल कंडिशन होती है। इसी की वजह से ऐसी परिस्थिति होती है। If it is running as per normal schedule, then there is no problem. From the operational point of view, the problem is because of delay due to some blockade and when some problem is being created. अगर यह होता है, आप जब प्लेन में जाते हैं तो क्या होता है? आसमान में प्लेन आधा घंटा चक्कर लगाता है। They are not getting the permission from air traffic control, तो क्या करें?

(समाप्त)

(Q. No. 383 -- Hon. Member absent)

MR. CHAIRMAN: Any supplementary question? Dr. Bhalchandra Mungekar.

DR. BHALCHANDRA MUNGEKAR: Sir, in view of the fact that 19.8 per cent of the total resources of the Eleventh Five Year Plan have been allocated to the education sector as a whole which is unprecedented in the history of India after independence the hon. Prime Minister described the Eleventh Five Year Plan as the Education Plan.

(Contd. by VKK/1F)

-YSR/VKK-SC/1f/11.25

DR. BHALCHANDRA MUNGEKAR (CONTD.): Sir, through you, I want to ask from the hon. Minister that as reported in one section of the Press, this is the fourth year of the Eleventh Five Year Plan and the speed of spending the resources earmarked for HRD is not keeping pace. As a result, some of the resources are likely to be under-utilised. Is it true that the resources are likely to be under-utilised? If so, what is the plan of the HRD Ministry to speed up the expenditure?

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I am thankful to the hon. Member to have asked this general question outside the main question that has been put. But, be that as it may, I am willing to answer it. Yes, Sir, there have been allocations which were given to us under the Eleventh Plan and yes, in terms of those allocations that were conceived, the actual Budgetary allocations are much less. And, that's due to several factors and not just one factor. One of the factors, for example, is, we announced 14 innovation universities. Plans for those innovation universities have not yet taken off for the simple reason that the concept of an innovation university

is not yet clear. We have to come to Parliament. We have set up a task force. So, in the absence of a plan or roadmap ahead, we can't spend that money. Same is the case with the Central Universities. Now, we had set up about 16 Central Universities. But, again, as far as those Central Universities are concerned, the architectural plans for building those universities are not yet complete. They are left to the Vice-Chancellors. Possessions have been taken in some cases; in some cases, not even boundary walls have been constructed. So, a lot of money, for example, Rs.89000 crore which was set apart for higher education sector has not been spent. But, as far as elementary education and Sarva Shiksha Abhiyan is concerned, because these are on-going schemes, the allocations that have been made for them have been spent more or less, over 90 per cent. So, where there are new schemes, they are yet to be spent. Therefore, for the allocations conceived in the Eleventh Plan, there is no Budgetary support because we are not ready on the ground. But, for the on-going schemes, in fact, the allocations have been spent wherever made.

SHRI M.P. ACHUTHAN: Sir, the norms of Sarva Shiksha Abhiyan, which is straight-jacket one, are applicable to all States irrespective of specific conditions prevailing in a State. In Kerala, we have got the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya scheme. Kerala is not getting any assistance under this scheme because the enrolment of girl child is very high in Kerala. In the same way, there is the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan for secondary schools. In Kerala, the problem is not of enrolment but of improving and enhancing the quality of

education. So, my question is: Will the hon. Minister be kind enough to take into consideration the specific conditions of States and change the norms accordingly?

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, it's very difficult to have a Centrally-sponsored scheme to suit specific conditions of different States. It's very, very difficult to do that. In fact, we must congratulate Kerala because Kerala has done very well in certain areas, especially education of girl child. Now, if you have done well and we all believe in inclusive development, then, we should actually be asking -- the hon. Member should be asking -- how much we are doing for the States which are not doing so well. As you know, once we have an inclusive agenda on which everybody has agreed, the question should not be that those States which are doing well should get more. The question should, in fact, be that please give more to the States which are not doing well because that is how we will take the nation forward.

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो एसएसए के फंड्स हैं, जैसे मंत्री जी ने कहा है कि North-East Region में 90 और 10 परसेंट का ratio है, क्या हिमाचल प्रदेश भी इसमें आता है क्योंकि उसे स्पेशल स्टेट माना गया था? दूसरा, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या एसएसए के फंड्स केवल हमारी सरकार के हैं या बाहर के देशों से भी इसमें फंड्स आते हैं?

श्री कपिल सिब्बल : सर, माननीय सदस्या ने दो सवाल पूछे हैं।

MR. CHAIRMAN: Please answer one.

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सर, दोनों का ही जवाब देने दीजिए।

श्री कपिल सिब्बल : सर, जहां तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, यह केबिनेट का decision है, सरकार का decision है कि नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का योगदान होगा, वह 90 प्रतिशत होगा और 10 परसेंट स्टेट का होगा। इसलिए ऐसी कोई नीति हिमाचल प्रदेश के बारे में हमने तय नहीं की है। जहां तक फॉरेन फंडिंग का सवाल है, सर्व शिक्षा अभियान में फॉरेन फंडिंग आती है, लेकिन वह लगभग 6 प्रतिशत है, बाकी हम अपना spend करते हैं। अगर हम 100 प्रतिशत spend करते हैं तो 6 प्रतिशत बाहर से आता है।

(समाप्त)

(1जी-जीएस पर आगे)

प्रश्न संख्या : 384

श्री नंद कुमार साय : माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय रेल मंत्री जी से जीपीएस के संबंध में पूछा था । यह परियोजना रेल सुरक्षा के लिए तकनीकी मिशन के तहत 2003 में स्वीकृत की गई थी और इसको 2008 तक पूरा करने का लक्ष्य था। किन्तु राजधानी या शताब्दी जैसी कुछ ट्रेन्स हैं, 40-50 ट्रेनों में ही यह सिस्टम लगाया जा सका है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2003 से 2010 तक सात वर्षों में इतनी कम ट्रेनों में इसको लगाया गया है, इसमें विलम्ब बहुत हुआ, उसके क्या कारण हैं ? क्या इसको और भी जगह लगाने के लिए कोई योजना रेल मंत्रालय के पास है ?

कुमारी ममता बनर्जी : सर, जीपीएस सिस्टम को यू.एस. में इस्तेमाल किया जाता है। हमारी जो रेलवे की एक्सपर्ट्स कमेटी Sam Pitroda की है, उन्होंने रिकमंडेशन दी, for SIMRAN and it is under consideration. We will do it as early as possible. From the safety point of view, हम लोगों ने जो pilot projects किया था, उसको हमने 42 लाख में किया था और अब यह complete हो गया है, यह successful हुआ है, and SIMRAN will be helpful in preventing the accidents even from the unmanned level crossings. So, we have decided to do it immediately and it will be completed within two years, Sir.

श्री सभापति : आप दूसरा प्रश्न पूछिए।

श्री नंद कुमार सायः माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि RDSO और IIT कानपुर SIMRAN के माध्यम से दो नये उपाय रेल पथों पर गैंगमेन और ट्रैकमेन की चेतावनी देने के हैं और दूसरे में चौकीदार रहित, सहित समपारों पर सड़क उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देने के लिए परीक्षण कर रहे हैं। क्या इन उपायों को लागू करने के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है ? यदि कोई समय-सीमा तय की गई है, तो उसको पूरा करने के लिए कब तक समय-सीमा है ?

कुमारी ममता बनर्जी : सर, मैंने बताया था कि दो साल में यह कम्पलीट हो जाएगा। जो क्वेश्चन SIMRAN के बारे में है, जो कानपुर IIT ने किया था, जिस पर रेलवे मिनिस्ट्री ने और HRD मिनिस्ट्री ने काम किया था, वह सक्सैसफुल हो गया है और वह दो साल में कम्पलीट हो जाएगा।

श्री सभापति : श्री मोहम्मद अमीन।

SHRI MOHAMMED AMIN: Sir, there are a large number of vacancies in the Railways. Connected with the question of railway safety, I want to know from the hon. Minister.....(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: The question is on GPS in railways.

श्री मोहम्मद अमीन : सर, रेलवे का ही तो मामला है।

श्री सभापति : नहीं, यह जीपीएस के संबंध में है।

श्री मोहम्मद अमीन: सर, इसमें एक्सीडेंट का सवाल है और एक्सीडेंट का रेलवे सेफ्टी के साथ कनेक्शन है।

MR. CHAIRMAN: No, no; railway safety is a much wider subject. Let us confine the supplementary to the main question, please.

श्री मोहम्मद अमीन : सर, हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि जो वेकेंसीज़ खाली हैं, इनके लिए पिछले छह महीने में कितने लोगों को लिया गया है and by what time these vacancies will be filled up.

KM. MAMATA BANERJEE: This is, absolutely, a different question, Sir. This is about equipment. The main question relates to GPS. But, for my friend, I want to say that already, we have started. We have started the work; the process is on. Because for ten years it was not done, the vacancy was there. This time, we

have started the process of filling the vacancies, and we are giving the special diet for SCs/STs, Physically Handicapped and the Minorities, and we are giving them the priority. As for OBCs and Disabled Persons, I have already covered. Then, for the Sports quota.....

MR. CHAIRMAN: Thank you.

KM. MAMATA BANERJEE: And the drive is on. We have done as per the new recruitment policy, and the process is on.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Shrimati Shobhana Bhartia.

SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA: Thank you, Sir. About the GP System, that would give real time information, there are certain concerns about the security, that this information can be used and misused by those who want to get the actual position and those who want to destroy and sabotage the railway tracks, and all that. In view of the fact that there have been certain suspected sabotage incidents and the consequent loss of life, what inbuilt checks and balances would the Ministry propose to keep so that this flow of information is not misused to actually damage the railway tracks?

KM. MAMATA BANERJEE: Sir, I am really obliged because Shobhana Bhartiaji has raised a very valid question. Yes, there is a concern, and we are examining it in detail; that is why some time more we are taking. But let me assure the House that we have to do it very quietly because the country matters; if there is a matter of security, it is a concern for each and every one. For that, we are trying to do

something. We will talk to the other Ministries, and also to the concerned Ministry, and we will take full precautions.

(Contd. by TMV/1H)

MKS-TMV-ASC/1H/11.35

KM. MAMATA BANERJEE (CONTD.): Nowadays, in the Railways, sabotage and terrorism are so much. They were not there earlier. The Railways is for the people. Earlier it was only protesting, अब तो सबोटेज के लिए भी हो गया, इसीलिए प्रॉब्लम भी हो गई है। She has raised a very valid point. We will get the details. We will examine the case very seriously. If there is any need for some foolproof security system, we will consider it and then we will do it.

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : सर, मैं मानीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि हम GPS सिस्टम ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और मंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र भी हैं। रेलवे की जो लाइनें हैं और उनके ऊपर जो फ्लाई ओवर बनते हैं, उनमें से काफी फ्लाई ओवर बनकर तैयार हैं। रेलवे लाइन के ऊपर का जो पोर्शन होता है, उसको रेलवे को तैयार करना होता है तथा यह उसकी जिम्मेवारी भी है, लेकिन वह अधूरा पड़ा हुआ है। ..(व्यवधान)..

श्री सभापति : यह GPS का सवाल है।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : सर, यह इन्फोर्मेशन ही है। GPS के माध्यम से रेल की इन्फोर्मेशन देनी है, तो हम ऑनरेबल मिनिस्टर के माध्यम से पुल की इन्फोर्मेशन ले लेंगे।

कुमारी ममता बनर्जी : सर, मैं कोई A to Z dictionary नहीं हूं। यदि माननीय सदस्य स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उत्तर दूंगी। स्टेट गवर्नमेंट फ्लाई ओवर के लिए 50 परसेंट देती है और रेलवे भी 50 परसेंट देती है। इस बारे में हमारा जो काम था, वह हमने पूरा कर दिया है। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक कम्पलेंट है, तो you can write to me, and I will give you the details.

(Ends)

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: Sir, my first supplementary is this. This is a 16-year project which is seeking to link very backward areas of Orissa. The hon. Minister has stated in her reply that it is a socially desirable project. An amount of Rs. 186 crores was allocated in the last 16 years. Out of that, an amount of Rs.95 crores was diverted and in the last three years an amount of Rs.58 crores was not spent. Is the Minister aware that the ongoing bridges could have been completed, a lot of work could have been done and the entire money could have been spent without going into the questions of forest clearance, handing over Government land free of encumbrances and failure of contracts? Why were they not completed?

KM. MAMATA BANERJEE: Sir, Khurda-Bolangir railway line is a very important railway line for Orissa. There are many other lines also. There are many pending projects worth more than Rs.1 lakh croes throughout the country. It is not that I am responsible for this. This is an ongoing process and the projects are pending. It is a fact that in our country there are socially desirable areas. People are staying in those backward areas. They need railway lines. They lack railways. Paucity of funds is also a problem. But Khurd-Bolangir line is very important. That is why we have given more than Rs.120 crores for this line. Previously it was given Rs.5 crores, Rs.10 crores, Rs.15 crores, like that. We try to do our best. Let us complete the first phase. I can assure the hon. Member that, whatever is the fund provided, it will be implemented.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: Sir, while thanking the Minister for continuing this as a socially desirable project, not transferring it to the RVNL, allocating Rs.120 crores this year and saying that this Rs.120 crores will be spent this year, I would like to know from the hon. Minister whether she is aware of the fact that as a result of the efforts of the State Government to persuade power plants and industries to come to the hinterland of the railway lines, two power plants have agreed to establish power plants in the hinterland.

(Contd. by 1J/RG)

RG/LP/11.40/1J

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA (contd.): Therefore, would the hon. Minister consider directing the Railway Board to fix a firm schedule for the completion of the line, at least, up to Daspalla, which is the second phase so that these power plants or industries do not shy away again from their decision?

KM. MAMATA BANERJEE: Our Department is encouraging private parties also to connect the port, the coal mines, and even the college areas, university areas and other important areas. We have already announced our RCH policy, where we say, we are willing to give them the economic share, if the people are interested. So, we are giving importance to this project. The first phase will be completed before March, 2011, and then, we will take up the second phase. I can assure the hon. Member that whatever we have said, we will do our best to complete the first phase, and, then, we will go in for the second phase. About RVNL, we are not in for it.

MR. CHAIRMAN: Shri Rudra Narayan Pany. You put your supplementary, without a speech.

श्री रुद्रनारायण पाणि : I will, specifically, put my supplementary. क्या माननीय मंत्री महोदया यह बताएंगी कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के विलंब का कारण यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण करके रेलवे को देने में कहीं कोई प्रॉब्लम रह गई है?

KM. MAMATA BANERJEE: It will be better if I give him a written reply.

SHRI BAISHNAB PARIDA: Sir, the hon. Minister, in her answer to this question, has said, "However, the project is progressing as per available resources." But, from the records of allotment which she has given, it is clear that in the previous years, that is, in 2008-09, Rs.32.33 crores were allotted, but only Rs.3.5 crores were spent; in 2009-10, Rs.28.07 crores were allotted, out of which only Rs.13.90 crores were spent." So, the resources are there. But why is the Ministry not spending this money on such an important line, which is considered as the lifeline of Orissa?

KM. MAMATA BANERJEE: Sir, when this project was announced, there was a decision that the State Government would acquire land. Now, there are some problems relating to land acquisition. That is why the Railways are not able to do it. But, this time, we have decided that we will pursue the matter with the State Government too. So, whatever is required to be done, we will take action accordingly.

SHRI RUDRA NAYARAN PANY: That was my supplementary. वे नहीं कर रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : पाणि जी, मैंने बोल दिया है।

(Ends)

श्री गंगा चरण : सभापति जी, मैंने माननीय मंत्री महोदय से जो ट्रेन दुर्घटनाओं का सवाल किया था, उस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि दुर्घटनाओं के बाद जो जांच होती है और जो अधिकारी दोषी पाए जाते हैं, उनमें से अभी तक कितने अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की गई है? दुर्घटना में जो विकलांग हुए हैं या मारे गए हैं, उनके आश्रितों में से कितने लोगों को रेलवे ने अभी तक नौकरी दी है? मैं यह भी जानना चाहता हूं..(व्यवधान)..

श्री सभापति : एक सवाल पूछिए।

श्री गंगा चरण : एक ही सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ है। यह इसी का पार्ट है।

श्री सभापति : इसका पार्ट नहीं है। आप दो सवाल पूछ रहे हैं, वन क्वेश्चन प्लीज।

(ks/1K पर क्रमागत)

AKG-KS/1K/11.45

SHRI E. AHAMMED: Sir, whenever the Railways find an officer at fault or guilty, action is taken. During the last five years, from 2005-06 to 2009-10, 985 defaulting railway employees have been awarded various penalties, ranging from removal, dismissal, minor punishment and their... (Interruptions)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल : सर, इन्होंने अधिकारियों के बारे में पूछा है, कर्मचारियों के बारे में नहीं।

श्री गंगा चरण : मान्यवर, मैंने DRM और GM level के अधिकारियों के बारे में पूछा है। मैं कर्मचारियों के बारे में नहीं जानना चाहता हूँ। जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनमें से कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है?

कुमारी ममता बनर्जी : सर, रेलवे में जब कोई accident होता है, तो इसके लिए एक सिस्टम होता है। जैसे अभी एक incident हुआ और उसे हम लोगों ने सीबीआई को दिया। एक तो हमने ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस की दुर्घटना को सीबीआई को दिया है और दूसरी को भी सीबीआई

को देने के लिए हमने request किया है। इसमें एक तो रेलवे की सेफ्टी कमेटी है, वह एक रिपोर्ट देती है, हम उस पर भी कार्रवाई करते हैं। साथ-साथ अगर कोई दूसरी बात आती है, तो हम लोग सीबीआई को भी देते हैं। जब तक रिपोर्ट नहीं मिलती है, तब तक हम लोगों का जो internally एक सिस्टम है, उसे हम अपने डिपार्टमेंट से करते हैं। रिपोर्ट आने के बाद, उसकी recommendation के मुताबिक हम लोग action लेते हैं। लेकिन हमें इसको और भी stringent करना है। Law would take its own course. यह सब हमको देखना है। इसको हमें ठीक तरीके से भी करना है। Law and order is not with the Railways. लेकिन जैसा केस होता है, उसके मुताबिक हम केस file करते हैं।

आपने DRM के बारे में बताया, ऐसे बहुत सारे DRMs पहले भी suspend हुए हैं, इधर-उधर उनका transfer हुआ और उनके खिलाफ action लिया गया। जैसे खन्ना कमेटी ने गाईसाल incident के बाद हम लोगों को 278 recommendations दिए थे, इनमें से हम लोगों ने 276 recommendations accept किए। ऐसे ही आपकी Standing Committee ने रेलवे के बारे में जो recommendations दिए, we have accepted all the recommendations. अगर आपके पास किसी के खिलाफ ऐसी कोई specific सूचना है, जिसमें किसी की कोई गलती है और उसके खिलाफ action नहीं लिया गया, you can send it to me; I would get it examined and give you details.

श्री सभापति : आप दूसरा सवाल पूछिए।

श्री गंगा चरण : सर, मेरा प्रश्न यह था कि आतंकवादियों द्वारा किए गए बम विस्फोटों तथा रेल पटरियों को उजाड़ने की वजह से कितनी रेल दुर्घटनाएँ हुईं। मैं माननीया मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो माओवादी हमले हुए हैं, उन माओवादी हमलों पर आपने बयान दिया कि इसमें कोई राजनीतिक साजिश है, तो मैं आज जानना चाहता हूँ, सदन जानना चाहता है कि आपने जाँच करा ली होगी, आज आप उस साजिश का भंडाफोड़ सदन के सामने करें कि

यह किसकी साजिश थी? आजकल आपकी ट्रेनों पर माओवादी हमले हो रहे हैं, जबकि आप उनके ऊपर बड़ी कृपा और सहानुभूति रखती हैं, तो इस साजिश का ... (व्यवधान) ...

MR. CHAIRMAN: One question, please.

कुमारी ममता बनर्जी : यह बहुत बड़ा क्वैश्चन है, sensitive question भी है। Investigation अभी चल रही है। Investigation खत्म होने के बाद मैं पूरी बात हाउस को बता पाऊँगी, लेकिन यह बात ठीक है कि maoist attacks, bandhs, अवरोध and sabotage, ये सब मिला कर 217 disruptions हुई हैं। हमारी रेलवे का एक हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसकी वजह से 416 पैसेंजर ट्रेनें cancel हुई हैं, हमारी 70 मेल ट्रेनों की punctuality affect हुई है। Sir, can you imagine, *Bandh* had been called on 75 occasions. तो ट्रेन कैसे चलेगी? अगर यह बंगाल में रुकेगी, तो बिहार में भी रुकेगी, अगर आंध्र प्रदेश में रुकेगी, तो automatically चेन्नई में रुकेगी और महाराष्ट्र में रुकेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? हम अपील करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए।

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, the CAG Report, which comes in the wake of a series of train accidents, has revealed not only the under-utilization of funds allocated for safety purposes, but also alleged that the Railways could still not fill up vacancies on the safety side. The audit carried out by CAG on the performance of the Railways in the first phase of Corporate Safety Plan between 2003 and 2008 shows that more than 50 per cent of the Rs.4600 crores allocated for safety works has remained unutilized. The Report found huge gaps between the Railways' promise and execution of safety-related projects, including upgradation of training centres to step up competence.

(Contd. at 1l/kgg)

Q. No.386 (Contd.)

SHRI TIRUCHI SIVA (contd.): Additionally, there are 86,108 vacancies in safety category posts, posing risk operations. Sir, 20 per cent of wagons run on railways was overloaded and those wagons were allowed to run even after detection of the overload endangering track conditions. Sir, I would like to know the response of the Minister towards this report; I would also like to know when would the over 86,000 vacancies in the safety category be filled up.

KM. MAMATA BANERJEE: Sir, the corporate safety fund was about Rs.17,000 crores and it was given to the Department in 2003. After that, Rs.31,000 crores was the allotted money for the corporate safety fund; out of that, more than Rs.29,000 crores have already been spent. Only Rs.2,000 crores are left out; the corporate safety fund would be fully spent within 2013. We are left with only Rs.2,000 crores and this money would be spent within 2013. We have almost spent all the money. If you see the report of 2007-08, you would find that the situation has changed.

About vacancies, I have already said. The House would be happy to know about filling up of safety-related vacancies. There are some categories like gangmen. Now, we have decided; in consultation with the union people, the safety-related people, there is a safety-related employment guarantee scheme; and we are doing it where gangmen and other safety-related employees, if they offer their voluntary retirement in favour of their son/daughter, then the Railways would give them the priority. In the Railways we give provision for the employees

son/daughter so that the gangmen who have put in 20 years of permanent service, if they are ready, if they apply saying that they are unable to do the gangman's work and that their son/daughter may be allowed to do the job, then we allow this. So, this scheme is already allowed. About other safety-related vacancies, they are in the process and we are doing everything to fill them up.

SHRI BALBIR PUNJ: Mr. Chairman, Sir, we all know about the Gyaneshwari Train accident which left about 160 people dead and many people injured. My question, through you, Sir, to the hon. Minister is: What are the findings of the cause of the accident? Who are these persons? Is it not a fact that many of the people who are accused of causing this accident were found to be attending a rally addressed by the hon. Railway Minister in Lalgarh?

KM. MAMATA BANERJEE: Sir, I have said in the House that let me deal with this question impartially and not politically though you have connected it politically. The question is related politically.

SHRI BALBIR PUNJ: It is a crime... (Interruptions) People were attending a rally, Madam. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please, Mr. Punj, you have asked your question, listen to the answer. (Interruptions)

KM. MAMATA BANERJEE: You have asked your question, please let me reply, it is my prerogative now. Sir, about the first part of the question on the Gyaneshwari Express train, yes, *prima facie,* the accident is a sabotage bomb-blast; we have handed over this case to the CBI; they are investigating it. After they submit a

report, you can get the details. Secondly, about the rally, it is your political question; it is politically fabricated. Nothing, not even a single thing is related to my rally.

SHRI RAASHID ALVI: The Railways had appointed a commission to find out the reasons of the accidents. According to the report of the commission, more than 40 per cent accidents have taken place because of human error. It is because of the human error. About 25 per cent accidents are taking place because of unmanned crossings. It means, these accidents can be avoided. अगर ये एक्सिडेंट्स इंसानी गलतियों की वजह से हुए तो अवॉयड किये जा सकते थे। अगर अनमैन्ड क्रॉसिंग की वजह से ये एक्सिडेंट्स हुए तो अवॉयड किये जा सकते थे। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि आपने उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जो इसके लिए जिम्मेदार थे?

(1एम/टीडीबी पर क्रमशः)

TDB-MCM/1M/11.55

SHRI RAASHID ALVI (CONTD.): What precautions are you taking in future that no accident takes place because of human error?

KM. MAMATA BANERJEE: Sir, there are so many projects on various things and unmanned level crossing is also a part of it. At that time, 25,000 unmanned railway crossings were there. But, during these years, it is now only 16,000. It is because funds are being spent on it from the Safety Fund. When, I again became the Railway Minister, I found that there were about 16,000 unmanned railway crossings. You will be happy to know that we have already taken up 4,000 unmanned railway crossings. So, right now, there are only 12,000 unmanned railway crossings. According to our Vision Document, these 12,000 unmanned railway crossings would also be completed in three-four years. And, we will complete the signaling of these unmanned level crossings within two years.

(Ends)

श्री महेन्द्र मोहन : धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय मंत्री जी के द्वारा जो उत्तर दिया गया है उसमें लिखा है कि डकैती की कोई भी घटना नहीं हुई है और उनकी जानकारी में भी नहीं है। अभी हाल ही में 6 अगस्त को कलकत्ता-दिल्ली एक्सप्रेस-3111 अप में बिहार में डकैती पड़ी, 21 आदमी घायल हुए जिसमें जी0आर0पी0एफ0 कास्टाफ भी था। 8 अगस्त को हावड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस-3049 अप में जेसीडी और झाझा रूट पर डकैती पड़ी, जिसमें 3 पैसेंजर्स को मारा व लूटा गया और डेढ़ लाख रुपए की लूट हुई। मेरी समझ में नहीं आता कि आए दिन रेलगाड़ियों में डकैतियां पड़ रही हैं, लूटमार हो रही है और उसके बाद अगर यह उत्तर दिया जाता है कि ऐसी कोई घटनाएं नहीं हो रही हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि यात्रियों को लूटने, ठगने, जहर खुरानी, स्नेचिंग तथा अन्य जो भी घटनाएं होती हैं उनकी एफ0आई0आर0 क्यों नहीं दर्ज होती हैं और अगर एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की जा रही हैं तो इसके क्या कारण हैं और सरकार किस प्रकार से जो रेलवे पुलिस फोर्स है उसको यह अधिकार देने जा रही है कि इन डकैतियों की, इन लूटमार की समाप्ति हो? क्योंकि, आजकल यह पाया जा रहा है कि रेलवे में चलना बहुत ही जोखिम भरा होता चला जा रहा है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इसमें वह क्या सुधार करने जा रही है और कानून में क्या परिवर्तन ला रही है?

कुमारी ममता बनर्जी : सर, माननीय सदस्य का क्वेश्चन था कि क्या पुलिस यूनिफार्म पहनकर डकैती की जा रही है या नहीं? तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई इंफार्मेशन हमारे पास नहीं है। अगर जी0आर0पी0एफ0 ने कुछ किया हो तो स्टेट पुलिस है। जी0आर0पी0एफ0 जो रेलवे में पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स है, RPF is different from the GRPF. लेकिन आपने जी0आर0पी0एफ0 का नाम लिया है, जी0आर0पी0एफ0 तो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, लेकिन The Railways give 50% salary to them. The State Government also gives 50%. So, they take care of it. हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि पुलिस

ड्रेस पहनकर कोई डकैती हुई है। क्योंकि यह सेंसेटिव सब्जेक्ट भी है अगर पुलिस की ड्रेस पहनकर कोई चीज होती है तो यह अनकांस्टीट्यूशनल है। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो हमको दीजिए।

श्री महेन्द्र मोहन : सभापति जी, जो जानकारी मिली है, जो अखबारों से सूचनाएं मिलती हैं उसमें तो यही जानकारी है कि पुलिस वर्दी वगैरह में लोग जाते हैं। जो माननीय मंत्री जी कह रही हैं, वही मैं भी कह रहा हूं कि उसकी एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की जाती है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में और भी कहा है कि यात्रियों से जुड़ी वारदातों में अधिक कारगर कार्रवाई करने में रेल सुरक्षा बल को समर्थ बनाने के लिए आर0पी0एफ0 एक्ट में संशोधन करने की जांच की जा रही है। यह जानकर प्रसन्नता है कि जांच की जा रही है। मैं जानना चाहूंगा कि यह प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, आर0पी0एफ0 को कब यह अधिकारी मिलेंगे और इतनी जो घटनाएं डकैती आदि की हुई हैं इसमें जो कोआर्डिनेशन स्टेट पुलिस के साथ होता है, उसमें क्या घटनाएं हुई हैं और स्टेट पुलिस से क्या कोई रिपोर्ट मिली हैं कि उन घटनाओं में क्या प्रगति हुई है, कोई अपराधी पकड़े गए हैं अथवा नहीं?

कुमारी ममता बनर्जी : हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंटीन्यूअस परस्यू करते हैं कि लॉ एंड आर्डर को प्रोटक्शन दीजिए, Law and order is a State subject. आप प्रोटक्शन दीजिए। हम इसको परस्यू करते हैं। लेकिन आपने बोला है कि पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? हम स्टेट गवर्नमेंट नहीं हैं, हम कैसे कार्रवाई करेंगे, स्टेट पुलिस के खिलाफ कार्रवाई तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, हम कैसे कर सकते हैं। उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करने की आथॉरिटी रेल की नहीं है। दूसरी बात, आर0पी0एफ0 के बारे में आपने जो पूछा है,.....(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : लगातार बिहार में भी डकैतियां हो रही हैं.....(व्यवधान)

श्री सभापति : बैठ जाइए, जवाब तो सुन लीजिए।.....(व्यवधान) बैठ जाइए।

KM. MAMATA BANERJEE: If Parliament allows the RPF to do it (Interruptions) because it is a law and order problem, then, we will be happy to do it. (Interruptions)

श्री राम कृपाल यादव : मैडम को तो पता ही होगा कि वहां पर कितनी घटनाएं हुई हैं.....(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

(Ends)

NB/KLS/1N/12.00

PAPERS LAID ON THE TABLE

1. **SHRI NAMO NARAIN MEENA:** Sir, I lay on the Table, under sub-section (1) of Section 7 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Statement on Quarterly Review of the trends in receipts and expenditure in relation to the Budget for the third quarter of the financial year 2009-10.

(ii) Statement on Quarterly Review of the trends in receipts and expenditure in relation to the Budget at the end of the financial year 2009-10.

(iii) Statement on Quarterly Review of the trends in receipts and expenditure in relation to the Budget at the end of the first Quarter of the financial year 2010-11.

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, मैंने एक विशेष उल्लेख का नोटिस दिया है ... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : अभी आप बैठिए, पहले पेपर्स lay करने दीजिए ... (व्यवधान)

SHRI NARESH GUJRAL: They are being forced to leave the Valley. ...(Interruptions).. This concerns the security of the whole nation. ...(Interruptions).. A strong message should go from this House. ...(Interruptions)...

श्री अविनाश राय खन्ना : यह बहुत सीरियस मामला है ... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : पहले पेपर्स lay करने दीजिए ... (व्यवधान) आपको नोटिस देना पड़ेगा ... (व्यवधान) आपने नोटिस क्यों नहीं दिया ... (व्यवधान) Have you given notice? ...(Interruptions).. Have you given notice? ...(Interruptions)... आपने नोटिस क्यों नहीं दिया ... (व्यवधान) आप सुबह नोटिस दे सकते थे ... (व्यवधान) What prevented you from giving notice? ...(Interruptions)... Ravi Shankar Prasadji, I can understand. ...(Interruptions).. I agree but what prevented you from giving notice? ...(Interruptions)..

श्री एस.एस. अहलुवालिया : सरकार बयान दे कि जो अल्पसंख्यक हैं ... (व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What prevented you from giving notice? ...(Interruptions).. Mr. Ahluwalia, please sit down. ...(Interruptions).. We have admitted it for Zero Hour in the name of Shri Rajiv Pratap Rudy under the heading 'threat to Sikhs in the Kashmir Valley'. It is coming during Zero Hour. ...(Interruptions)..

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, the point is very simple. We don't want to have a discussion on this, we want an assurance from the Government...(Interruptions).. On Independence Day, the Prime Minister declared from the ramparts of the Red Fort that Kashmir is part and parcel of India. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have admitted it. ...(Interruptions)..

SHRI S.S. AHLUWALIA: We want a response from the Government today. ...(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I would like the Government ...(Interruptions)..

श्री बलबीर पुंज : कश्मीर घाटी में पहले 5 लाख पंडितों को निकाला गया, अब सिखों को निकाला जा रहा है ... (व्यवधान)

SHRI S.S. AHLUWALIA: Where is the Minister? ...(Interruptions)...

श्री बलबीर पुंज : उपसभापति जी, आप तो हमारी पीड़ा समझिए ... (व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Government may examine and get back to the House. ...(Interruptions)...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, are you informing the Government? ...(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have said that on this issue if they want to react, they may react. ...(Interruptions)..

SHRI BALBIR PUNJ: People are being asked to get converted to Islam. ...(Interruptions)..

श्री उपसभापति : गुज़राल साहब, आप क्या कर रहे हैं ... (व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि रूडी साहब का ज़ीरो ऑवर मैंशन admitted है ... (व्यवधान) आप क्या चाहते हैं बताइए ... (व्यवधान) मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है ... (व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि रूडी साहब का ज़ीरो ऑवर मैंशन admitted है, उस वक्त आप यह बात कह सकते हैं ... (व्यवधान)

SHRI S.S. AHLUWALIA: You should direct the Government that they come back to the House and give a statement. ...(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already said. You have not listened. I have said it. ...(Interruptions)..

श्री विनय कटियार : उपसभापति जी, आपकी बात सही है कि रूडी साहब का ज़ीरो ऑवर मैंशन है, लेकिन कभी-कभी देश में ऐसे विषय होते हैं ... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : आप लोग बोलते जा रहे हैं, लेकिन मुझे बोलने का मौका ही नहीं देते ... (व्यवधान) आप डिस्कस कीजिए ... (व्यवधान) Nothing will go on record .....

श्री विनय कटियार : *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The External Affairs Minister wants to react.

———————————————————————

***Not recorded.**

(Followed by 1o/SSS)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister of External Affairs wants to react. आप बैठ जाइए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Government wants to react. आपने कहा कि गवर्नमेंट का reaction चाहिए, When Government wants to react, you say, 'What can he say?' The Government wants to react. (Interruptions) Please, (Interruptions) Mr. Rudy, your Zero Hour is coming. In the meantime, they have raised this, what can I do?

SHRI JESUDASU SEELAM: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Seelam, you please go back to your seat. Please maintain silence. This is a very serious subject.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S. M. KRISHNA): Sir, it is a fact that Government of India has always taken the position that Jammu and Kashmir is part and parcel of the Republic of India. There is no ambiguity about it and we are not open to any talks about this position. So, everyone...(Interruptions)...

श्री अनिल माधव दवे: *

SHRI S. M. KRISHNA: Well, the protection of minorities is the concern of the Government and India will strive every now and then to see that minorities, wherever they are, will be protected. (Interruptions)

————————————————————————

***Not recorded.**

श्री उपसभापतिः इसको जीरो आवर में ले रहे हैं ..(व्यवधान)... आप क्या चाहते हैं? ...(व्यवधान)... Papers laid on the Table. Shri Dinsha Patel.

2. **SHRI DINSHA J. PATEL**: Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) (a) Tenth Annual Report and Accounts of the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE), Mumbai, for the year 2009-10, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(ii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises) and the National Small Industries Corporation Limited (NSIC), for the year 2010-11.

3. **SHRI SRIKANT JENA**: Sir, I to lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(a) Eighteenth Annual Report and Accounts of the Institute of Pesticide Formulation Technology (IPFT), Gurgaon, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

4. **SHRI E. AHAMMED**: Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(a) Annual Report and Accounts of the Rail Land Development Authority (RLDA), New Delhi, for the year 2006-07, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Annual Report and Accounts of the Rail Land Development Authority (RLDA), New Delhi, for the year 2007-08, together with the Auditor's

Report on the Accounts.

(c) Review by Government on the working of the above Authority.

(d) Statements giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) and (b) above.

5. **SHRIMATI D. PURANDESWARI:** Sir, I lay on the Table—

I.(1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (3) of Section 31 of the University of Allahabad Act, 2005:—

(a) Annual Report of the University of Allahabad, Allahabad, for the year 2008-09.

(b) Review by Government on the working of the above University.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

II.(1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of Section 19 of the Jawaharlal Nehru University Act, 1966:—

(a) Thirty-ninth Annual Report of the Jawaharlal Nehru University (JNU), New Delhi, for the year 2008-09.

(b) Review by Government on the working of the above University.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

III. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) (a) Annual Accounts of the Visva-Bharati, Santiniketan, for the year 2008-09, and the Audit Report thereon, under sub-section (4) of Section 36 of the Visva Bharati (Amendment) Act, 1984.

(b) Statement giving reasons for the delay in laying the paper mentioned at (i) (a) above.

(ii) (a) Annual Report of the Atal Bihari Vajpayee-Indian Institute of Information

Technology and Management (ABV-IIIT&M), Gwalior, for the year 2008-09.

(b) Annual Accounts of the Atal Bihari Vajpayee-Indian Institute of Information Technology and Management (ABV-IIIT&M), Gwalior, for the year 2008-09 and the Audit Report thereon.

(c) Statement by Government accepting the above Report.

(d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (ii) (a) and (b) above.

(iii) (a) Annual Report of the Indian Institute of Information Technology (IIIT), Allahabad, for the year 2008-09.

(b) Annual Accounts of the Indian Institute of Information Technology (IIIT), Allahabad, for the year 2008-09 and the Audit Report thereon.

(c) Statement by Government accepting the above Report.

(d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (iii) (a) and (b) above.

(iv) (a) Annual Report and Accounts of the Bharat Shiksha Kosh (BSK), for the year 2006-07, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (iv) (a) above.

(v) (a) Annual Report and Accounts of the Bharat Shiksha Kosh (BSK), for the year 2007-08, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (v) (a) above.

(vi) (a) Annual Report and Accounts of the Bharat Shiksha Kosh (BSK), for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (vi) (a) above.

(vii) (a) Annual Report and Accounts of the Bihar Mahila Samakhya Society, Patna, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the

Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (vii) (a) above.

(viii) (a) Annual Report and Accounts of the Kerala Mahila Samakhya Society, Trivandrum, for the year 2007-08, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (viii) (a) above.

(ix) (a) Annual Report and Accounts of the Central Institute of Classical Tamil (CICT), Chennai, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (ix) (a) above.

(x) (a) Annual Report of the Indian School of Mines (ISM), Dhanbad, for the year 2008-09.

(b) Annual Accounts of the Indian School of Mines (ISM), Dhanbad, for the year 2008-09 and the Audit Report thereon.

(c) Review by Government on the working of the above School.

(d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (x) (a) and (b) above.

(xi) (a) Annual Report and Accounts of the Lakshadweep Sarva Shiksha Abhiyan State Mission Authority, Ladshadweep, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (xi) (a) and above.

(xii) (a) Annual Report and Accounts of the Sarva Shiksha Abhiyan, Union Territory Mission Authority, Dadra and Nagar Haveli, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (xii) (a) above.

(xiii) (a) Annual Report and Accounts of the Sarva Shiksha Abhiyan, Union Territory Mission Authority, Puducherry, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (xiii) (a) above.

(xiv) (a) Annual Report and Accounts of the Rajiv Gandhi Indian Institute of Management (RGIIM), Shillong, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (xiv) (a) above.

(xv) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Advanced Study (IIAS), Shimla, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (xv) (a) above.

(xvi) (a) Annual Report and Accounts of the School of Planning and Architecture (SPA), New Delhi, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above School.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at

(xvi) (a) above.

(xvii) (a) Annual Report and Accounts of the UEE Mission Delhi, Delhi, for the year 2005-06, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (xvii) (a) above.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already said that Government will come back to the House with a reply. (Interruptions)

6. **PROF. K.V. THOMAS:** Sir, I lay on the Table—

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, (Department of Food and Public Distribution) Notification No. EP. 1 (1)/2010, dated the 20th July, 2010, publishing the Food Corporation of India (Staff) (3rd Amendment) Regulations, 2010, under sub- section (5) of Section 45 of the Food Corporations Act, 1964.

II. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Agriculture, (Department of Agriculture and Cooperation) Notification No. G.S.R. 650 (E), dated the 2nd August, 2010, amending Notification No. G.S.R. 129 dated the 17th April, 2004, to insert certain entries in the original Notification, under sub-section (2) of Section 3 of the Agriculture Produce (Grading and Marking) Act, 1937.

III.(1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956 —

(a) Thirty-seventh Annual Report and Accounts of the Kerala Agro Industries Corporation Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2004-05, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

II. **SHRI NAMO NARAIN MEENA**: Sir, I lay on the Table, under clause (2) of article 151 of the Constitution, a copy each (in English and Hindi) of the following Reports:—

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended March, 2010: Report No.15 of 2010-11: Union Government (Defence Services) - Procurement of Stores and Machinery in Ordnance Factories; and

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended March, 2009: Report No.16 of 2010-11: Union Government (Defence Services) - Air Force and Navy.

(Ends)

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

THE APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 4 BILL, 2010

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Lok Sabha, I am directed to enclose the Appropriation (Railways) No. 4 Bill, 2010, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 19th August, 2010.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

(Ends)

REPORT OF THE DEPARTMENT RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

DR. JANARDHAN WAGHMARE (MAHARASHTRA): Sir, I present the Two Hundred and Twenty-fifth Report (in English and Hindi) of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development on 'The Educational Tribunals Bill, 2010'.

(Ends)

REPORT OF THE DEPARTMENT RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (GOA): Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Eighth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution (2009-10) on 'Food Subsidy and its Utilisation' of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution).

(Ends)

REPORTS OF THE DEPARTMENT RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON LABOUR

SHRI G.N. RATANPURI (JAMMU & KASHMIR): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Labour:—

(i) Thirteenth Report on Action taken by the Government on the recommendations/observations contained in the Fortieth Report of the Committee (Fourteenth Lok Sabha) on the 'Problems Being Faced by Workers Due To Sickness of HMT Units'; and

(ii) Fourteenth Report on Action taken by the Government on the recommendations/observations contained in the tenth Report (Fifteenth

Lok Sabha) of the Committee on the 'Demands for Grants of the Ministry of Labour and Employment for the year 2010-11'.

(Ends)

(Contd. by USY/1P)

-SSS-USY/1P/12.10

ACTION TAKEN STATEMENTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON LABOUR

SHRI G.N. RATANPURI (JAMMU & KASHMIR): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following Statements of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Labour:—

(i) Statement showing further action taken by the Government on the recommendations/observations contained in Seventh Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Committee (2009-10) on the recommendations contained in Thirty-fifth Report (Fourteenth Lok Sabha) on 'General conditions of weavers in the country-a case study of Sircilla concentration zone of weavers' of the Ministry of Textiles;

(ii) Statement showing further action taken by the Government on the recommendations/observations contained in Eighth Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Committee (2009-10) on the recommendations contained in Thirty-ninth Report (Fourteenth Lok Sabha) on 'Employees' Provident Fund Organisation-Employees' Pension Scheme, 1995' of the Ministry of Labour & Employment;

(iii) Statement showing further action taken by the Government on the recommendations/observations contained in Ninth Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Committee (2009-10) on the recommendations contained in Third Report (Fifteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants' for the year 2009-10 of the Ministry of Labour and Employment; and

(iv) Statement showing further action taken by the Government on the recommendations/observations contained in Twelfth Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Committee (2009-10) on the recommendations contained in Fourth Report (Fifteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants' for the year 2009-10 of the Ministry of Textiles.

(Ends)

...(Interruptions)...

REPORT OF THE DEPARTMENT RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES

SHRI KUMAR DEEPAK DAS (WEST BENGAL): Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Fifth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Water Resources on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the First Report (Fifteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2009-10) of the Ministry of Water Resources.

(Ends)

...(Interruptions)...

MOTION FOR ELECTION TO THE NATIONAL BOARD FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SHRI DINSHA J. PATEL) : Sir, I move the following Motion:—

"That in pursuance of clause (d) of sub-section (3) of Section 3 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (No.27 of 2006), read with sub-rule (ii) of Rule 6 of the National Board for Micro,

Small and Medium Enterprises Rules, 2006, this House do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, one Member from amongst the Members of the House, to be a member of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises in the vacancy caused due to the retirement of Shri Oscar Fernandes from the membership of the Rajya Sabha on the 30th June, 2010."

The question was put and the motion was adopted.

(Ends)

...(Interruptions)...

STATEMENT RE.: STATUS OF IMPLEMENTATION OF OBSERVATIONS/ RECOMMENDATIONS CONTAINED IN FOURTH REPORT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE AND IN SECOND AND FOURTH REPORTS OF DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (PROF. K.V. THOMAS): Sir, on behalf of Shri Sharad Pawar, I make the following statements regarding :—

(i) Status of implementation of observations/recommendations contained in the Fourth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Agriculture.

(ii) Status of implementation of recommendations contained in the Second and Fourth Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution.

(Ends)

...(Interruptions)...

STATEMENT RE.: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS CONTAINED IN FIRST REPORT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS ON DEMANDS FOR GRANTS (2009-10) OF THE DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS; FOURTH REPORT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS ON DEMANDS FOR GRANTS (2009-10) OF THE DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS; AND FIFTH REPORT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS ON 'PRODUCTION AND AVAILABILITY OF MEDICINES TO DEAL WITH SWINE FLU'

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SRIKANT JENA): Sir, I make the following statements regarding:—

(i) Status of implementation of recommendations contained in the First Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2009-10) of the Department of Pharmaceuticals.

(ii) Status of implementation of recommendations contained in the Fourth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2009-10) of the Department of Chemicals and Petrochemicals.

(iii) Status of implementation of recommendations contained in the Fifth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on 'Production and availability of medicines to deal with Swine Flu'. (Ends)

...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned till 12.30 p.m.

———

The House then adjourned at thirteen minutes past twelve of the clock.

PK/1Q/12.30

**The House reassembled at thirty minutes past twelve of the clock,
THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE)
in the Chair.**

.....

THE VICE-CHAIRMAN : The House is adjourned for another fifteen minutes.

.....

**The House then adjourned at thirty minutes
past twelve of the clock.**

PB/1r/12.45

**The House reassembled at forty-five minutes past twelve of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.**

STATEMENT RE. ASSURANCE TO GIVE FULL PROTECTION TO THE SIKH COMMUNITY IN JAMMU & KASHMIR

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, I am told that the hon. Members expressed concern about some threats received by the members of the Sikh community in Jammu & Kashmir. I am aware of it. There is one incident where the rights of one person belonging to the Sikh community were violated. But, then the Chief Minister and I discussed the matter, and the Chief Minister has assured that the rights of the Sikh community will be fully protected and no harm will come to them. We are aware of these so-called threats but there is nothing to fear, nothing to worry. The Chief Minister has assured me that the Sikh community will be given full protection and nobody will be allowed to harm the Sikh community. I think, yesterday or a day before, I received a letter, if I

recall, from a delegation of the Sikh community to meet me; I have said, 'yes; I will be happy to meet them.' I think they will come in the next few days. But let the House be assured that both the Central Government and the State Government will work together to give full protection to the Sikh community in Jammu & Kashmir.

(Ends)

SHRI BALBIR PUNJ: Mr. Deputy Chairman, Sir, one minute, please.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no. Please.

SHRI BALBIR PUNJ: I want to make only one observation. Sir, the hon. Minister's assurance looks very correct on the face of it. But going by the history, we have seen how five lakh Hindus were thrown out of the valley in spite of repeated assurances. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no. Zero Hour Mentions. Dr. Bhalachandra Mungekar. ...(Interruptions)...

SHRI BALBIR PUNJ: Sir, we need an assurance that history will not be allowed to repeat. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is not the subject before us. ...(Interruptions)...

SHRI BALBIR PUNJ: But, it is very relevant, Sir. Five Lakh Hindus were thrown out of the valley in spite of all the assurances from the Central Government. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have called the Member for Zero Hour Mention. ...(Interruptions)...

SHRI BALBIR PUNJ: Assurances stand. But Kashmiri Pundits and Hindus continue to be refugees in their own country. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no notice on this subject. ...(Interruptions)...

DR. CHANDAN MITRA: Sir, can the Minister assure that nobody will be forced to leave the valley? ...(Interruptions)...

SHRI BALBIR PUNJ: Sir, this thing will not be allowed. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has said about it. ...(Interruptions)...

SHRI BALBIR PUNJ: No; Sir. Please understand the sensitivity. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I understand it. But you also know that this House discusses issues on notices. ...(Interruptions)...

SHRI BALBIR PUNJ: Mr. Deputy Chairman, Sir, this is a question of ... ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You give a notice and have a fulfledged discussion on this. ...(Interruptions)...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, I would like to remind the Government that when Bill Clinton came to India in 2000, at that time, in Chittisinghpura, 36 Sikhs were killed. At that time, I went there. I assured them. They wanted to migrate from Kashmir. In Valley, the Indian civilian face is the Sikh face. Otherwise, either it is paramilitary or Army. The Indian civilian face is the Sikh face and they want to finish that also by converting them forcibly to Islam. ...(Interruptions)... How can we allow and how are you going to do this? That is my point. And, then, after Chittisinghpura, Mehjoor Nagar came. ...(Interruptions)... Then again a delegation went there and assured them; all the leaders went there and assured

that 'on our dead body, you will leave.' This is the same situation. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ahluwalia, you know on what basis, this House works. ...(Interruptions)...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Maulana Faruki came; everybody came there; all the leaders came, and assured them. ...(Interruptions)...

DR. CHANDAN MITRA: Sir, just allow me to say something.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Chandan Mitra, I can understand the sentiments. ...(Interruptions)...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, my point is, whether the Government will assure this House on it.

SHRI BALBIR PUNJ: Mr. Deputy Chairman, Sir, the rules of this House cannot be more sacred than the unity and integrity of this country which is being questioned today.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Is anybody questioning that?

(Followed by 1s/SKC)

1s/12.50/skc-gs

SHRI BALBIR PUNJ: It is being questioned, Sir. (Interruptions) It is being questioned. (Interruptions)

SHRI S. S. AHLUWALIA: Their heads were shaved; their beards were cut. And, now you are saying that they will be forced to undergo *sunnat* and they will be forced to recite *kalma*! Why? Why is this happening? Who is going to protect them?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ahluwalia, you are a senior Member. (Interruptions) You know that you have to give notice. (Interruptions) Who is preventing you from discussing all these matters? (Interruptions)

SHRI S. S. AHLUWALIA: You cannot protect them by providing security guards. You have to create that atmosphere. We want congenial atmosphere there. You cannot provide security to each and every Sikh. Sikhs are living in villages. They are cultivators. They are farmers. They are running orchards. You have to create a congenial atmosphere. That congenial atmosphere is not there. Then, how are you going to protect them? (Interruptions)

SHRI BALBIR PUNJ: Mr. Deputy Chairman, Sir, I have one request to make. The hon. Home Minister is here. Why don't you ask him to...(Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Punj, I have no matter here to ask the Government to reply. There is no subject. There is no notice. How can I do it? If every time a Member gets up and asks the Chair to make the Government respond...(Interruptions)

SHRI S. S. AHLUWALIA: Sir, the Home Minister is talking about protection. I am saying that you must create an atmosphere. How will you do that? Not by providing guns or bodyguards!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. The Home Minister has come here for a specific purpose because, in the morning, all of you raised this issue and you had wanted the Home Minister to react; I had said that the Government should take note of it and react. The hon. Home Minister has come and reacted. Now, you are raising another subject. (Interruptions)

SHRI BALBIR PUNJ: We are not raising a different subject. We are raising the same very issue. (Interruptions)

SHRI S. S. AHLUWALIA: Their assurance has failed. (Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You know, if the assurance has failed, what to do.

SHRI S. S. AHLUWALIA: 'What to do' means what? Whose responsibility is that? This is the responsibility of the Government.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If a senior hon. Member says this, I have to just...(Interruptions)

श्री विनय कटियार : उपसभापति जी। ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : आप भी उठकर खड़े हो गए। ..(व्यवधान)..

SHRI NARESH GUJRAL: Sir, hon. Members want to seek clarification...(Interruptions)

श्री विनय कटियार : उपसभापति जी, पांच हजार हिन्दुओं को वहां से निकाला जा चुका है। ..(व्यवधान).. हमें आपका संरक्षण चाहिए। ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : आप नोटिस दीजिए। ..(व्यवधान).. Mr. Rudy, your own people are standing; what can I do?

श्री विनय कटियार : उपसभापति जी, हमें आपका संरक्षण चाहिए। पूरी कश्मीर घाटी के अंदर ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : अब क्या आप लगातार बोलते रहेंगे ? ..(व्यवधान).. क्या आपका बोलने का राइट है ? क्या दूसरे मेम्बर का राइट नहीं है ? ..(व्यवधान).. आप बैठ जाइए। ..(व्यवधान).. Nothing goes on record. (Interruptions) Nothing goes on record.

श्री विनय कटियार : *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You cannot go on talking. I cannot allow...(Interruptions) Nothing goes on record.

श्री विनय कटियार : *

श्री उपसभापति : यह क्या बात है ? ..(व्यवधान).. यह रिकार्ड में नहीं जा रहा है। आप क्यों बोल रहे हैं ?..(व्यवधान).. Dr. Bhalchandra Mungekar.

SHRI BALBIR PUNJ: *

श्री उपसभापति : यह रिकार्ड में नहीं जा रहा है। ..(व्यवधान)..

SHRI NARESH GUJRAL: Sir, I have only one request to make. I want to seek some clarification from the hon. Minister if you allow me just one minute.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION OF THE CHAIR

RE. IMPLEMENTATION OF THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT, WITH SPECIAL REFERENCE TO THE KHAIRLANJI INCIDENT OF MAHARASHTRA

DR. BHALCHANDRA MUNGEKAR (NOMINATED): Thank you, Sir, for allowing me to raise this matter of national importance.

Sir, Scheduled Castes and Scheduled Tribes constitute about 25 per cent of our country's population... (Interruptions)...

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, what is this disturbance? (Interruptions)

***Not recorded**

DR. BHALCHANDRA MUNGEKAR: They continue to suffer from multiple disabilities, economic, social, educational, and so on. Besides, they have suffered all kinds of discrimination for centuries. Today, I would like to share with this august House my deep anguish and concern over the growing number of atrocities against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in different parts of the country.

Sir, as per the Home Ministry's statistics, there were 1,46,2900 crimes against Scheduled Castes and Scheduled Tribes between 2001 and 2005. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Atrocities Act is absolutely irrelevant so far as its implementation is concerned. In the Khairlanji case in Maharashtra, where four dalits, a mother and her three children, were virtually lynched, as per the Court's order and observation, investigation by the police and the local CID were not conducted properly. Unfortunately, the matter was referred to the CBI but CBI also did not challenge the acquittal of the accused under Section 354 of the Indian Penal Code, as the Prevention of Atrocities Act requires. Therefore, I am convinced that all this was not just an accident, but care was taken to see that the Atrocities Act was not applicable to the Kharlanji case at all. In view of this case, the future of the POA as well as safety and security are in danger.

(Contd. at 1t/hk)

HK-ASC/1t/12.55

DR. BHALCHANDRA MUNGEKAR (CONTD.): The Government, therefore, must implement the Prevention of Atrocities Act in all sincerity and do justice to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. I also appeal to this House and all

sections of the society that generally when atrocity takes place, it is only the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes who protest. It is absolutely not auguring well with the commitment to equality -- social, economic and political in the country. Fighting atrocities against the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is not the responsibility of those communities alone. That is why I take the opportunity to appeal to all sections of the House and the Indian society to raise their voice to implement the provisions of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act and do justice to the most neglected and vulnerable sections of the society.

(Ends)

SHRI D. RAJA (TAMIL NADU): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI MOINUL HASSAN (WEST BENGAL): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI RANJITSINH VIJAYSINH MOHITE-PATIL (MAHARASHTRA): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

(Ends)

RE. DENIAL OF PAYMENT OF SALARY TO THE RAILWAY EMPLOYEES IN KERALA

SHRI P. RAJEEVE (KERALA): Sir, I would like to raise a serious issue regarding the denial of payment of salaries to the Railway employees in Kerala before 20th August in connection with Onam. The Ministry of Finance has given orders on 5th of this month for advance payment of salaries. The order says, "In view of the

'ONAM' festival, the Government have decided that the salary of all Central Government employees in the State of Kerala for the month of August, 2010 may be drawn and disbursed by the Central Government offices (including Defence, Posts & Telecommunications) on 20th August, 2010." We are very grateful to the Finance Ministry for recognizing the feelings of Malayalese. The Ministry has also given orders for advance payment of pension also. But, Sir, only one Ministry, that is, the Ministry of Railways in this country is not ready to implement the directions of the Finance Ministry. Even the Defence Ministry and other Government companies like BSNL and MTNL have also followed this order, but the Railway Ministry has not issued orders for the disbursement of salaries before today, that is, 20th August. Is the Railway Ministry functioning as a separate republic in our country? There is clear evidence of breach of collective functioning of the Ministry and the Government in many cases. It is also evident in this case. This is a very serious discrimination against the State of Kerala by the Railway Ministry. The Minister of State of Railways belongs to Kerala State, but I don't know why he could not recognize the feelings of Malayalese. I request the Minister to intervene in this issue and ensure today itself the payment of advance salary. Today is the only working day before Onam. I request the Government to intervene in this issue.

(Ends)

RE. THREAT TO SIKHS IN THE KASHMIR VALLEY

श्री राजीव प्रताप रूडी (बिहार) : उपसभापति महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में आप से चर्चा हुई है और हमने नाटिस भी दिया है। हम इस बात को मानते हैं कि सिख

समुदाय का भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में जिस प्रकार का कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको कभी भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सिख समुदाय का एक स्थान है। उन्होंने हर क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाया है। चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे यूथ का क्षेत्र हो, चाहे देश की सुरक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उनका योगदान है । आप चाहे दक्षिण में चले जाओ, उत्तर में चले जाओ, पश्चिम में चले जाओ, देश के हर कोने में हम सिख समुदाय को देखते हैं। हम उनको बड़ी कद्र के साथ अपने भाई की तरह मानते हैं। हमने देखा है कि हाल के कई वर्षों में जिस प्रकार से सिख समुदाय के साथ अफगानिस्तान में व्यवहार हुआ है, हमने वे तमाम तरह की घटनाएं देखी हैं। उसके बारे में सदन में भी चर्चा हुई है और सदन ने भी उस बारे में चिंता व्यक्त की है, लेकिन हम उनको वहां जितना सुरक्षित करना चाहते थे, दुर्भाग्य से उतना सुरक्षित नहीं कर पाए। हमने पाकिस्तान में भी देखा है कि पिछले कई वर्षों में ऐसी घटनाएं घटी हैं, जहां हम सिखों की सुरक्षा नहीं कर पाए हैं। वहां पर जिस प्रकार से सिखों के सिर काटे गए, उनका कत्ल किया गया, हमारे तमाम प्रयास के बाद भी भारत सरकार पूरी तरह से विफल रही, हम इस बात को जानते हैं। हमें विश्वास है कि सरकार उस काम में पूरी तरह लगेगी। आज हमारी सबसे बड़ी चिंता जम्मू और कश्मीर के बारे में है और इस बारे में मेरा नोटिस भी है। वहां पर लगभग एक लाख सिख समुदाय के लोग रहते हैं, जिस प्रकार से उनको चेतावनी दी गई है, चुनौती दी गई है और सभी समाचार-पत्रों में छपा है, उनको तीन विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प यह है कि आप या तो आपना धर्म परिवर्तित करें, यदि आप अपना धर्म परिवर्तित नहीं करते हैं, तो कम से कम आप Stone Pelters' Association के सदस्य बनें, यानी जितने वहां एंटी नेशनल हैं, उनके साथ लाइन में खड़े हो जाएं। सिख समुदाय का आदमी देश के लिए हमेशा कुर्बानी देता रहा है।

(1U/LPपर क्रमशः)

श्री राजीव प्रताप रूडी (क्रमागत) : उसको यह कहना कि "तुम हमारे साथ देश के आंदोलन में खड़े होओ", यही उसका सबसे बड़ा अपमान है। वे उनसे कह रहे है कि या तो आप "स्टोन पैल्टर्स एसोसिएशन" के सदस्य बनो, नहीं तो जम्मू-कश्मीर से बाहर निकल जाओ। महोदय, यह कोई पहली घटना नहीं है, यह शुरुआत है। जो शुरुआत हम देख रहे हैं, वह हमने पहले भी देखी है कि जिस प्रकार से कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं को वहां से निकालकर भगाया गया, आज वे पूरे भारत में बिछे हुए हैं, चारों तरफ हैं, दिल्ली में हैं, हमारी पीड़ा उनके साथ है, हम उनको वापस वहां पर पुनर्वासित नहीं कर पाए हैं, आज अगर वैसी ही चुनौती फिर से सिख समुदाय के साथ हो तो उस परिस्थिति में हमारा क्या रिस्पॉंस होगा। आज We are proud to have a Prime Minister who is a Sikh. We are proud; the country is proud of him. But, enough is enough and if this is what the policy of the Government is, and if this is how the Government is going to treat the Sikh community in this country, it is a matter of great concern. It is not just Rajiv Pratap Rudy; it is not just the BJP, or, the JD(U), or, the Congress; if this is an attitude and if this is going to happen, the entire country would be compelled to go and shed our lives to protect each and every Sikh residing in the Valley. This will happen. The Prime Minister recognised the problem, but the Prime Minister cannot...(Interruptions).

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, all are associating.

श्री अविनाश राय खन्ना (पंजाब) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश) उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करती हूं।

श्री बलबीर पुंज (उड़ीसा) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

सुश्री अनुसुइया उइके (मध्य प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

श्री अनिल माधव दवे (मध्य प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

श्री नरेश गुजराल (पंजाब) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं। Sir, I want to take only ten seconds to add to what Mr. Rudy has said. Sir, there were hundred thousand Sikhs in the Valley. Unfortunately, their number has now come down to 50,000. They are leaving by the day, and I am sorry to point out that twice, their delegations have come to Delhi to meet the Prime Minister, but they were not given time. I hope that now, the Prime Minister will send for them and re-assure them that their lives and property and their families would be protected in the Valley.

(Ends)

RE. REHABILITATION OF VICTIMS OF LEH TRAGEDY

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदय, 5, 6 तारीख की रात लेह में जो कुछ घटा, वह प्राकृतिक विपदा थी। यह सब हमारे सामने आ चुका है, लेकिन लेह में आज भी जिस तरह से नागरिकों को तकलीफ हो रही है, उससे परेशानी है। तीन-तीन केंद्रीय मंत्री वहां गए थे, लेकिन वहां की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। आज भी आप वहां पर टेलीफोन नहीं लगा सकते हैं, कोई बात नहीं कर सकते हैं। वहां पर कीचड़ों का अम्बार लगा हुआ है, नागरिकों की साधारण बुनियादी सुविधाओं पर प्रश्न चिह्न लगा हुआ है। गृह मंत्री जी ने यहां आकर सारी बातें रख दीं कि वहां पर हालत स्थिर हो रही है, बढ़िया हो रहा है, परंतु 7,400 लोग वहां से बाहर जा चुके हैं। उनके लिए सरकार ने 429 करोड़ रुपए दे दिए हैं, लेकिन वे लोग रुपए का क्या करेंगे? वहां पर व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। वहां सरकार कोई नागरिक

सुविधा, जैसे पीने का पानी भी मुहैया नहीं करवा पा रही है। वहां शुद्ध पीने के पानी की जगह पर पूरी तरह से गंदा पानी फैला हुआ है।

(उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे.कुरियन) पीठासीन हुए)

वहां पर महामारी फैलने की पूरी तरह से संभावना व्यक्त की जा रही है। हम लोग यहां पर बैठे हैं, गृह मंत्री जी ने कहा कि सब कुछ देखकर आ गए हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या वहां पर इस तरह की स्थिति है, क्या लोग वहां से जा रहे हैं, क्या वहां पर लोग रह पा रहे हैं? हमारा यह कहना है कि आप वहां की स्वास्थ्य सेवाएं देखिए। वहां के सारे लोग इस समय बीमार हैं। वहां पर कोई स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दी जा रही हैं। आपने डॉक्टर्स की टीम भेज दी। आपने कह दिया है कि वहां पर चार नर्सेज़ भेज दी हैं, लेकिन वहां पर लोगों को अपने बच्चे नहीं मिल रहे हैं, किसी का पिता खो गया है, किसी की मां नहीं मिल रही है, किसी की बहिन नहीं मिल रही है। सर, लेह भारत का ही हिस्सा है। लेह में प्राकृतिक आपदा आई है। वहां पर सैनिक सब काम कर रहे हैं। मैं उन सैनिकों को सेल्यूट करता हूं। सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी लेह की हालत बहुत विचित्र है, दर्दनाक है। उपसभाध्यक्ष जी, मैं यहां पर एक बात बहुत शिद्दत के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूं, आप मेरी बात सुनेंगे। उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपसे डिस्टर्ब हो रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष : आप बोलिए।

श्री प्रभात झा : मैं जिस बात को कहना चाह रहा हूं, वह यह है कि आज लेह में लोग जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि स्थिति ठीक नहीं है। आज सवेरे ही मैंने अखबारों में एक विज्ञापन देखा, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, आदर अर्पित करता हूं, लेकिन अखबारों में करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए गए हैं, करोड़ों रुपए कागज के टुकड़े के लिए खर्च किए गए हैं, मेरा निवेदन है कि अगर ये करोड़ों रुपए लेह के लिए दिए जाते, तो गरीब और अनाथ बच्चों को शायद रोजी रोटी मिलती और भूख की वजह से जो लोग मर रहे

हैं..(व्यवधान)..मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। ..(व्यवधान)..मैं बता रहा हूं..(व्यवधान)..मैं एक निवेदन कर रहा हूं। यदि राष्ट्रीय विपदा हो...(व्यवधान)..

(AKG/1W पर क्रमागत)

AKG-YSR/1W/1.05

श्री प्रभात झा (क्रमागत) : यह राष्ट्रीय विपदा है, राष्ट्रीय आपदा है ... (व्यवधान) ... और इससे बड़ी श्रद्धांजलि और नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्य है कि हर चीज़ में राजनीति होती है। क्या करोड़ों रुपए बर्बाद करने से आपको लाभ मिलेगा? (समय की घंटी) मेरा निवेदन है कि इस पर विचार करना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay. Your time is over.

श्री प्रभात झा : इस तरह सरकार को करोड़ों रुपए, जो विज्ञापनों के माध्यम से बर्बाद किए गए, नहीं करने चाहिए थे।

(समाप्त)

THE VICE-CHAIRMAN: Now, we shall take up Special Mentions.

SPECIAL MENTIONS *

Kgg/9a

NEED FOR CONSOLIDATION OF PUBLIC SECTOR BANKS

--

SHRI N.K. SINGH (BIHAR): I would like to draw the attention of the Finance Minister to the need for consolidation of public sector banks. Our banks are not

---

* Laid on the Table of the House.

able to compete in the global arena in terms of fund mmobilisation, loan disbursal, investment and rendering of financial services due to the fragmented nature of the industry. Even the largest bank, the State Bank of India ranks 76 in terms of total assets and 64 in terms of tier-I capital globally.

The lack of global scale for Indian banks came into sharp focus during the recent financial crisis that saw several international banks reneging on their funding commitments to Indian companies. But, local banks could not step into the breach because of balance sheet limitations. While the Government is widely reported to have a pro-consolidation stand itself, I urge the Minister to take decisive actions in this direction and not delay such consolidation further.

(Ends)

TDB/9B

CONCERN OVER THREAT TO LIFE AND PROPERTY OF VILLAGERS IN WEST BENGAL DUE TO SUBSIDENCE OF ILLEGAL COAL MINES

SHRI R.C. SINGH (WEST BENGAL): Sir, I would like to draw your kind attention that on 23rd July, 2010, subsidence at Porascole village, P.S. Asansol, District Burdwan, West Bengal, in Kajoria area of Eastern Coalfields Ltd., has taken place owing to mining operations. About 550 sqm. has been subsided. The village is totally covered by mining and there is no doubt that the whole underground of the village has been mined out by ECL and illegal miners. Since the subsidence has taken place very close to the village, some houses of the village have to be vacated as per the order of the Safety Department of Mines. Earlier also, many

cases of subsidence have taken place adjacent to the village, and the same has been brought to the notice of the concerned authorities. But, nothing has been done in that respect. It is not only due to mining operations by ECL, but also due to rampant illegal mining. Not only this, due to unscientific mining operations, huge agriculture land has been damaged and the life and property of villagers is in danger.

About 3,000 habitations are residing there for centuries. These incidents are posing danger to these villagers and their property. In view of this, I request you to immediately direct the officials concerned in the Ministry and take necessary steps forthwith to halt illegal mining; and villagers are shifted to safer places with appropriate arrangements for their livelihood, or, make proper arrangements for the safety of the village.

(Ends)

ASC/9c

DEMAND TO TAKE STEPS TO ASCERTAIN THE FEES CHARGED BY THE PRIVATE MEDICAL PRACTITIONERS AND HOSPITALS IN THE COUNTRY

सुश्री अनुसुइया उइके (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि देश में गरीबों के लिए कैंसर, हृदय की शल्य चिकित्सा, सिर की चोटों की चिकित्सा, ब्लड कैंसर, स्पाईन सर्जरी, जैसी गंभीर बीमारियों की जिला चिकित्सालयों एवं छोटी जगहों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ा नहीं है।

आम व्यक्तियों को निजी चिकित्सालयों एवं चिकित्सकों की शरण में जाना पड़ता है, जिनके शुल्क शासन द्वारा निर्धारित नहीं हैं, इसलिए उनके द्वारा बहुत अधिक फीस ली जाती है। यह फीस गरीब एवं आम व्यक्तियों की हैसियत से बहुत अधिक होती है किंतु गंभीर बीमारी,

दुर्घटना के समय मजबूरी में निजी चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों की शरण में जाना ही पड़ता है।

निजी चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा कार्य को पूर्णतः व्यवसाय बना लिया गया है। मरीजों का बिल बढ़ाने के लिए लम्बे समय तक उन्हें भर्ती रखा जाता है, विभिन्न क्लिनीकल परीक्षण किए जाते हैं, इसके उपरांत भी मरीज के जीवित रहने की कोई गारंटी नहीं होती है और न ही मरीज की स्थिति के बारे में सही जानकारी दी जाती है। यहां तक देखा गया है कि यदि मरीज का स्वर्गवास हो जाता है तो जब तक उसके परिजन अस्पताल का बिल जमा नहीं करा देते, तब तक लाश उनको नहीं दी जाती है। इस प्रकार का व्यवहार चिंता का विषय है।

ऐसी स्थिति में बीमार व्यक्ति को या तो अपनी संपत्ती बेच कर इलाज करवाना पड़ता है अथवा इलाज के अभाव में उसकी मौत हो जाती है।

अतएव मेरा सरकार से अनुरोध है कि देश में कार्यरत निजी चिकित्सालयों, चिकित्सा परीक्षणों एवं चिकित्सकों की फीस निर्धारित की जाए, जिससे गरीब एवं आम व्यक्तियों की मौत होने से बचाया जा सकता है।

(समाप्त)

LP/9D

NEED FOR ESTABLISHING AIIMS/PGI, CHANDIGARH LIKE INSTITUTE IN HIMACHAL PRADESH

श्रीमती बिमला कश्यप सूद (**हिमाचल प्रदेश**) : मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूं कि मैं पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश से आती हूं और यह हर्ष की बात है कि स्वयं माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं। वे पहाड़ी क्षेत्र की समस्याओं से भली-भांति परिचित हैं। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संसाधन सीमित हैं। वहां पर कोई बड़ा (AIIMS) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा चण्डीगढ़ स्थित PGI की भांति अस्पताल नहीं है और न ही कोई ट्रामा सेंटर है। पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की भी बहुत कमी रहती है। हिमाचल प्रदेश में 1000 व्यक्ति

प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटना की वजह से मर जाते हैं और लगभग 1500 लोग सड़क दुर्घटना की वजह से अपंग हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं, इसलिए 12 ट्रामा सेंटर होने चाहिए, जो पूर्ण रूप से आधुनिक उपकरणों द्वारा सुसज्जित हों। जब कभी बस या कार 400, 500 फुट गहरी खाई में गिर जाती है तो पीड़ित लोगों को खाई से निकाल कर जब तक अस्पताल पहुंचाया जाता है, तब तक आधे लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, अतः पूर्ण रूप से आधुनिक उपकरणों द्वारा सुसज्जित एम्बुलेंस होनी चाहिए। जो विशेषज्ञ डाक्टर हैं, उनको विशेष भत्ता, बेहतर आवास व्यवस्था, जैसे प्रोत्साहन केंद्र सरकार को देने चाहिए। अतः मैं सरकार के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय से मांग करती हूं कि हिमाचल प्रदेश में एक बड़े अस्पताल, जो (AIIMS) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा चण्डीगढ़ स्थित (PGI) की तरह का अस्पताल हो, की अति आवश्यकता है, ताकि आम आदमी को उचित स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी सेवाएं उपलब्ध हो सकें।

(समाप्त)

AKG/9E

DEMAND FOR BAN ON USE OF GM SEEDS

डा. राम प्रकाश (हरियाणा) : महोदय, यूरोप सहित विश्व के 180 देशों में जी.एम. कृषि और उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। जी.एम. खेती का 75 प्रतिशत अमेरिका, कनाडा, ब्राजील व अर्जेंटीना में होता है। इन देशों में भी कपास, सोयाबीन, मक्का, बैनोला में ही जीन संवर्द्धन की अनुमति है। बीटी बैंगन के खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल की अमेरिका और इंग्लैंड में अनुमति नहीं है। भारत में जीएम फसलों को परखने के लिए गठित जी.ई.ए.सी. ने अक्तूबर 2009 में बीटी बैंगन की व्यावसायिक खेती की अनुमति दे दी थी, जिस पर उत्पादकों, उपभोक्ताओं आदि के विरोध के कारण और अधिक अनुसंधान करवाने का पर्यावरण मंत्री तथा यूपीए सरकार का फैसला सराहनीय है। पर भिंडी, पत्तागोभी, टमाटर, धान आदि की

व्यावसायिक खेती पर पर्यावरण मंत्रालय का यह फैसला लागू नहीं है। अभी ऐसे 41 खाद्य फसलों पर परीक्षण चल रहे हैं। जी.एम. बीज की अनुमति देने से पूर्व कम-से-कम 30 परीक्षण अनिवार्य है। जिन खाद्य फसलों की अनुमति दी गई है, उन पर पूरे परीक्षण नहीं किए गए। प्रायः सभी परीक्षण उत्पादक कम्पनियों या किसी सरकारी एजेंसी के हैं। उनकी independent testing नहीं हुई। बीटी बैंगन पर निर्णय केवल 90 दिन की स्टडी पर आधारित था और वह भी केवल 10 चूहों पर। इन खाद्य पदार्थों पर दीर्घकालीन अध्ययन नहीं किए गए। बीटी कॉटन का अनुभव भी सुखद नहीं है। जीएम खेती का आस-पास के खेतों में कुप्रभाव पड़ता है। बीज शुरू में अच्छी पैदावार देता है, लेकिन धीरे-धीरे उत्पादकता में कमी आ जाती है। तीन-चार साल के बाद खेत में ऐसे कीट पैदा हो जाते हैं, जिनके लिए अधिक शक्तिशाली रसायनों की जरूरत पड़ती है।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि जीएम बीजों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए।

(समाप्त)

9F/DS/SPL. MENTION/20.08.2010

DEMAND FOR INQUIRY INTO IRREGULARITIES BEING COMMITTED BY PRIVATE HAJ TOUR OPERATORS

श्री मोहम्मद अली खान (**आन्ध्र प्रदेश**): सर, मैं आपके तवस्सुत से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफ़ेयर्ज़ का ध्यान हज कोटा हासिल करने वाले प्राइवेट टूर-ऑपरेटरों की धांधलियों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। हिन्दुस्तान को सऊदी अरब सरकार ने 1,60,000 से ज्यादा हाजियों का कोटा अलॉट किया है, जिसमें से हज कमेटियों के ज़रिये 1,26,000 से ज्यादा हाजी भेजे जाते हैं और बाकी कोटा प्राइवेट टूर-ऑपरेटरों को अलॉट कर दिया जाता है, लेकिन अफ़सोस की बात है कि कुछ टूर-ऑपरेटरों के अलावा, जो ख़ुलूस और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, बहुत से टूर-ऑपरेटर्स बहुत धांधलियाँ कर रहे हैं। जहाँ हज कमेटी के ज़रिये जाने वाले हाजी का तक़रीबन 1,26,000 रुपये ख़र्चा आता है, वहीं प्राइवेट टूर-ऑपरेटर्स हर

हाजी से कम से कम 1,80,000 रुपये वसूल करते हैं और कुछ ऑपरेटर्स हज की बढ़ती हुई मांग का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर चार से पाँच लाख रुपये तक वसूल करके अपने कोटे का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले हाजी मेहरूम रह जाते हैं। प्राइवेट हज टूर-ऑपरेटरों की बहुत सी शिकायतें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफ़ेयर्ज़ के पास पड़ी हुई हैं। मैं ऐसे कई मामलों से वाक़िफ़ हूँ और मैंने इसकी शिकायत वज़ीर-ए-आज़म और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफ़ेयर्ज़ से भी की है।

इसलिए भारत सरकार से मेरी माँग है कि हज का कोटा हासिल करने वाले प्राइवेट टूर-ऑपरेटरों के खिलाफ़ उन तमाम शिकायात की जाँच के लिए इस साल हज से पहले ही एक कमेटी मुक़र्रर की जाए और उन धांधलियों के ज़िम्मेदार पाए जाने वाले सभी प्राइवेट टूर-ऑपरेटरों के खिलाफ़ सख्त कार्यवाही की जाए। साथ ही, मेरी माँग है कि प्राइवेट टूर-ऑपरेटरों का कोटा खत्म करके उसे सूबाई हज कमेटियों में तक़सीम कर दिया जाए ताकि आम हाजियों को राहत मिल सके।

(समाप्त)

جناب محمد علی خان (آندھرا پردیش) : سر، میں آپ کے توسط سے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کا دھیان حج کوٹہ حاصل کرنے والے پرائیویٹ ٹور-آپریٹروں کی دھاندلیوں کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کو سعودی عرب سرکار نے 1،60،000 سے زیادہ حاجیوں کا کوٹہ الاٹ کیا ہے، جس میں سے حج کمیٹیوں کے ذریعے 1،26،000 سے زیادہ حاجی بھیجے جاتے ہیں اور باقی کوٹہ پرائیوٹ ٹور-آپریٹروں کو الاٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ کچھہ ٹور-آپریٹروں کے علاوہ، جو خلوص اور ایماندری سے اپنا کام کر رہے ہیں، بہت سے ٹور-آپریٹرز بہت دھاندلیاں کر رہے ہیں۔ جہاں حج کمیٹی کے ذریعے جانے والے حاجی کو تقریبا 1،26،000 روپے خرچ آتا ہے، وہیں پرائیویٹ ٹور-آپریٹرز ہر حاجی کو کم سے کم 1،80،000 روپے وصول کرتے ہیں اور کچھہ آپریٹرز حج

کی بڑھتی مانگ کا ناجائز فائدہ اٹھاکر چار سے پانچ لاکھ روپے تک وصول کرکے اپنے کوٹے کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے حاجی محروم رہ جاتے ہیں۔ پرائیویٹ حج ٹور-آپریٹروں کی بہت سی شکایتیں منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ میں ایسے کئی معاملوں سے واقف ہوں اور میں نے اس کی شکایت وزیر اعظم اور منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز سے بھی کی ہے۔

اس لئے بھارت سرکار سے میری مانگ ہے کہ حج کا کوٹہ حاصل کرنے والے پرائیویٹ ٹور-آپریٹروں کے خلاف ان تمام شکایات کی جانچ کے لئے اس سال حج سے پہلے ہی ایک کمیٹی مقرر کی جائے اور ان دھاندلیوں کے ذمہ دار پائے جانے والے سبھی پرائیویٹ ٹور-آپریٹروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے۔ ساتھہ ہی، میری مانگ ہے کہ پرائیویٹ ٹور-آپریٹروں کا کوٹہ ختم کرکے اسے صوبائی حج کمیٹیوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ عام حاجیوں کو راحت مل سکے۔

(ختم شد)

KLS/9G

DEMAND TO WITHHOLD ENVIRONMENTAL CLEARANCE TO THE PROPOSED POWER PROJECT AT SOMPETA IN ANDHRA PRADESH

SHRI SYED AZEEZ PASHA (ANDHRA PRADESH): Sir, a private mega power plant of 1000 MW was proposed at Sompeta, Srikakulam District in Coastal Andhra Pradesh. The location of the mega power plant is in a sensitive ecological zone on the coast effecting 8 Panchayats and 2 lakh people covering 20 kilometre area with a water body serving the drinking water needs of the people other than flora and fauna. The farmers and fishermen have been protesting against and it recently culminated in a police firing, resulting in deaths and serious injuries to

hundreds of people. National Environmental Appellate Authority conducted a study afterwards and suspended all environmental clearances.

After suspension, the people hoped that the plant would be scrapped. However, the State Government has since been writing letters to the Government of India to rescind it. This has fuelled anxiety among locals. Tension is prevailing in the area again.

Public agitations and facts being considered afresh, there should be no re-issue of clearances. People expect Government would reject such toxic projects violating laws in public interest. It is not a good practice to give permission to such projects and then await public reaction. There is no doubt that if Ministry of Environment and Forests tries to revive this project, there will be violent agitations. I appeal to the Government of India to announce that this mega power plant at Sompeta is rejected. This assurance is urgently needed as tension is building up in Sompeta and there is grave insecurity as private sectors interests are preparing threatening postures against the fishermen and farmers. Thank you.

(Ends)

NB/9H

DEMAND TO RESTORE THE EMERGENCY QUOTA IN TRAINS PLYING THROUGH BIHAR

श्री राम कृपाल यादव (बिहार) : उपसभापति जी, अभी ऐसा समाचार आया है कि रेल मंत्रालय ने बिहार आने-जाने वाली सभी गाड़ियों में आपातकालीन आरक्षण कोटे (EQ) को घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। समाचार के अनुसार 2394 संपूर्ण क्रांति में 60 से घटाकर 24, सम्पर्क क्रांति में 52 से घटाकर 30, श्रमजीवी में 40 से घटाकर 24, वैशाली में 42 से घटाकर

24, विक्रमशिला में 40 से घटाकर 24 आदि इसके कुछ द्रष्टांत हैं । बिहार की सभी गाड़ियों में प्रतिदिन बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। EQ के द्वारा VVIP से कुछ राहत दी जा रही थी, वह भी अब समाप्त कर दी गई है। बिहार के लोगों के साथ यह अन्याय हो रहा है। पूर्व रेल मंत्री जी द्वारा चालू की गई योजनाओं पर कुछ कार्य नहीं हो रहा है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि बिहार के लिए स्वीकृत परियोजनाओं और EQ को पुनः बहाल किया जाए, सभी परियोजनाओं पर तीव्र गति से काम हो और इनके लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाए।

(समाप्त)

SSS/9J/

NEED FOR EASY ACCESS TO HIGHER EDUCATION FOR EVERY CITIZEN OF THE COUNTRY

DR. JANARDHAN WAGHMARE (MAHARASHTRA): Sir, education for whom and education for what? These are the two most important and crucial questions. 'Education for all' is the answer to the first question. This is the national policy on education. Education for life is the answer to the second question. The right of children to free and compulsory education is a Fundamental Right now. It has put education into action. But this right is continued only to elementary education, for children in the age group of 6-14 years. The elementary education is not enough to develop the whole potential in an individual male or female. Higher education is essential for the development of human resources as well as natural resources. Time demands that secondary education should be universalized. Higher education is an engine of development. Secondary and higher education cannot be made free and compulsory. But it is also a fact that students from weaker and marginal sections of society cannot bear the cost of higher and technical

education. Then, what to do? Government should give them loans at low interest, say four per cent. Government should also open professional colleges for them. Poor students cannot bear the expenditure of private colleges. At the same time, Government should construct hostels at *taluka* places and provide them accommodation with minimum charges. A talented individual, properly educated and equipped with skills is an asset to the nation. I urge upon the Government to give opportunity of education at all the levels, to every boy and girl.

(Ends)

9k/VNK

DEMAND FOR PROVIDING MARKETING AND PROCESSING FACILITIES TO THE POTATO GROWERS IN THE COUNTRY

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): महोदय, देश के 8 प्रमुख राज्य के किसान आलू की खेती प्रमुखता से करते हैं और इन राज्यों का आलू पूरे देश में खाने में उपयोग होता है। आलू के किसानों के लिए मार्केटिंग की व्यवस्था न होना, फूड प्रोसेसिंग उद्योगों की कमी व निम्न स्तर के आलू का उत्पादन होना, जिसके कारण विदेशों में भारत के आलू की मांग न होना, आलू किसानों के लिए ये भीषण समस्याएं हैं। उपरोक्त समस्याओं के कारण इस वर्ष आलू के किसान को आलू की कीमत 2 रुपए प्रति किलो भी नहीं मिल पा रही है। कोल्ड स्टोरेज भरे हैं और किसान उनका किराया देने की स्थिति में नहीं है। वह कोल्ड स्टोर से आलू नहीं उठा रहा है। बाजार में आलू की मांग नहीं है। भारत सरकार ने भी इसकी खरीद का कोई इंतजाम नहीं किया, इससे स्थिति विकट होती जा रही है। किसान आत्महत्या पर उतारू हो गया है। कोई

भी अप्रिय घटना हो सकती है। हम इस विशेष उल्लेख के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर स्थिति से अवगत होना चाहते हैं। धन्यवाद।

(समाप्त)

-SSS/NBR/9L.

NEED TO CHECK UNSOLICITED TELEPHONE CALLS

SHRI MOINUL HASSAN (WEST BENGAL): Sir, unsolicited phone calls are one of the major problems that telecom customers are facing. The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has framed the Telecom Unsolicited Commercial Communications Regulations, 2007, for curbing unsolicited calls. Under this, all telecom subscribers are to maintain a Private Do Not Call List of subscribers who do not want to receive any UCC. This is to be updated in the National Do Not Call Registry established in 2007. All telemarketers are also required to register in the NDNC Registry.

(iv) Even after registering in NDNC, complaints regarding UCC have been received by service providers.

(v)The frequency of receiving unsolicited SMS and MMS has increased.

(vi) The framework established is not very effective as only about 11 per cent of the telephone subscribers have registered for 'Do Not Call' in NDNC Registry since the process is complicated and there is no appropriate advertising to make customers aware.

(vii) A penalty of only Rs. 500 for the first time call and Rs. 1,000 for every subsequent call is made by the telemarketer to the service provider. No

compensation is provided to the customer for the mental irritation he faces.

(viii) There are no penal provisions for unsolicited private communications.

Due to limited effectiveness of the present regulations and the large number of complaints being received, TRAI is considering public consultations on the issue of Do Call Registry in place of NDNC for reducing unsolicited calls.

I urge upon the Government to take effective measures in this regard.

(Ends)

(FOLLOWED BY USY "9M")

USY/9M

DEMAND TO SUPPLY ADEQUATE UREA AND OTHER FERTILIZERS TO FARMERS OF ANDHRA PRADESH

SHRI M.V. MYSURA REDDY (ANDHRA PRADESH): Sir, due to start of sowing season in Andhra Pradesh, the demand for urea has gone up. The requests for making the urea available have gone up from the farmers of almost all the districts of Andhra Pradesh. But in the absence of adequate supply of urea, the farmers are facing umpteen problems in the sowing season. In June and July, the Government of India has allotted 4.8 lakh tonnes of urea, but supplied only 3.57 lakh tonnes of urea. The demand of urea, in May, was 1.02 lakh tonnes, but supplied only 0.96 lakh tonnes; in June, the demand was 1.35 lakh tonnes and the supply was only 1.31 lakh tonnes; and in July, the demand was 2.31 lakh tonnes and the supply was only 2.10 lakh tonnes. In august, the demand is 4.5 lakh

tonnes, but the supply, till today, is only 1.2 lakh tonnes. This clearly shows that there is a drastic reduction in the supply of urea to Andhra Pradesh. Even the stocks in the MARKFED have exhausted. The Government of India says that 2.97 lakh tonnes of urea for Andhra Pradesh has to come from abroad. It means, till the imports reach our country, the farmers will have to wait and by the time the imports would reach Andhra Pradesh, the sowing season would be over. Due to this, there is a rampant black-marketing and hoarding of fertilizers in the State. In view of the above, I request the Government of India to immediately take steps and release urea, complex and other fertilizers required for the farmers of Andhra Pradesh.

(Ends)

(Followed by 1x/VKK)

-YSR/VKK-DS/1x/1.10

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): The House is adjourned to meet at 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch
at eleven minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-one minutes past two of the clock, THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN: Hon. Members, see, the Appropriation (Railways) No.4 Bill, 2010 is also listed. A special Supplementary List of Business is being circulated. Therefore, you know that it is more important. So, I would like to take the sense of the House. Shall we take up the Appropriation (Railways) No.4 Bill, 2010 first as it is more important?

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

DR. V. MAITREYAN: We can take up this Bill first, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN: Now, Km. Mamata Banerjee to move the Bill.

SHRI D. RAJA: Sir, I want to seek only one small clarification. After the Railways Bill, what will be the next item of business? ...(Interruptions)...

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Sir, since yesterday, we have been frequently changing the items one after another. At least, ten times it has been changed since yesterday. ...(Interruptions)...

SHRI D. RAJA: What is the next item to be taken up after the Railways Bill?

THE VICE-CHAIRMAN: I will let you know. Hon. Minister, the question is: After the Railways Bill, which item is to be taken up? Shall we go as per the agenda?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN): Sir, we shall start the discussion on illegal mining. Rest of the business can be taken up tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : That is clear. So, you agree that after the Railways Bill, we will take up the discussion on illegal mining.

SHRI BALAVANT alias BAL APTE: Sir, what about the other Bills? Will they be taken up tomorrow? Tomorrow morning, there will be no Government Business.

THE VICE-CHAIRMAN: Tomorrow morning, there will be Government Business. Tomorrow morning, we can take up these Bills. Now, we are going to take up the Railways Bill. After the Railways Bill discussion is over, we will take up illegal mining.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Sir, tomorrow morning, it is a Private Members' Bill. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN: Just now you have said 'after the Railways Bill, illegal mining'!

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: There will be no changes, I suppose! ...(Interruptions)...

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: Sir, what changes they want? ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN: I announced it after taking the sense of the House. I have not taken the decision. It was your decision. It was the decision of the House. Now, Km. Mamata Banerjee, please move the Bill.

THE MINISTER OF RAILWAYS (KM. MAMATA BANERJEE): Sir, I beg to move:

That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2010-11 for the purposes of Railways, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The question was proposed.

श्री अविनाश राय खन्ना (पंजाब) : उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर हम रेलों को देखें, तो रेलें पैसेंजर्स को लेकर जाती हैं, कोचेज़ लेकर जाती हैं। रेलवे का इंटरनेशनल इतिहास भी है क्योंकि पाकिस्तान को भी रेल जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह भारतीय रेल भी है और अंतर्राष्ट्रीय रेल भी है। यह कई राज्यों को भी आपस में जोड़ती है। जैसा आज माननीय मंत्री महोदया ने बताया कि करीब 2 करोड़ लोग प्रतिदिन रेलों से सफर करते हैं। इसलिए रेलवे का बहुत महत्व है। रेलवे का डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है। देश के कोने-कोने में रेलों का जाल बिछा हुआ है। इसलिए रेलवे के प्रति बहुत सी अपेक्षाएं लोगों के मन में हैं।

(1Z/VNK पर क्रमशः)

-NB/VNK-TMV/1z/02:35

श्री अविनाश राय खन्ना (क्रमागत): रेलवे का सफर सुरक्षित हो, रेलवे में पूरी सेफ्टी हो, रेलवे में खाना अच्छा मिले, पैसेन्जर्स को सुविधाएं हों, करप्शन बिल्कुल न हो, रेल साफ-सुथरी हो, रेल टाइम पर आए और टाइम पर जाए, स्टाफ का व्यवहार अच्छा हो और रेलवे का जो expansion है, वह भी हो, जहां तक रेल नहीं पहुंची है, वहां तक रेल पहुंचनी चाहिए, नए पुल बनें, फुट ब्रिज बनें और रेलवे में जो facilities नहीं हैं, वे facilities भी provide की जाएं, जैसे

कि medical facility. रेलवे employment देने वाली एक बहुत बड़ी संस्था है। लाखों लोग रेलवे में काम करते हैं। रेलवे में जो भर्ती हो, वह भी transparent way से हो। ऐसी आम लोगों की अपेक्षा है। रेल फौजियों और उनके वाहनों को इधर से उधर ले जाने का काम भी करती है। रेलवे यह एक बहुत महत्वपूर्ण काम करती है।

लेकिन आज modern age में लोग पैसा खर्च करके रेल में बैठते हैं तो वे चाहते हैं कि रेल में उनको सब कुछ अच्छा मिले। लेकिन, मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ, जिन पर यहां अलग-अलग प्रश्नों के समय में चर्चा भी हुई है, जब रेल देर से आई, रेलवे में सफाई नहीं थी, रेलवे का चार्ट, जो बाहर लगता है, वह भी गलत लगा हुआ था, रेलवे में accidents बहुत हो रहे हैं, आदि। अगर मैं सबसे पहले रेलवे की सेफ्टी की बात करूं, एक्सीडेंट की बात करूं, तो 1965-70 का जो डेटा है, उसकी तुलना में बहुत कम एक्सीडेंट हुए हैं। लेकिन आज के समय में जब कि हमें modern facilities मिल गई हैं, तब भी एक्सीडेंट का होना बहुत बड़ी चुनौती का विषय है। इससे जहां एक तरफ एक व्यक्ति की मौत होती है, वहीं दूसरी तरफ देश की बहुत सारी properties का नुकसान भी होता है। यह ऐसा नुकसान होता है, जिसके कारण देश के ऊपर बर्डन पड़ता है।

सर, अगर 2007-08 का डेटा लिया जाए, तो उसमें 8 आमने-सामने accidents, 100 के करीब डीरेलमेंट, लेवल क्रॉसिंग पर 76 accidents, 5 फायर accidents और 7 miscellaneous accidents हुए। कुल मिला कर 196 accidents 2007-08 में हुए। इसी तरह 2008-09 में 13 आमने-सामने accidents, 85 डीरेलमेंट, लेवल क्रॉसिंग पर 69 accidents, 3 फायर accidents और 7 miscellaneous accidents हुए। कुल मिला कर 170 accidents 2008-09 में हुए। 2009-10 का जो डेटा है, जिसमें जनवरी तक का डेटा है, जनवरी के बाद के एक्सीडेंट के बारे में डिसप्ले नहीं हुआ है, जब कि जनवरी के बाद काफी accidents हुए हैं और काफी मौतें हुई हैं। 2009-10 में 9 आमने-सामने accidents, 59 डीरेलमेंट, लेवल क्रॉसिंग पर 54 accidents और 2 फायर accidents हुए हैं। कुल मिला कर 124 accidents

2008-09 के जनवरी तक हो चुके हैं। इसलिए रेलवे में सफर करना एक बहुत असुविधा का कारण भी बनता जा रहा है। इसी तरह, आज माननीय मंत्री जी ने नहीं माना, जब एक प्रश्न में आया था कि ट्रेनों में जो डकैती और लूट-पाट हो रही है, जिसके कारण रेलवे की सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह लग गया है और जो रेल में सफर करते हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सबसे बड़ी चिंता की बात तब पैदा होती है, जब रेल की सुरक्षा में लगे हुए लोग ही यात्रियों को लूटते हैं, यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उस समय, जैसा कि मैंने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय रेल की बात बताई है, उसके ऊपर एक दाग लगता है। सर, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि सबसे पहले रेल में यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए।

सर, Anti Collision Device (ACD) लगाने की बात हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। Konkan Railway Corporation Limited ने स्वदेशी device बनाया था, लेकिन वह अब तक क्यों नहीं लगा? अभी तक इसका जवाब सदन को और देश के लोगों को नहीं मिला है।

(2a/MP पर क्रमशः)

MP/2A/2.40

श्री अविनाश राय खन्ना (क्रमागत) : माननीय मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि 1700 किलोमीटर Southern और Western Railway पर जो गाड़ियां चलती हैं, उन पर Anti Collision Device लगाया जाएगा, लेकिन अभी तक देश को इंतज़ार है कि कब रेल पर यह instrument लगेगा ताकि रेल accident-free हो सके।

महोदय, रेलवे की unmanned crossings पर बहुत सारे accidents होते हैं लेकिन अभी पार्लियामेंट में जो question आया था, उस समय जिस ढंग से मंत्रालय ने जवाब दिया, वह satisfy करने वाला जवाब नहीं था। Unmanned crossings पर इतने accidents हो रहे हैं, उनको manned करने की प्रक्रिया रेल मंत्रालय को करनी चाहिए। जब हमारे नेता श्री

अरुण जेटली ने एक प्रश्न उठाया था, उस समय भी आप उसका उत्तर सही नहीं दे पाई थीं। आपने MPs के ऊपर वह डाल दिया कि बीस-बीस लाख या एक project MP ले, तो उसके बाद रेल सोचेगी। रेल मंत्रालय अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, क्योंकि उन unmanned crossings पर बहुत से accidents होते हैं, बहुत लोगों की जानें जाती हैं और बहुत सी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, इसलिए उनकी सेफ्टी का प्रबंध रेलवे को करना चाहिए। उनको फेज़वाइज़ manned करना चाहिए या alternative ढंग से करना चाहिए। महोदय, मुझे भी कई बार विदेशों में जाने का मौका मिला है। वहां पर ऐसा सिस्टम है कि जब ट्रेन आती है, तो फाटक automatically बंद हो जाता है और जब ट्रेन चली जाती है, तब वह फाटक खुल जाता है। क्या रेल मंत्रालय इस सिस्टम पर विचार कर सकता है कि automatic रेल फाटक लग पाएं? अगर नहीं, तो क्यों, ऐसा जवाब यह सदन आपसे चाहता है।

महोदय, देश में बहुत सारी जगहें रेल से unconnected हैं। हमारे प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सपना देखा था कि कश्मीर तक रेल को शुरू किया जाएगा और उस पर बहुत काम भी हुआ, लेकिन आज देश के बहुत से हिस्से हैं, जो आज भी रेलवे से connected नहीं हैं। यहां पर उतनी connectivity नहीं है, इसलिए उन प्रदेशों का, उन जगहों का विकास नहीं हो पाता, इसलिए मैं रेल मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि आप इन जगहों पर expansion करें। महोदय, मैंने सुना है कि आज़ादी से पहले होशियारपुर से पेशावर तक ट्रेन जाती थी लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि लोग आगे जा रहे हैं और हम पीछे हो गए। अब होशियारपुर last station है। मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट की है, मैं जब लोक सभा में MP था, उस समय भी हर बजट स्पीच में बोलता था, हर बार question raise करता था कि होशियारपुर से रेलवे को extend किया जाए। यह bordering district है, साथ में हिमाचल पड़ता है और tourist की दृष्टि से यह एक ऐसा स्थान है कि अगर रेल का expansion किया जाए तो रेलवे को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, लेकिन हर question के जवाब में यह आया कि manpower नहीं है, revenue की कमी होगी, लेकिन कभी भी try करके नहीं देखा गया। मैं

आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जहां connectivity है, वहां DMU रेल चलाने की कुछ सुविधाएं अगर दी जाएं तो जनता को बहुत लाभ हो सकता है। उदाहरण के तौर पर होशियारपुर से जम्मू तक rail connectivity है। होशियारपुर से दिल्ली तक वाया जालंधर rail connectivity है, लेकिन वहां से कोई भी ट्रेन न जम्मू को जाती है, न दिल्ली के लिए आती है। मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि इसमें आपका कोई additional खर्च नहीं आएगा, जो ट्रेन जालंधर तक आती है, आप उसकी सिर्फ 30-35 किलोमीटर आगे होशियारपुर तक connectivity कर सकते हैं। होशियारपुर एक इंडस्ट्रियल टाउन डेवलप हुआ है और वहां अच्छी-अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं।

महोदय, साथ ही बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म हैं, अगर उनको देखा जाए तो वे डिब्बों से इतने नीचे होते हैं कि यदि किसी विकलांग, बुज़ुर्ग या महिला को किसी प्लेटफॉर्म पर उतरना हो, तो बहुत मुश्किल होता है।

(2B/SC पर क्रमशः)

-mp/sc/2.45/2b

श्री अविनाश राय खन्ना (क्रमागत) : कई बार लोग गिर जाते हैं, accidents होते हैं। ऐसे कई platforms हैं, जो, जितनी लम्बी ट्रेन है, उतने लम्बे नहीं हैं। ऐसी जगह पर एक passenger को उतरना कितना मुश्किल होगा, यह आप समझ सकते हैं। आप रेल मंत्री हैं, आपने भी रेल में सफर किया होगा, आपको मालूम ही होगा कि अगर किसी को बिना platform के कहीं उतरना पड़ जाए, तो कम से कम दो लोगों की सहायता की जरूरत होगी, तब वह नीचे उतर सकता है। मेरा अनुरोध है कि उन platforms को extend किया जाए, ताकि लोग रेलवे का पूरा फायदा उठा सकें। कई बार लोग इसीलिए रेल में नहीं चढ़ते कि platform है नहीं, तो हम चढ़ेंगे कैसे। इसी तरह एक platform को दूसरे platform से connect करने के लिए कई जगह पर footbridge ही नहीं हैं। इसलिए सभी footbridge बनाए जाएं, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। माननीय रेल मंत्री महोदया, आपको याद होगा, हमारे एक माननीय सदस्य ने इसी सदन में

एक प्रश्न उठाया था कि जो लम्बी दूरी की ट्रेनें चलती हैं, जिनमें लोग 24 घंटे, 36 घंटे सफर करते हैं, उनमें कोई भी medical facility नहीं होती। अगर आप बसों की बात करें, ट्रकों की बात करें, यहां तक कि जो टैक्सियां चलती हैं, उनकी बात करें, तो ऐसे छोटे-छोटे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी first aid देने का provision होता है। रेलवे, जो कम से कम 1000-1500 लोगों को लेकर चलती है, उनके साथ अगर कभी emergency हो जाए, तो कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि उन्हें medical facility दी जाए। हां, आपके लोग इतना जरूर करते हैं कि जब कोई emergency होती है तो एक announcement होती है कि गाड़ी में अगर कोई डॉक्टर है तो फलां डिब्बे में चला जाए। वैसे तो कोई जाता नहीं है, अगर चला भी जाए तो medicine न होने के कारण, कोई facility न होने के कारण वह कैसे इलाज कर पाएगा? इसलिए आपको इस संबंध में सोचना होगा कि सारे passengers को ध्यान में रखते हुए उनके लिए medical facility प्रोवाइड की जाए। इसी तरह से pantry की समस्या है। बहुत सी ट्रेनों में pantry car न होने के कारण लोगों को असुविधा होती है। ट्रेन जब platform पर जाकर रुकती है तो वहां पर बहुत rush होता है, लोगों के लिए वहां पर उतरकर कुछ खाने के लिए लाना बड़ा मुश्किल होता है। सर, लोगों ने पेमेंट करके खाने के लिए कुछ खरीदना होता है इसलिए मेरा अनुरोध है कि उनके लिए pantry की सुविधा ज्यादा से ज्यादा extend की जाए। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस और व्हील ऑन पैलेस - ये सब ऐसी ट्रेनें हैं जिनमें बहुत सारे foreigners सफर करते हैं, लेकिन ऐसी ट्रेनों में जब खाना अच्छा नहीं मिलता तो उससे देश के गौरव को ठेस पहुंचती है। मुझे याद है, मैं एक बार अमृतसर शताब्दी से सफर कर रहा था तो उस समय मेरे खाने में एक कंकड़ आया। जब मैंने उन लोगों को बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि आप खाना बदल सकते हैं। सर, बात खाना बदलने की नहीं है, जिस ट्रेन को विदेश से आए हुए लोग prefer करते हैं कि इस ट्रेन में सफर किया जाए, इसमें सफर करना comfortable होगा, उस ट्रेन में अगर खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो इस देश के गौरवमयी इतिहास को ठेस पहुंचेगी। महोदया, इस संबंध में मैं आपको

सजेशन देना चाहता हूं कि जो खाना परोसा जाता है, आप उसको परोसने से पहले चेक करने का provision बनाइए ताकि रेलवे में अच्छा खाना मिले। इसके अलावा रेलवे में बहुत सारी vacancies खाली पड़ी हैं। कृपया उन vacancies को भरिए क्योंकि आज तक जितने भी accidents हुए हैं, उनमें से बहुत से accidents के कारण यह बताए गए हैं कि वहां पर manpower की कमी थी। अगर हम ड्राइवर से ज्यादा काम लेंगे, गार्ड से ज्यादा काम लेंगे तो इसके कारण वह अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से perform नहीं कर पाएगा, जिसके कारण accidents हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जितनी भी vacant posts हैं, उनको भरा जाए और जो posts भरने का सिस्टम है, वह भी transparent होना चाहिए। लोगों को विश्वास हो कि यहां पर बिना पैसे दिए हमें नौकरी मिल सकती है। महोदय, जो आम passengers गाड़ियों में सफर करते हैं उनके संबंध में एक बात मैं और कहना चाहता हूं - इसमें ज्यादा पैसा या बजट खर्च करने की जरूरत नहीं है - आप अपने स्टाफ के behaviour को ठीक कीजिए। जितने लोग गाड़ियों में सफर करते हैं, उनके साथ आपके टीटी जो व्यवहार करते हैं, वह अशोभनीय है। कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ जो पुलिस चलती है, उनका व्यवहार भी ज्यादा अच्छा नहीं होता है।

(2सी-एमसीएम पर क्रमशः)

SC/MCM-KS/2C/2-50

श्री अविनाश राय खन्ना (क्रमागत) : तो मैं माननीया रेल मंत्री जी से निवेदन करुंगा, मैंने अपने क्वेश्चंस में कुछ सुझाव दिए हैं, जहां पर बिना पैसे खर्च किए रेलवे अपना विस्तार कर सकती है। आनन्दपुर साहिब पंजाब के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया में कहीं भी बैठे हुए लोगों के लिए एक गौरवमयी स्थान है, वहां पर सिख पंथ का निर्माण हुआ था और पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। लेकिन अफसोस की बात है कि आजादी के 63 साल बाद भी इन दोनों स्थानों के लिए कोई भी ट्रेन आज तक नहीं चलाई गई है। बहुत बार सभी

लोगों ने, खासकर के पंजाब के लोगों ने आपसे निवेदन किया था कि ट्रायल के रूप में बेशक आप हफ्ते में एक ट्रेन या महीने में दो दिन ट्रेन आनन्दपुर साहिब से पटना साहिब के लिए चला दें, तो बहुत बड़ा लाभ उन यात्रियों को होगा जो पंजाब में आनन्दपुर साहिब और अमृतसर में घूमने आते हैं। मेरी एक प्रपोजल के आधार पर अमृतसर को आनन्दपुर साहिब से जोड़ने के लिए एक बजट में एनाउंस हुआ और सर्वे हुआ। इसके बाद मैं लोक सभा से एम0पी नहीं रहा और जब मैं राज्य सभा में आया तो मैंने यहां क्वेश्चन किया कि उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ? मुझे इसका जवाब आया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। जवाब में उन्होंने यह कह कर बात टाल दी कि अगर इसमें 50 परसेंट राज्य डाले और 50 परसेंट रेलवे डालेगा, तब हम यह प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। यह रेलवे का काम है, रेलवे की प्रापर्टी है। अगर राज्य पैसा डालेगा तो क्या उससे होने वाला प्राफिट आप राज्यों को देंगे? यह बात ठीक नहीं है, यह न मानने वाली बात है। कोई भी राज्य कभी भी रेलवे के लिए या उसके विस्तार के लिए, क्योंकि यह रेलवे का अपना प्रोजेक्ट है, रेलवे के विस्ताव से आपकी आमदनी बढ़ेगी, तो कोई भी राज्य उसमें शेयर नहीं करेगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जैसा बजट में माननीय लालू प्रसाद जी ने माना था कि अमृतसर से आनन्दपुर साहिब रेलवे कनेक्टिविटी हो गई है, सिर्फ 33 किलोमीटर का जो एरिया है, वहां पर रेल बिछानी है, उससे आगे रेल बिछी हुई है। कृपया उस रेलवे प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए।

मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि होशियारपुर से एक डी0एम0यू0 चलाई जाए, क्योंकि जहां पर अमृतसर से बिजनेस कनेक्टिविटी बहुत है। भटिंडा के चार पांच सौ हॉकर्स हैं और वहां सामान बेचने का काम करते हैं, उन्होंने मुझे दुखी होकर बताया कि रेलवे ने उनका काम बंद करवा दिया है, सिर्फ भटिंडा का। 9 स्टेशनों से उनकी कम्पलेंड आई थी कि उन्होंने पैसे जमा नहीं कराए। भटिंडा के सभी वेंडर्स पैसे लेकर आपके अधिकारियों को मिले। उनको बताया गया कि आप पहले सारे पैसे जमा कराओ, तब आपसे बात करेंगे।

तब वे पैसे लेकर गए, उनके पैसे जमा नहीं हुए। लेकिन आज भी भटिंडा में जितने, चार-पांच सौ, वेंडर्स हैं, वे बेचारे बेकार होकर बैठे हैं। वे कोई एजिटेशन भी नहीं कर रहे हैं। उनमें से दो-तीन डेली दिल्ली आते हैं, आपके अधिकारियों से टाइम लेते हैं, कोई किसी के पास भेजता है, कोई उनको किसी और के पास भेज देता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उन लोगों का रोजगार शुरू कराया जाए। ये लगभग 500 वेंडर्स हैं, उन लोगों के लिए जो भी सुविधा हो वह उनसे पैसे जमा कराकर शुरू करायी जाए, नहीं तो सब के साथ एक व्यवहार किया जाए, चाहे वे अम्बाला के हों, चाहें वे जालंधर के हों या किसी और स्थान के हों। वहां के ये लोग आज भी रो रहे हैं। वे सिर्फ धरने पर इसीलिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि आपने कहा था कि ट्रेन इसलिए लेट होती हैं कि लोग ट्रेन रोक देते हैं। अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो लोगों के पास क्या चारा रहेगा, और वे लोग इस बात पर नहीं उतरें, आपकी ट्रेनें न रोकें, आपकी ट्रेनें चलती रहें। तो उन लोगों के लिए आपको कुछ करना होगा।

मैं गुड्स ट्रेन्स के बारे में भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कई स्टेशनों का दौरा किया। अगर कोई व्यापारी आधा घंटा भी अपना माल देरी से उतारता है तो आप उस पर डेमरेज डाल देते हैं। लेकिन वहां आप उनको क्या सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, कभी जाकर देखिए। यहां दफ्तर में बैठकर सिर्फ अपनी रिपोर्ट्स को देखकर किसी सवाल का जवाब मत दो, बल्कि वहां किसी अफसर को देखने के लिए भेजें कि वहां क्या सुविधा है। मैं कपूरथला गया, जहां पर आपकी गुड्स ट्रेन्स खड़ी होती हैं, वहां पर मजदूरों को पीने के लिए पानी नहीं है।

(2d/GS पर क्रमशः)

GS-KGG/2D/3.55

श्री अविनाश राय खन्ना (क्रमागत) : वहां पर लाइट का कोई प्रावधान नहीं है, वहां के प्लेट फार्म पर लोग सामान उतारते हैं, वह भी खस्ता हालत में है। होशियारपुर में जहां पर रेलवे की

गुड्स ट्रेन्स खड़ी होती हैं, जब से वहां पर लगे शेड उठाए गए हैं, लोगों ने रेलवे से अपना सामान बुक करवाना बंद कर दिया है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस डाटा को आप वैरिफाई करवा लेना। रेलवे सामान को ले जाने का और लाने का एक सस्ता साधन है। आप इसको वैरिफाई करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वहां पर लोगों ने अपना सामान लाना और ले जाना बंद कर दिया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस बात को वैरिफाई करके लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाइए। दफ्तर में बैठकर, एयर कंडीशंड कमरों में बैठकर रिपोर्टें तैयार करके अगर सदन में इस तरह से जवाब देंगी तो, आपके जवाब को वैरिफाई करके, हो सकता है कि मुझे प्रिवलेज़ मोशन भी मूव करना पड़े, अगर वे असत्य हुए तो।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हम इस देश के वासी हैं। हम नहीं चाहते हैं कि सरकार का कोई नुकसान हो। रेलवे की बहुत सी प्रॉपर्टी, बहुत से वृक्ष, बहुत से पेड़ ऐसे ही कटे पड़े हैं, लेकिन कभी भी रेलवे ने चिंता नहीं की है कि उनको उठाकर, बेचकर रेलवे का रेवेन्यु बढ़ाया जाए। माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा, आपका जो समय है, वह आजकल वेस्ट बंगाल में ज्यादा लग रहा है, यह इतना बड़ा मंत्रालय है, यह गौरव का मंत्रालय है, इसलिए आप पूरा टाइम इस मंत्रालय को देकर इसकी जो भी कमियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश करिए, अन्यथा अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। मैंने एक अखबार में पढ़ा था, टाइम्स आफ इंडिया के पेपर में लिखा था, The Ministry of Railways needs a full time Minister. मुझे पता नहीं, उन्होंने ऐसे क्यों लिखा। वे चाहते हैं कि एक पूरे टाइम का मिनिस्टर रेलवे को मिले, ताकि जितनी भी रेलवे की समस्याएं हैं, वे हल की जा सकें। मैं ज्यादा न कहते हुए, फिर पाइंटिड बात आपसे कह रहा हूं। ...(व्यवधान)... मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो पाइंटिड बात है, जो रेलवे का इतिहास है। ...(व्यवधान)...जो रेलवे की हिस्ट्री है, उसको देखते हुए, रेलवे एक्सीडेंट-फ्री हो, रेलवे में सफर करना आसान हो, यात्रियों की इंश्योरेंस का जिम्मा भी रेलवे ले, तो उससे यात्रा करने वाले लोगों में एक विश्वास पैदा होगा कि वे रेलवे में यात्रा करेंगे और यदि कोई

बात होती है, तो वे कम्पनसेट भी आराम से हो जायेंगे। इन बातों को कहते हुए, मैं माननीया रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि मैंने जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कही है, आज आप कुछ न कुछ अनाउंसमेंट, कुछ न कुछ बात उसके बारे में कहेंगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

श्री नंदी येल्लैया (आन्ध्र प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, रेल बजट के बारे में अभी माननीय सदस्य ने अपने विचार प्रकट किए । मैंने रेल बजट पर कई बार अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसा कि माननीया रेल मंत्री जी को मालूम है, मैं जब लोक सभा में था, तेलगांना का जो एरिया है, उसमें मेढक डिस्ट्रिक्ट है और वहां से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इलेक्शन जीता था। वहां की डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के एक-दो बुजुर्ग थे, मिस्टर बागा रेड्डी, मदन मोहन और मैं भी था, वहां से मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट चुनने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधान मंत्री बनीं थीं, तो हम लोगों ने उनके पास जाकर अनुरोध किया कि यह बैकवर्ड एरिया है, इसको फारवर्ड एरिया बनाने के लिए रेल की जरूरत है। वहां की डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और जितने भी इलेक्टिड मेम्बर्स थे, उन सबकी रिक्वेस्ट के बाद मैडम ने आठ किलो मीटर रेलवे लाइन खुलवाई। लेकिन रेलवे लाइन खुलने के बाद, उस वक्त हमारे मल्लिकार्जुन आन्ध्र प्रदेश की ओर से स्टेट मिनिस्टर थे, कुछ साल चलने के बाद, फिर सरकार बदल गई और दूसरी सरकार आई, फिर उसको क्लोज किया गया।

(2E/ASC पर जारी)

ASC-TDB/2E/3.00

श्री नंदी येल्लैया (क्रमागत) : सर, मैं मैडम से यह अनुरोध करूंगा कि जिस वक्त नई रेल लाइन बनाई जाए, उस वक्त यह जांच लिया जाए कि उसका क्या सिस्टम है। इस प्रकार की तमाम जांच होनी चाहिए थीं, लेकिन वैसा नहीं किया गया और बाद में 8 किलोमीटर की पूरी लाइन को क्लोज कर दिया गया। महोदय, मैं मैडम से यह भी अनुरोध करूंगा कि आपको काफी

जानकारी है और आप रेलवे में काफी तरक्की करने के बारे में सोचती रहती हैं। मैं यह सोचता हूं कि भारत के अंदर कितने बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उनकी जानकारी रेलवे बोर्ड को होनी चाहिए। आज-कल बैकवर्ड एरिया और फॉरवर्ड एरियाज़ में कोई फर्क नहीं किया जाता है। ऐसा होता है कि *'जिसकी लाठी उसकी भैंस'।* मैंने यह बात जाफ़र शरीफ साहब से भी कही थी। मैंने उनसे यह कहा कि साहब, यह क्या हो रहा है? तो उन्होंने जवाब दिया कि आप भी मिनिस्टर बनो, तब अपने हिसाब से काम करना। मैंने कहा कि डेमोक्रेसी का यह ढांचा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आज मैडम से यह कहूंगा कि बैकवर्ड एरिया कौन सा है और फारवर्ड एरिया कौन सा है, इसके लिए आपके पास एक क्राइटेरिया होना चाहिए। उस एरिया से एक MP बदल सकता है और उसकी जगह दूसर MP आ सकता है। आपके पास एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि यह बैकवर्ड एरिया है और इसे फारवर्ड करने के लिए कुछ करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तीन साल पहले यहां पर बैकवर्ड एरिया का सर्वे हुआ था। यहां मनोहराबाद से लेकर कोत्तपल्लि वाया सिद्धिपेट, दुब्बाका आदि बैकवर्ड एरिया का सर्वे भी हो चुका है, लेकिन आज तक उस पर काम नहीं हुआ है। हमने कई बार इस सदन में इस विषय को उठाया है। जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं, हम तो राज्य सभा में MP हैं, लेकिन जो लोग लोक सभा में MP हैं, जब वे अपने एरिया में जाते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि आप लोगों ने दिल्ली में जाकर लोक सभा में बैठने के बाद, राज्य सभा में बैठने के बाद, अपने एरिया के लिए क्या किया है? हमें आवाम को इन सारी बातों का जवाब देना पड़ता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि बैकवर्ड एरिया और फारवर्ड एरिया का एक ढांचा होना चाहिए, एक मास्टर प्लान होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जैसे साउथ सैंट्रल रेलवे की प्रॉपर्टी है और उसमें ज्यादा जमीन है, जिस तरह से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, उसी तरह से कुछ लोग जमीन पर कब्जा करने में स्पेशलिस्ट होते हैं और उसमें हर पार्टी के लोग होते हैं। मैं मैडम को यह भी बताना चाहूंगा कि जैसे मल्काजगिरी का म्युनिसिपल एरिया है, वह मेरी पार्लियामेंट्री ओल्ड

कांस्टीट्युएंसी है, वहां पर लोग बसे हुए हैं, आप उनके साथ क्या करने वाले हैं? क्या आप उस एरिया को डिमॉलिश कराने जा रहे हैं? क्या आप उनको वहां से रिमूव कर सकते हैं? यह नामुमकिन है। यदि आप ऐसा करोगे, तो वहां पर दूसरी पार्टियों के लोग आ जाएंगे, लॉ एंड आर्डर की प्राब्लम हो जाएगी और फायरिंग हो जाएगी, इस तरह की तमाम बातें हैं। मेरा यह कहना है कि रेलवे की जो प्रॉपर्टी है, उसको आप रेगुलराइज़ कीजिए, उसको नोमिनल रेंट पर दीजिए। आप उसको रेगुलराइज़ नहीं कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन रेलवे की जमीन पर इन्क्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि या तो रेलवे की प्रॉपर्टी को उस जोन के अंदर रखिए या फिर उसे रेगुलराइज़ करिए। यह एक अहम सवाल है।

दूसरी बात यह है कि हमारे साथी बहुत कम रेल की यात्रा करते होंगे..(व्यवधान).. आप करते हैं? ..(व्यवधान)....मैजोरिटी लोग तो नहीं करते हैं, क्योंकि MP के पास समय कम रहता है। उसको कई कमेटीज एटेंड करनी पड़ती हैं, जिला परिष्ाद् की कमेटीज़ अटेंड करनी पड़ती हैं और कभी उसे पार्टी मीटिंग में जाना पड़ता है, जिसके लिए उसे प्लेन का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए जो कॉमन मैन हैं, गरीब लोग हैं और जो वीकर सैक्शन से हैं, उनके लिए ट्रेन के सिवाय दूसरा कोई जरिया नहीं है। ट्रेनों में इतना गंदा भोजन दिया जाता है, जिससे फूड पाइज़निंग हो सकती है। इस तरह हमारे यहां ट्रेनों में 70 प्रतिशत लोगों के लिए खाने की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं यह कहता हूं कि केटरिंग सिस्टम इस प्रकार का होना चाहिए, भले ही आप सामान का रेट बढ़ाएं, लेकिन भोजन अच्छा खिलवाइए। ममता जी के जमाने में भोजन में फिश भी खिला सकते हैं, क्योंकि बंगाली लोग ज्यादा फिश खाते हैं। ...(व्यवधान)..मैं यहां पर वेजिटेरियन और नॉन वेरिटेरियन की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा यह कहना है कि आप केटरिंग के रेट बढ़ाइए, लेकिन अच्छा भोजन दीजिए। सभी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ट्रेन में भोजन अच्छा नहीं होता है। इसी तरह से हमारे साउथ सैन्ट्रल रेलवे में RPF की बहुत शॉर्टेज है। मैंने इस बात का जिक्र स्टेंडिंग कमेटी में भी किया था कि वहां पर रिक्रूटमेंट बहुत समय से रुका हुआ है क्योंकि पहले तो RPF के

बारे में काफी शिकायतें हैं कि ये लोग ट्रेन में रहते ही नहीं है, ये कहां रहते हैं भगवान जाने। लेकिन इनके बारे में काफी शिकायते हैं। जहां-जहां पर शार्टेज है, वहां पर वेकेंसीज को भरना चाहिए, वे नहीं भरी जा रही हैं, इनको जल्दी भरा जाना चाहिए। आज रेलवे स्टेशन्स पर कितने मासूम लोग घंटो तक ट्रेन के लिए प्रतीक्षा करते हैं।

(2F/LP पर क्रमशः)

LP/KLS/3.05/2F

श्री नंदी येल्लैया (**क्रमागत**) : वहां पर बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है, वे लोग नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए वहां पर बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। दो-तीन घंटे तक ट्रेन का इंतजार करने के लिए यह व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेन कभी लेट भी हो सकती है। मैं समझता हूं कि रेलवे एक बड़ी ऑटोनॉमस बॉडी है। वह एक बहुत बड़ा समुद्र है, वहां पर क्या होता है, यह किसी को मालूम नहीं पड़ता है, इसलिए मैडम, मैं चाहता हूं कि आप बैकवर्ड एरिया का खयाल रखिए। मैं समझता हूं कि मनोहराबाद, जिसके बारे में मैंने एक बार नहीं, कई बार बोला है कि मनोहराबाद टू कोट्टापल्ली, करीमनगर बैकवर्ड एरिया है, जहां सिद्दिपेट एरिया एक डिवीजन है, एक हेडक्वार्टर है, वहां पर कई राइस मिल्स हैं, आपके बहुत से बिजनेस सेंटर हैं, लेकिन उनको रेल में यात्रा करना नसीब नहीं है। मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं पांच बार लोक सभा में था, पांच बार मामूली बात नहीं है, मैंने आठ बार कंटेस्ट किया है, उसमें से पांच बार इलेक्ट हुआ हूं, एक बार पांच हजार वोट से हार गया था, अभी सैकिंड टाइम सोनिया गांधी जी की वजह से, उनकी मेहरबानी से दो दफा राज्य सभा में हूं, इसीलिए मैडम, मैं चाहता हूं..(व्यवधान)..ममता जी की मेहरबानी अलग है, सोनिया गांधी की मेहरबानी अलग है। वे नेशनल लीडर हैं, आप मैडम और सोनिया गांधी को कंपेयर मत कीजिए..(व्यवधान)..यहां रेलवे के बारे में बोल रहे हैं। वे बहुत होशियार महिला हैं।..(व्यवधान).आप क्या बोल रहे हैं..(व्यवधान)...देखिए, मैं चेयर की तरफ एड्रेस कर रहा

हूं, मैं आपकी तरफ एड्रेस नहीं कर रहा हूं..(व्यवधान)..हमारी मिनिस्टर साहिबान चाहे पोलिटिक्स में हों, देश में हों या कहीं ओर हों या रेलवे में, मैंने अभी सुना है कि उनकी पूरी फोर्स बंगाल जाती है, वे खामोश नहीं बैठती हैं, बहुत कुछ डिस्पोजल कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। उनके अच्छा काम करने के लिए हम उनको बधाई देते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि ..(व्यवधान)..

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : सब इधर से ही करते हैं, उधर से नहीं करते हैं।

श्री नंदी येल्लैया : मैडम, इधर से करते हैं, उधर से नहीं करते हैं, यह तो अंदर की बात है। यह सभी को मालूम है, क्या हमको मालूम नहीं है, चाहे कहीं से भी हो, मगर आप करती जरूर हैं, काम होता रहता है। मैं चाहता हूं, मेरी गुजारिश है, मैं पांच बार सदस्य रहा हूं, मैं आपसे एक छोटा सा टुकड़ा मांग रहा हूं कि मनोहराबाद टू सिद्दिपेट, जो आपकी रेलवे लाइन है, जो बैकवर्ड एरिया है, बिजनेस सेंटर है, आप यहां रेलवे लाइन दीजिए। आप कंजूसी मत कीजिए, जरा हमारा हाथ बंटाइए। इतना ही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, शुक्रिया।

(समाप्त)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी। क्योंकि मैं ममता जी का व्यक्तिगत समर्थक हूं, हम उनके साथ प्रोग्रेसिव एलायंस में भी रहे हैं, इसलिए मैं बजट का विरोध करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं जानता हूं कि ममता जी डायनामिक हैं, लेकिन जिस कदम पर विभाग चल रहा है, उसकी आलोचना करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं और कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। श्रीमन्, यह बात सही है कि आज यातायात के लिए रेल व्यवस्था सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। विश्व में शायद ही कोई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में सुधार नहीं किया गया, उसकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया गया, तो वह व्यवस्था कहीं चरमरा न जाए, इसकी तरफ भी हमें देखना पड़ेगा। आज हमें इस पर भी सोचना पड़ेगा कि इतने सालों के बाद, जब विश्व में दो सौ, ढाई सौ किलोमीटर पर ऑवर की स्पीड से ट्रेन्स चल रही हों, हमारे हिंदुस्तान में आज भी ट्रेन्स की स्पीड पचास से

सत्तर किलोमीटर से ऊपर नहीं बढ़ी है। आजादी के तिरसठ साल बाद आज भी हम रेल व्यवस्था को पचास से सत्तर किलोमीटर से ऊपर नहीं पहुंचा पाए है। श्रीमन्,"लखनऊ मेल", बड़ी वी.आई.पी. ट्रेन कहलाती है, यह लखनऊ से दिल्ली के बीच चलती है, यह वी.आई.पी. ट्रेन नौ घंटे में लखनऊ से दिल्ली पहुंचाती है। यह जो "लखनऊ मेल" ट्रेन है, यह चार सौ किलोमीटर नौ घंटे में पहुंचाती है। आप जोड़ लीजिए कि कितने किलोमीटर पर ऑवर पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि ममता जी इस व्यवस्था पर विचार करें कि अगर रेलवे की स्पीड बढ़ानी है, तो कुछ सोचना होगा। यह सही है कि हमें कहना पड़ रहा है कि रेलवे में एक्सीडेंट्स बहुत अधिक हुए हैं। पिछले दस साल में रेलवे के करीब 3000 एक्सीडेंट्स हुए हैं। एक पूरा विवरण दिया हुआ है कि दस साल में 3000 एक्सीडेंट्स हुए हैं और करीब दस हजार लोग उनमें हताहत हुए हैं। श्रीमन्, खाली कम्पेनसेशन देना अगर हमने अपना कर्तव्य समझ लिया है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। कैग की रिपोर्ट आई है।

कैग की एक रिपोर्ट है कि पिछले तीन साल में रेलवे को सुरक्षा पर जितना पैसा दिया गया, रेलवे उस पैसे को खर्च नहीं कर पाई। (akg/2g पर क्रमागत)

AKG/2G/3.10

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल (**क्रमागत**) : ममता जी, आप अपने विभाग में खुद विचार करें, आप सप्लीमेंटरी बजट पेश कर रही हैं, आज आपने क्वैश्चन ऑवर में कहा कि हम सुरक्षा पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, अगर आप ध्यान दे रही हैं, तो accidents क्यों बढ़ रहे हैं? हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। केवल compensation देना अगर हमने अपना कर्त्तव्य समझ लिया है, तो मैं समझूँगा कि व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है और कहीं-न-कहीं कमी हो रही है। मैं चाहूँगा कि अगर दिल्ली में ज्यादा टाइम दिया जाए, तो इस पर ज्यादा अच्छा विचार होगा और व्यवस्था में कहीं-न-कहीं सुधार जरूर होगा।

श्रीमन्, कह दिया जाता है कि infrastructure की कमी है, ट्रेनें बहुत बढ़ गई हैं। आप क्यों नहीं infrastructure पर पैसा खर्च करतीं? Infrastructure पर पैसा खर्च करने से कोई मना तो नहीं करता! हमें चाहिए कि हम infrastructure पर पैसा खर्च करें और इस व्यवस्था को और सुधारें। आज सुरक्षा का हाल यह है कि जब आदमी रेल में चलता है, तो उसे लगता है कि हम सुरक्षित हैं कि नहीं, हम गंतव्य स्थान पर पहुँच पाएँगे या नहीं। यह ठीक है, आपने कह दिया कि GRP राज्यों के जिम्मे है, हम 50-55 प्रतिशत पैसा देते हैं, लेकिन RPF तो रेलवे का organization है। हम क्यों नहीं दोनों का तालमेल करके रेलवे की सुरक्षा को बढ़ाते? आज लूटपाट की घटनाएँ बढ़ रही हैं। मैंने सुबह ही कहा कि कोलकाता से या बिहार से जितनी ट्रेनें उत्तर प्रदेश आती हैं, कोई भी ट्रेन समय से नहीं पहुँचती है। आखिर उसका कारण क्या है? आपने ठीक कहा कि तमाम राजनीतिक दल बंद का आह्वान कर देते हैं, लेकिन सालों भर तो बंद का आह्वान नहीं रहता है। अगर वहाँ delay होती है, तो इसका कोई reason होगा।

श्रीमन्, मैंने इसको भी अच्छा नहीं समझा, माओवाद के आतंक में जिस तरह ट्रेनें रोक दी गईं, वह कोई बहुत अच्छा निर्णय नहीं था। आज माओवादी कह दें कि हम इस एरिया में नहीं चलें, तो क्या उस एरिया में पूरे मकान ही खाली करा दिए जाएँगे? माओवादियों से संघर्ष करने के लिए एक कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। माओवादियों से संघर्ष करना, नक्सलवाद से संघर्ष करना सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर हम नक्सलवाद को समर्थन देंगे, तो हम नक्सलवाद का विरोध क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश में तीन जिलों में नक्सलवाद था। हमारी मुख्य मंत्री जी ने तीनों जिलों में नक्सलवाद समाप्त कर दिया। सोनभद्र, मिर्जापुर और भदोही, उत्तर प्रदेश के ये तीनों जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। हमने वहाँ कड़ाई भी की, हमने विकास भी किया और नक्सलवाद को समाप्त किया। आखिर बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ या झारखंड, आन्ध्र प्रदेश, जहाँ पर नक्सलवाद है ... (व्यवधान) ... इसमें उड़ीसा भी है, उन

सब जगह पर हम क्यों नहीं कोई व्यवस्था करते, क्यों नहीं निर्णय लेते? जब इस सदन में internal security पर बात आएगी, तब इन चीजों को रखा जाएगा।

श्रीमन्, मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है, लेकिन सबसे ज्यादा उपेक्षा उत्तर प्रदेश की होती है। उसका कारण है कि रेल मंत्री ज्यादातर या तो बंगाल से बने या बिहार से बने। रेल विभाग ने उत्तर प्रदेश को उपेक्षित कर दिया है। हमारी याद्दाश्त में पंडित कमलापति जी उत्तर प्रदेश से रेल मंत्री थे। उस जमाने में ... (व्यवधान) ... लाल बहादुर जी तो शुरू में रहे। उसके बाद पंडित कमलापति उत्तर प्रदेश से रेल मंत्री रहे। ... (व्यवधान) ...

श्री अनिल माधव दवे : हम आपकी ओर सम्भावना से देख रहे हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल : ठीक है, आशा बाँधे रहिए। आशावान बने रहेंगे, तो कुछ-न-कुछ मिलेगा ही।

लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद पंडित कमलापति जी रेल मंत्री रहे। कुछ दिन हमारे उत्तर प्रदेश के महावीर प्रसाद जी भी राज्य मंत्री रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से कितनी नई ट्रेनें चलाई गईं? आप पिछले बजट को देखिए। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग कर दिया गया। अगर हम लखनऊ से देहरादून के बीच जाना चाहें, तो दो राज्यों की राजधानियों, लखनऊ से देहरादून के बीच जाने के लिए बाबा आदम के जमाने की चली दून एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस, मात्र दो ट्रेनें हैं, जिनसे हम वहाँ जा सकते हैं। श्रीमन्, 50 साल पहले चली वे ट्रेनें, जो बंगाल से आती हैं, बनारस से आती हैं, उन दो ट्रेनों से हम आशा करें कि दो राज्यों के बीच आवागमन बढ़ गया, हम चल पाएँगे, तो ठीक नहीं है। मैं ममता जी से कहूँगा कि वे इस पर विशेष ध्यान दें और लखनऊ से देहरादून के बीच एक ट्रेन चला दें, तो कम-से-कम दो राज्यों की राजधानियाँ जुड़ जाएँगी और उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल फिर एक हो जाएँगे और उत्तर प्रदेश के लोगों को लगेगा कि हम पर ध्यान दिया गया। वैसे तो उत्तर प्रदेश में बहुत ट्रेनों की डिमांड है, मैंने उस दिन कहा भी था, मैं आपके

विभाग के अधिकारियों से मिला भी था, उनको भी तमाम सुझाव दिए हैं, उनसे तमाम माँग की हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनमें से कितनी पूरी होंगी।

(2एच/डीएस पर जारी)

-AKG/DS-NBR/2h/3.15

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल (क्रमागत): वैसे तो आपने लखनऊ स्टेशन को टॉप प्रायोरिटी पर लिया है, लेकिन उसमें अभी तक बहुत अच्छा सुधार नहीं हुआ है। अगर वहाँ प्लेटफॉर्म्स बढ़ा दें तो अच्छा होगा, क्योंकि अब लखनऊ से 200 ट्रेनें निकलने लगी हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चाहे झांसी हो, कानपुर हो, बनारस हो या लखनऊ हो, इन सब स्टेशनों में हमें सुधार करना पड़ेगा।

मैं हरदोई की बात करूँगा। मैं ऑरिजनली वहीं का रहने वाला हूँ और राजनीतिक जीवन की शुरुआत मैंने वहीं से की। हरदोई नॉर्दर्न रेलवे का एक मुख्य स्टेशन है। मैंने उस दिन भी कहा था कि हरदोई और लखनऊ के बीच लोकल ट्रेन चलायी जाए तो रेल विभाग ने एक जवाब दे दिया कि वहाँ 6000 पैसेंजर्स चलते हैं, जबकि बीच के स्टेशनों को नहीं जोड़ा गया। मैं कहता हूँ कि अगर आप लखनऊ के बाद बालामाऊं, संडीला, रहीमाबाद, मलीहाबाद, काकोरी, आदि क्रांतिकारियों से संबंधित बड़े-बड़े स्टेशनों को जोड़ लीजिए तो 20 हजार से कम पैसेंजर्स नहीं चलते हैं। अगर आप इन 20 हजार पैसेंजर्स के आवागमन के लिए एक शटल अथवा लोकल ट्रेन चला दें तो अच्छा रहेगा, वह रूट भी electrified हो गयी है। उस दिन ब्रजेश पाठक जी ने भी यह बात उठायी थी। हमारे हरदोई में अंग्रेजों की बनी हुई माधोगंज-सांडी, बहुत पुरानी लाइन है। वहाँ लोग आज भी तरस रहे हैं कि अंग्रेज चले गये, ट्रेन बन्द हो गयी। अब तो कम से कम हमारा देश आजाद हो गया, अब ट्रेन चल जाएगी, लेकिन आज तक कोई भी ट्रेन उस पर नहीं चली। आप उस पर ही ट्रेन चला दें, आखिर आप कुछ तो कर दें। तमाम ऐसी ट्रेनें हरदोई से पास हो जाती हैं जो लखनऊ, शाहजहाँपुर, बरेली और मुरादाबाद में रुकती हैं, लेकिन पता नहीं हरदोई से क्या नाराजगी है? (समय की घंटी)

श्रीमन्, मैं ममता जी से कहूँगा कि मैंने कई पत्र दिए हैं, अगर आप उन पत्रों को निकलवा लें और उन पर विचार कर लें तो मैं समझूँगा कि आपको उत्तर प्रदेश के प्रति कहीं न कहीं से रहम आया। अगर आप उत्तर प्रदेश के प्रति कुछ सोचेंगी तो जरूर आगे बढ़ेंगी और अगर उत्तर प्रदेश की उपेक्षा करेंगी तो भगवान ही मालिक है कि क्या होगा।

श्रीमन्, इसी प्रकार, मैंने लखीमपुर के बारे में कहा था कि आप वहाँ मयगलगंज में माल गोदाम बनवा दें, क्योंकि छोटी लाइन का मयगलगंज स्टेशन बड़ी लाइन पर पड़ता है। लखीमपुर में एक पुल भी बनना है। ग़ाजियाबाद से हमारे माननीय सदस्य कश्यप जी बैठे हुए हैं। ग़ाजियाबाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है, लेकिन आज वह बुरी स्थिति में है। वहाँ के स्टेशन पर बड़ी गन्दगी है और वहाँ कोई वीआईपी रूम नहीं है। ममता जी, ये तो मैंने लोकल बातें बतलायी हैं।

श्रीमन्, अगर हम रेलवे की पेन्ट्री देख लें तो वहाँ इतनी गन्दगी है कि कोई पैसेंजर खाना नहीं खाएगा। कई बार अखबारों में यह बताया गया कि शताब्दी में जो फल परोसे जा रहे हैं, वे सड़े हुए और खराब हैं, पता नहीं वे किस तरीके के हैं। अब शायद आपने यह निर्णय लिया है कि आप इन सारी चीजों पर कड़ाई करेंगी, लेकिन आप यह कड़ाई कब करेंगी? अगर हमें रेलवे में भी अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ पर अच्छा खाना मिलेगा? अगर वहाँ सफाई नहीं हुई और हम रेलवे का खाना खाकर बीमार हुए ... (समय की घंटी)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude. We have to take up the next item also.

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: अन्त में, मैं कहूँगा कि कि रेलवे में कुलियों की बहुत कमी है। पूर्व मंत्री लालू प्रसाद जी तमाम कुलियों को अपग्रेड कर गये थे। आज स्टेशनों पर कुलियों का बहुत अभाव है। कुछ स्टेशन तो ऐसे हैं, जहाँ एक कुली भी नहीं रह गया है। हर पैसेंजर की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह अपना सामान खुद उठा कर चले। इसलिए आप कुलियों की भर्ती पर भी ध्यान दें और उनकी भर्ती में आरक्षण का विशेष ध्यान रखें। अगर आप इन सब

बातों पर ध्यान देकर इस सदन को कुछ जवाब देंगी तो मैं समझूँगा कि आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, उस पर कुछ विचार किया और निर्णय लिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

SHRI MOINUL HASSAN (**WEST BENGAL**): Mr. Vice-Chairman, Sir, before I start my main speech, I would like to remember the 2010-11 Budget Speech delivered by the hon. Railway Minister in the Lower House. She said and I quote it from the PIB release. It says, "Safety and Security never sleeps and zero tolerance for accidents is our vision and mission." I firmly believe that this should be the vision and mission of the Railways as well as the country. Today morning, while replying to a supplementary, the hon. Railway Minister said that more than 2 crore people are traveling from one part of the country to the other. But, we all know the reality and the problems that we are facing.

(CONTD. BY USY "2J")

-NBR-USY/2J/3.20

SHRI MOINUL HASAN (**CONTD.**) During the last one year, or, to be very precise, during the last fourteen months, there has been an unprecedented series of accidents, not only in any particular State, but throughout the country. It is absolutely right that an accident is an accident. You can't predict about an accident. It is a fact. But it is a very serious matter that the people of this country have been facing a series of accidents. The reply to a Starred Question, placed before the House today, says that maximum number of accidents has taken place due to human errors. But I would like to make one point that the Railways should

pay attention to the maintenance of equipments. Also, the safety measures are being neglected. It is one of the major factors for accidents. It should be recognized by the Ministry of Railways. So, it is not only the human errors that are responsible for accidents. Very recently, in West Bengal, a very big and unfortunate accident had taken place at Sainthia between Vananchal Express and Uttar Banga Express. A lot of ill-fated people had suffered in this accident. A lot of casualties had taken place. But my submission is that it is not only the human errors that are responsible for such accidents, but, in most of the cases, there is negligence on the part of Railway administration. We know that proper inquiry will be conducted. So far as Gyaneshwari Express is concerned, more than 160 casualties had taken place. The matter is being investigated by the CBI. The hon. Minister had herself told today morning that so far as the Sainthia Express accident is concerned, there was a demand for CBI investigation. I am not going into the details of that. But I would like to know one thing from the Minister. It is reported that thirteen people have been arrested in connection with the Gyaneshwari Express accident. Is the Ministry aware of their identity? Who are these 13-14 people, who have been arrested? It is a prime concern of common man. People are in panic because of these frequent accidents. They are so scared whether they should travel by train or not. I am saying all this because the Railways is the lifeline of the country. More than 2.20 crore people, throughout the country, travel by Railways; more than 70,000 trains are running; there are thousands of kilometers of railway line throughout the country. So, I firmly believe that the 'Railways' is the lifeline of our country, so far as the people and economy

of our country are concerned. So, safety of passengers should be the first priority of the Railways. I suppose, even today also, there are three slogans at the railway stations -- safety, security and punctuality. But the first slogan, that is, safety, is under attack. So, the prime concern of the Railways should be the safety and security of its passengers. This is my first submission.

My second point is with regard to security. It is a fact that there are some maintenance problems, and like that. But a lot of posts are also lying vacant in the Railways.

(Contd. by 2k -- pk)

-USY/PK/3.25/2K

SHRI MOINUL HASSAN (CONTD.): There are two three points in this regard. In the reply given to an Unstarred Question in the Lok Sabha this week, it was said, —"Merely 87,000 posts are vacant which are related to the safety and security measures, as far as the railway is concerned." Why is this so? (Time-bell) I know the railways are in a process to fill up the vacant positions. But Sir, since it is related to the safety and security of the passengers, it should be done as early as possible. Today morning, the Ministry of Railways told that right from OBC, minorities to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, she is now in the process of filling up these vacancies. So, I emphasis upon this point that as far as the safety and security is concerned, she must fill up these posts as early as possible.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude.

SHRI MOINUL HASSAN: Sir, my next point is this. I am very much astonished to hear the reply of the hon. Minister. I heard her speech in the Lok Sabha. I would like to know from the hon. Minister why the anti-collision device has not been introduced in the Railways so far. This is my question. Who will reply to this? The Government of India will reply to this. Why is the Government of India not introducing this?

Sir, my last point is this. I feel that there is some discrimination against the Rajya Sabha Members. I do not know why the Railways is having this type of a system. The Railways have introduced monthly passes, 'Izzat train pass' of Rs.25/- for some section of the people. It is a good thing. But the Lok Sabha Members send requisition letter to the Station Master, and, Sir, I was compelled to send it to the DRM. It is causing inconvenience to the Rajya Sabha Members. I request the hon. Minister to look into this and make the process easier.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay.

SHRI MOINUL HASSAN: Sir, there are two, three more points. Sir, One is about the Palghat coach factory, which is in your State. Then, Sir, the UPA-I Government had declared a wagon factory at Alapuzha. Nothing has been done. Then, more allocation should be made for doubling and electrification in Kerala. This is very much related to your State, Sir. These are my points. Again, I would like to draw the attention of the hon. Minister to these points and request the hon. Minister to address these points. With these words, I conclude. Thank you.

(Ends)

SHRI S. THANGAVELU (TAMIL NADU): Sir, at the outset, I would like to express my sincere gratitude to my leader, hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Kalaignar, who has given me the opportunity to become a Member of this august House. I remember here with pride, Perarignar Anna who was the hon. Member of this House and made a great contribution to the growth and development of the people of Tamil Nadu.

As a common citizen belonging to the Scheduled Caste, I also remember Dr. Ambedkar who was a Member of this august House and the architect of our Constitution and his contribution for upgradation of downtrodden people. I further remember here with pride Hon. Murasoli Maran on the occasion of his 76th birthday. He also was a Member of this House and also the Cabinet Minister for a long period. Previously, he acted as a bridge for our leader Dr. Kalaignar and the Central Government. We cannot forget his great contribution to growth and development of this nation and also his diplomatic approach and powerful advocacy for the honour and growth of our country in Doha Conference.

(Contd. by 2L/PB)

PB/2l/3.30

SHRI S. THANGAVELU (CONTD.): First of all, I welcome the Supplementary Demands for Grants for the Ministry of Railways. Railways has direct link with every citizen of the country and it is therefore necessary to earmark adequate funds for railway projects on priority basis to make the railway service accessible to all sections of the society. Sir, it is my maiden speech. So, I would like to

utilize this opportunity for listing a number of long pending demands of the people of Tamil Nadu, as I feel it is my principal duty to do so.

As far as conversion of gauge is concerned, I can certainly say that Tamil Nadu is the only State which has the longest distance of meter gauge lines than any other State of the country. Even though a number of projects are being announced in the Railway Budget every year, but the implementation of those projects could not be realized. For example, the conversion of line between Sengottai and Punalur section of 49 kilometres with 950 meters of tunnel is still under process. It should be completed without further delay so that Tutucorin Port and Cochin Port will have direct link as well as successful execution of Samuthram Project will come into reality.

Also the gauge conversion between Sengottai to Punalur is important, as it would be fruitful for economic and industrial development of both Tamil Nadu and Kerala States. After completion of gauge conversion between Sengottai to Punalur via Thenkasi and Madurai if a new train from Cochin or Thiruvananthapuram to Chennai is introduced, the present distance of 250 kilometres would be reduced and five hours journey time would be saved.

Also the gauge conversion between Tirunelveli and Tenkasi section of 70 kilometres is in slow progress. So I request that it should be completed within the stipulated time.

Secondly, gauge conversion of 90 kilometres between Madurai and Bodinayakkanur has not been initiated till today despite the fact that it was previously announced by the Government in the Railway Budget. Likewise,

though the gauge conversion between Villupuram to Katpadi via big pilgrim centre of Thiruvannamalai started four years ago but the work is still going on.

Apart from long distance meter-gauge lines in the State of Tamil Nadu, the early proposed projects of doubling the line are still not implemented and some works are going on at snail pace. I would like to remember in this House that our Hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Kalaignar, has already urged the Government for doubling and electrification of Chennai to Kanniyakumari section. Due to the absence of double line between Madurai-Virudunagar segment, trains from Virudunagar-Kanniyakumari, Virudunagar-Sengottai and Vanchi Moniyachi to Tuticorin sections are unnecessarily halted at small stations like Kallikudi and Thirumangalam for hours.

Sir, I am very much concerned about the meagre number of new trains introduced in my State and it is customized to cancel the train service of any route without prior notice or alternative steps. Sir, presently, the Podhigai Express from Chennai Egmore to Sengottai is fully congested as this line is the main route for the majority of the people who are visiting Kuttralam, a tourist place and Ayyappan Koil. Further, there was a weekly train between Chennai Egmore to Shengottai but, later, it was cancelled. It has created more passenger traffic in the existing Podhigai Express. Hence, I request the Government to bring back the earlier weekly train and convert the same into daily basis.

Likewise, a new train from Sengottai to Coimbatore via Tiruppur was announced by the Government recently and as such a weekly train was running, but this was also stopped now. So, I request the Government to provide daily

service on this line. A shuttle train from Coimbatore to Salem via Tiruppur and another new train from Coimbatore to Bangalore should be introduced to minimize road traffic and consequent fuel wastage. From the big pilgrim centre, Thiruchendur to Chennai via Madurai, Trichy, a weekly train is running presently, and I request to convert this service on daily basis with a stopping at Kayalpattinam. I also request for a daily service in day time from Rameshwaram to Chennai for which a new train may be introduced.

(Contd. by 2m/SKC)

2m/3.35/skc-sc

SHRI S. THANGAVELU (contd.): I would request you to provide daily train service during the day between Nagercoil and Rameswaram, where the train service provided is only three days a week. A new route connecting Dindigul-Theni-Kumuli-Aiyyappankoil should be laid, as the route has a number of tourist places. Also, it would provide a link between Tamil Nadu and Kerala. The process of laying a new line between Salem and Karur has been very slow; it has been going on for the last ten years. It should be completed within one or two years. Also, a new 27 kilometres stretch should be laid between Dharmapuri and Murappur.

Sir, Sankarankovil is a tourist and religious place. The passenger reservation system in Sankarankovil, Kadayanallur, Srivilliputhur and Tirumangalam should be upgraded into a full-fledged ticket counters functional from 8 a.m. to 8 p.m.

Before concluding, I would like to make two important requests. There is a big yard with a coaching terminus at the Madurai Junction. Here, widening of

platforms, modernization and installation of escalators is necessary since thousands of people use the Madurai Station everyday. I would request the Government to consider setting up a wagon workshop and coach maintenance yard at the Tirunelveli Junction. Also, the Tirunelveli Junction should be declared a big terminal station. If that is done, it would provide a useful link to a number of new routes and connect various places.

Sir, while participating in the discussion on The Appropriation Bill of the Railways, I have listed a number of long-pending demands of my State. There are many more points left, but there is paucity of time, and with the hope that the pending demands would be addressed in the coming years, I support this Appropriation Bill wholeheartedly.

(Ends)

SHRI RANJITSINH VIJAYSINH MOHITE-PATIL (MAHARASHTRA): Thank you, Sir, for giving me time to speak on the Appropriation Bill. सर, मैं ज्यादा समय न लेते हुए ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से यह विनती करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में पंडरपुर-मिराज रेलवे लाइन थी, उसकी पटरी तो डाली गयी है लेकिन स्टेशंस पर कार्गो हब बनाने और अन्य चीज़ें करने के लिए 800 करोड़ रुपए की अभी भी आवश्यकता है। आदरणीय मंत्री महोदया से मेरी विनती है कि यह जो 800 करोड़ रुपए की मांग है, उसे अगर पूरा किया जाए तो अच्छा होगा क्योंकि पंडरपुर एक धार्मिक स्थल है और साल में लगभग सवा करोड़ से दो करोड़ लोग वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए पंडरपुर-मिराज रेलवे लाइन, जितनी जल्दी हो सके, वहां पर जितनी जल्दी amenities दी जा सकें, दी जाएं, यह देखने की आवश्यकता है। दूसरा, जो कुर्दवाडी है, वहां पर वेगन्स के rehabilitation का काम किया जाता था। वहां पर सरकार की जमीन है, रेलवे की जमीन है लेकिन आज तक वहां पर काम न मिलने की वजह

से हजारों मजदूर और कामगार बेकार हो गए हैं। वहां पर आज जो भी infrastructure बचा है, उसके लिए आपने 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी, वह tender भी निकाला गया था, लेकिन बाद में वह tender केंसिल हो गया। इसलिए मेरी आदरणीय मंत्री महोदया से विनती है कि वह 30 करोड़ रुपए अगर आप देंगी तो जो भी वहां पर facilities आज खड़ी हैं, उनसे और भी अच्छे wagons का rehabilitation होगा और जो कामगार हैं, उनको काम मिल सकता है। महोदय, मैं एक आखिरी मांग और करना चाहता हूं। आदरणीय मंत्री महोदया, आपको सब दीदी बुलाते हैं। आपका छोटा भाई होने के नाते मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। आज़ादी के बाद हर साल यहां पर एक सवाल उठाया गया है - पंडरपुर-लोनंद रेलवे लाइन के बारे में यह मांग हमेशा आती रही है, लेकिन आज तक उस पर कोई सोच-विचार नहीं किया गया है। मेरा अनुरोध है कि अगर उसका सर्वे हुआ है तो आगे की कार्यवाही की जाए और अगर सर्वे नहीं हुआ है तो सर्वे कराया जाए क्योंकि पंडरपुर शोलापुर डिस्ट्रक्ट में आता है, जहां पर barren land है, वह barren district है। ऐसा करने से वहां के किसानों को और वहां के धार्मिक स्थलों को अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसलिए पंड़रपुर-लोनंद रेलवे लाइन डालने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं। महोदय, चार दिन के बाद रक्षा बंधन का त्योहार है। मेरी दीदी से विनती है कि लोहे की कड़ी डाल दें ताकि एक रक्षा बंधन आपका महाराष्ट्र से जुड़ा रहे। यही विनती करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(समाप्त)

(2एन-एमसीएम पर आगे)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Shri Pyarimohan Mohapatra, not present. Shri Mahendra Mohan.

श्री महेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीया रेल मंत्री जी ने जो लगभग 498 करोड़ रुपए का भारत सरकार के कंसोलिडेटिड फंड से धन मांगा है, उससे मैं सहमत हूं, वह धन उन्हें जरूर आबंटित किया जाए। लेकिन मेरा उनसे अनुरोध है कि कुछ ऐसे कार्य हैं जो बहुत समय से बाकी पड़े हुए हैं और रेलवे के पास एक बहुत बड़ा स्रोत है जहां से धन लाया जा सकता है। यह सवाल मैंने रेलवे कंवेंशन कमेटी में भी उठाया था जब मैं वहां पर था। रेलवे की जो प्रापर्टी पड़ी हुई है उसका कोई स्टॉक टेकिंग नहीं हुआ है। अगर रेलवे की प्रापर्टी का स्टॉक टेकिंग कराया जाए कि कहां कितनी रेलवे की प्रापर्टी पड़ी हुई है, उससे बहुत सा धन एकत्रित किया जा सकता है, जिससे रेलवे के एक्सपेंशन के लिए अच्छे कार्य किए जा सकते हैं।

इसके साथ ही साथ मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कानपुर स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेशन बनाने की घोषणा सदन में दो साल पहले की गई थी। लेकिन जिस प्रकार से वहां कार्य चल रहा है, अगर कभी वहां का आकस्मिक दौरा माननीया रेल मंत्री जी कर लें तो पता लगेगा कि किसी भी प्रकार से प्रगति नहीं हो रही है। वहां स्टेशन पर हर समय गंदगी पड़ी रहती है और वहां कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। कानपुर के स्टेशन पर व्यवस्थाएं ठीक की जाएं। इसके साथ ही साथ ट्रेनों के अंदर साफ-सफाई, इसके अलावा स्टेशनों पर साफ-सफाई की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। एक जो अन्य विषय है, वह कानपुर-झांसी में इलेक्ट्रिफिकेशन का था, जिसे पूर्व रेल मंत्री जी ने स्वीकार भी किया था। कानपुर-झांसी से होकर ही कानपुर और उत्तर प्रदेश का जुड़ाव बनता है। कर्नाटक से, तमिलनाडु से, इन सारे स्टेट्स से, वहां पर सिंगिल लाइन चलती है, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है जिसके कारण बहुत दिक्कतें होती हैं। वहां पर डबल लाइन

कराए जाने का कार्य पहले से ही स्वीकृत है, लेकिन बहुत ही धीमी गति से वह कार्य चल रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या आती है जब ट्रेनें लेट हो जाती हैं। उसमें यह व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़ चुकी है, उससे रेलवे के अंदर यह एनाउंसमेंट हो जानी चाहिए कि अगर गाड़ी एक घंटे से अधिक लेट हो रही है तो किस कारण से यह गाड़ी लेट हो रही है और कितनी लेट है। तो जो सवारियां गाड़ी में चल रही होती हैं, इससे उन्हें सुरक्षा का कुछ भाव प्राप्त हो सकता है, अन्यथा उनको बड़ी दिक्कत होती है। यह पता ही नहीं चलता है चाहे वह राजधानी ट्रेन हो, शताब्दी हो या अन्य विशेष ट्रेनें हों, कि वे क्यों लेट हो रही हैं और कितनी देर बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंचेंगी, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। उस ओर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अगर इसमें एनाउंसमेंट की व्यवस्था करा दी जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा।

मैंने आज सुबह ही एक प्रश्न सुरक्षा के बारे में उठाया था। लूटपाट और जिस प्रकार की घटनाएं आजकल रेलवे के अंदर हो रही हैं, उस ओर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें एक कोआर्डिनेशन होना चाहिए स्टेट के साथ, अन्यथा जो रेलवे पुलिस फोर्स है उसको अतिरिक्त अधिकार दिए जाएं। उसके लिए जो भी संशोधन कानून में करने हों, वे किए जाएं जिससे कि ट्रेनों के अंदर सुरक्षा मिले। ट्रेनों के अंदर विशेष रूप से महिलाओं को सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है, उनके साथ बदसलूकी भी हो जाती है और उन्हें सुरक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। आज ट्रेनों में महिलाओं का अकेले चलना बहुत ही कठिन और दूभर होता चला जा रहा है, इस ओर भी इन्हें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए।

इसी प्रकार से जब से कुलियों को गैंग मैन बनाने का कार्य किया गया, तब से कुलियों की बहुत कमी हो गई है। जब महिलाएं और बुजुर्ग ट्रेनों में चलते हैं तो सामान वगैरह उठाने में उन्हें बहुत कठिनाई होती है। तो कुलियों के लिए नए लाइसैंस दिए जाएं और कुलियों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे महिलाओं और बुजुर्गों को समुचित सुविधा प्राप्त हो सके। इन्हीं चीजों के साथ मेरा आपसे अनुरोध है कि रेलवे के जो ओवर ब्रिजेज के काम पैंडिंग पड़े हुए हैं, बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं, उस ओर ध्यान दिया जाए, ताकि ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो सकें, ताकि ट्रेफिक जाम की जो समस्या रहती है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत

से स्थानों पर और कानपुर में विशेष रूप से, उस ओर भी ध्यान दिया जाए। वहां के ओवर ब्रिजेज जल्दी से जल्दी पूरे किए जाएं और यह कार्य आगे बढ़ाया जाए।

इन्ही शब्दों के साथ मैं समर्थन करता हूं कि उनको अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाए। इस देश की रेलवे पूरी उसी प्रकार से क्रियाशील होनी चाहिए जिस प्रकार से शरीर के लिए सारी धमनियों का कार्य होता है, वैसे ही रेलवे हमारे सारे देश को जोड़ती है, एकता को बढ़ाती है। मैं उनका समर्थन करता हूं।

(समाप्त)

(2o/gs पर आगे)

KSK/3.45/2O

SHRI A. ELAVARASAN (TAMIL NADU): Sir, the Indian Railways has been playing a vital role in the development of the economy. It has become the lifeline of country's economic prosperity. Everyday, lakhs and lakhs of people travel in the trains, irrespective of caste, creed and religion. It is also the symbol of national integration. It is the largest public sector enterprise with 14 lakh employees and eleven lakh pensioners.

In Tamil Nadu, the length of the metre gauge lines is very-very high as compared to other parts of the country. I appeal that concerted action should be taken by the Railway Ministry to convert all the metre gauge lines into broad gauge lines. It is needless to say that poor allocation for safety works will cost precious human lives. Accidents at unmanned level crossings have become a regular affair. This puts the rail travel safety and road travel safety to great risk. I appeal to the hon. Railway Minister to increase allocation for safety works.

The announcement was made in the Budget for the modernisation of the railway stations into the world class stations and Adarsh stations. A minimum number of stations have been identified. Chennai Egmore, Tambaram, Trichirapalli, Madurai, Salem, Coimbtore, Kumbakonam and Myladuthurai stations may also be included in the proposed list of Adarsh stations. Chennai Egmore, Chennai Central linking project was inaugurated in the year 2003 by the then Minister of State for Railways. There is an increasing doubt in the minds of the people whether the scheme has been dropped. I categorically urge the Minister to clarify whether the scheme has been dropped or not. The main and chord lines from Chennai to Kanyakumari via Trichy and Madurai should be double lined and electrification must be done. There are the five new lines which are under construction: Salem-Karur, Tindivanam-Nagari, Athipattu-Puthur, Erode-Palani and Tindivanam-Thiruvannamalai.

Many railway stations in the rural areas of the country lack basic amenities like drinking water, clean toilets and hygienic refreshment stalls. Many stations have small platforms that don't accommodate all the coaches of the trains. Many coaches of the trains are far away from the platforms causing great inconvenience to passengers while boarding and alighting. I request that funds may be allocated for the extension of all such platforms in the current Budget itself. A new railway line should be ordered in between Madurai and Trichy via Melur and Viralimalai. Steps should be taken to provide safety and security for the passengers. The formation of new railway line in between Nagapattinam and Velankanni is complete. In view of the festival of Velankanni, which is going to start from 29th

August, 2010, I request the hon. Minister for Railways for early inauguration of the railway line on or before 29th August, 2010.

I humbly request the hon. Minister to consider the following genuine requests of the public : (1) To resume the service of Rockfort Express from Chennai-Trichy-Chennai instead of Chennai to Kumbakonam, (2) The Railway Workshop at Golden Rock may be converted into Coach Manufacturing Factory like the Perambur Coach Factory, Chennai, (3) The Railways should come forward to start new hospitals and multifunctional shopping complex at Trichirapalli Railway Junction, (4) Fill up the safety-related posts, (5) To provide adequate personnel in unmanned railway crossings, (6) efforts should be made to provide better sanitary maintenance in the railway compartments, (7) adequate security with the help of defence personnel may be provided in long-running trains to ensure the safety of the passengers, and (8) to set up a monitoring mechanism to check the quality of food provided in the long-running trains.

With these words, I conclude. Thank you.

(Ends)

(followed by 2p - gsp)

GSP-ASC-3.50-2P

SHRI M. P. ACHUTHAN (**KERALA**): Mr. Vice-Chairman, Sir, there is a widespread criticism and dissatisfaction about the working of the Railways. It was amply manifested in today's Question Hour. Railway accidents are increasing and the safety of the passengers is in danger. More than 87,000 posts are lying vacant. Today, the Minister has promised that she will take action to fill up the

vacancies. I hope, she will give a timeframe to fill up the vacancies, especially, those which are concerning the railway safety. Sir, 87,000 posts, which are directly connected with the Railway safety, are lying vacant. Due to the shortage of staff, the workload on Railway employees has tremendously increased. Some drivers are forced to work continuously up to sixteen hours, which endangers the safety of the passengers. This is the general picture.

Now, I will draw the Minister's attention to some urgent needs and complaints of Kerala. Sir, we have been saying for long that the State of Kerala is being neglected or discriminated by the Railway authorities. We hoped that there would be some improvement. When the Minister of State for Railways was in Kerala, he toured every Railway station in Kerala, and, received thousands of complaints and suggestions from the passengers. But I am sorry to say that he failed to fulfill his promises. I do not know the reasons but still many of the promises have not been fulfilled.

Sir, in the Railway Budget for the year 2008-09, it was announced that a Rail Coach Factory will be sanctioned at Palakkad. The State Government acquired more than 431 acres of land and handed it over to the Railways but still, the Railways and the Union Government have not taken any decision to sanction this project. The State Government has suggested that the value of the land may be converted as the equity of the State. Either through PPP or any other mechanism, we want Rail Coach Factory, which was promised long time back during Smt. Indira Gandhi's time.

Sir, in the Railway Budget for the year 2007-08, the State of Kerala was promised that a joint venture with steel industry of Kerala will be formed to establish a wagon factory at Alappuzha. Still, there is no word or clearance in this regard by the Railway authorities.

Sir, a dedicated freight corridor connecting Trivandrum with all major metro cities was also promised to us. It is a long-standing demand of the State of Kerala but the Railway is not ready to consider that demand. Sir, with regard to doubling and electrification work in Kerala, there are a few stretches where the doubling work is pending. Without doubling and electrification work, railway facilities cannot be improved in Kerala. (Time-bell)

Finally, Sir, I will request the Railway Minister to grant some more funds and also give us a timeframe to complete the electrification and doubling work in the State of Kerala. With these words, I conclude my speech. Thank you.

(Ends)

(Followed by YSR-2Q)

-GSP/YSR/3.55/2Q

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Shri Birendra Prasad Baishya, not there. Shri Kumar Deepak Das, I can allow you because only one Member can be allowed from your party. Take two-three minutes.

SHRI KUMAR DEEPAK DAS (ASSAM): Sir, the Railways is running with an ambitious and creative plan. I thank the hon. Railway Minister for assuring us that the pilgrimage of Kamakhya will be connected with other important places of pilgrimage by the Railways. I also thank her for her assurance to complete the

survey of new railway line between Jogighopa, Barpeta, Hajo and Amingaon within this financial year. We are eagerly awaiting the announcement of fund provision for this new railway line in the next Railway Budget.

Sir, the North-East region needs an adequate and focussed funding for the railway network. The pace of national project, which has been taken up for implementation in our region, is very slow because of paucity of funds. A long-standing demand of electrification and double-tracking of railway line in the North-East region is still an illusion. The North-East region is backward and one of the main reasons of it is this.

We are surprised that Bongaigaon-Jogighopa-Kamakhya line is considered for the double-track line between Bongaigaon, Rongia, and Kamakhya. This is the impression given by the Ministry in various replies.

Madam, I request you to take immediate steps for doubling the existing railway tracks in the North-East region which is still an illusion for the people of North-East region. It will cost much less in comparison to other States, because meter-gauge track, which is still abundant, can be developed as second broad-gauge track. I hope the hon. Minister for the Railways will assure us in this regard.

Madam, 400 bigha of Railways' land at Sorbhog line has been lying unutilized for the last six years. Please utilise it and establish at least one factory there or start any other development work in that area, so that it cannot be occupied by other unexpected persons.

Madam, we want that there should be removal of dirty and deplorable coaches which are usually used in various trains running from Assam.

Madam, please start a new passenger train between Dhubri and Guwahati via Rongia, so that North Lakhimpur district and Dhemaji district of Assam along with Arunachal Pradesh can be linked up. There is an urgent need of creating a new separate zone exclusively for the North-East region. It will have exclusive and inclusive economic growth of the North-East Region.

I would like to know whether the hon. Minister will give priority to consider such demands. I hope that Madam will react positively to such demands.

With these few words, I, once again, thank the hon. Minister for giving priority to consider various projects in the North-East region.

Sir, I thank you very much for having given me this opportunity.

(Ends)

(Followed by VKK/2R)

-YSR/VKK-AKG/2r/4.00

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA (**ORISSA**): Sir, I do not support this Appropriation Bill for the simple reason that the Railways perhaps need an additional Rs.15,000 crore. They have been short-changed in this Budget. They have been short-changed in this Budget as they have been short-changed in every Budget. It is high time that from the Central exchequer, the Railways are funded more and more to be able to do their duty to the nation. It is the most crucial infrastructure. The Railway Minister keeps on listening to all of us in both the Houses. And when she goes and sits down in her throne with all the Railway

Board Members and everyone, they say that they have not got enough funds, but, let us try to satisfy everyone, put a little bit here and put a little bit there. What else can she do if she is denied the funds that she deserves? So, I will not make any demand as such because our demands are well known. Every State has demands. All my colleagues have been making demands. We should demand that the Railways should not be treated merely as a commercial organisation. There should be support available. For the social cost which they incur, they must get the benefit. Unless they do so, I am afraid, the rolling stock will deteriorate, safety measures will not be there and gradually, we will come to a situation where accidents will be more. And because it is depreciating, every such rolling stock will depreciate pretty fast. I don't think I have studied it, but, I think, their depreciation fund is not big enough to really take care of the situation.

Sir, having said this, I will come to a few problems of Orissa. Sir, after long decades, Orissa is going into the throes of industrialisation. Today, there are commitments of more than Rs.6,00,000 crore of investment. If the PCPIR of the Ministry of Chemicals and Fertilisers are put together, if it comes up, which is likely to come up in the near future, it will add another Rs.1.7 lakh crore of more investment. Madam, you will be glad to know that in 2009-10, Orissa stands as number one with an investment of Rs.71,000 crore or Rs.74,000 crore, well ahead of all the other States. But, how would these fructify without infrastructure? You said, "Build roads". Now, the cheapest mode of goods and passenger traffic is the Railways and you are not there. Let us say we need this Daitari-Banspani, which you have built to be doubled, to be extended up to Barbil. A short gap is

there -- that's not being done -- to connect it to Jamshedpur. The entire northern market, the northern region, is available for industries in Orissa. Otherwise, they go by a longer route and costs increase. Similarly, we are putting up ports. Thirteen ports have been planned. Three have already started; three more are likely to start during this year. The general principle that the Railways appear to be taking is, "No, we won't build lines to those ports." It will be too much to accept port developers to take care of the entire cost of the line. Why don't you get into a joint venture? If he takes the railway line, you also lose revenue. It will be a dedicated private railway line. So, why not take up a joint venture? Please think about this suggestion. Another suggestion would be to kindly shift Rourkela-Jharsuguda portion from South Eastern Railway to Orissa and take out the Waltair Division minus Orissa portion to Andhra Pradesh. Andhra Pradesh has been demanding. We have been demanding for this portion.

(Contd. By MKS/2s)

MKS-DS/4.05/2S

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA (CONTD.): Please do it; you will get the blessings of the people of both Andhra Pradesh and Orissa for your future ventures. I have a number of railway lines which are important in the State, which I can mention before you, but I do not want to mention for paucity of time. A number of important trains which you have to run, So, all those lists I will send to the Chairman, Railway Board, and with a copy to you, if you have time to look at it. But passenger amenities in Orissa stations are awful. (Time Bell) You go to

other States; you go to Orissa; you will find the difference. Please take care of that. Thank you very much, Sir.

(Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you, Mr. Mohapatra. Now, Shri Rajniti Prasad.

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं नंदी येल्लैया साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आन्ध्र प्रदेश के होते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छी हिन्दी में रेलवे पर अपनी बात कही। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। वे तेलुगुभाषी हैं, लेकिन फिर भी वे अच्छा बोले। ..(व्यवधान)..

सर, पहली बात यह है कि जो प्राकृतिक आपदा होगी, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी लेह में बादल फटा, फिर वहाँ भूकम्प आया और वहाँ पर लेह में जो हुआ, स्कूल की छत पर बच्चे मर गये, उनके टिफिन आदि हमको दिखाये गये, लेकिन जब हमारी और आपकी भूल के कारण पैसेंजर्स का जो बस्ता दिखता है, यानी आदमी तो मर जाता है, लेकिन उसका लगेज़ बच जाता है। वह हमारी भूल के कारण होता है। अगर हम बात नहीं करेंगे, तब भी आपको पैसा तो मिलेगा ही, लेकिन इसके बारे में आपको कोई उपाय निकालना चाहिए। जब हम लोग रेल में जाते हैं तो एक दर्दनाक स्थिति होती है और हमें हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता है, *जय हनुमान ज्ञान गुण सागर* कि कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। तो यह जो हनुमान चालीसा पढ़ने वाली बात है, उसके लिए आप जरूर कुछ कीजिए। अगर आप नहीं करेंगी तो गरीब लोग ट्रेन में कैसे चलेंगे? हम लोग तो हवाई जहाज में चलते हैं या कभी किन्हीं दूसरे साधनों से चलते हैं। आपकी जो ट्रेन है, उसमें कभी ऐसा झंझट होता है, उसमें कभी ऐसा हड़कम्प होता है कि या तो कभी लाइन खत्म हो जाती है, कभी बिजली की लाइन खत्म हो जाती है या कभी कहीं सिग्नल में गड़बड़ी आ जाती है और तब ये ट्रेनें रुक जाती हैं। आप यहाँ संसद में हमसे पैसा ले रही हैं तो आप भी एक बात याद रखिए कि आप 500 करोड़

रुपये ले रही हैं और 100 करोड़ रुपये आप कॉमनवेल्थ गेम्स में दे रही हैं, इसमें फिर घपले की बात भी आएगी, जिसे बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी आप उसको दे रही हैं।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बिहार बहुत ही गरीब राज्य रहा है। बिहार आपका भाई ही रहा है, क्योंकि पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब एक रहे हैं ..(व्यवधान).. हमने रेलवे में 58 हजार करोड़ रुपये बिहार को दिये हैं। हमने वहाँ पाँच प्रोजेक्ट्स चलवाये। ऐसा नहीं कि उनका केवल शिलान्यास हुआ बल्कि उन सभी प्रोजेक्ट्स की मंजूरी भी हो गयी थी। उन सभी के लिए पैसा सैंक्शन हो गया था कि आप पाँच फैक्ट्री वहाँ लगाएँगे। जब हमने आपसे सवाल पूछा था तो आपने 2010-11 में एक फैक्ट्री चालू करने की बात तो कही, लेकिन बाकी चार के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि बिहार बहुत पिछड़ा है, इसके लिए आप जरूर ध्यान दीजिए।

मंत्री महोदया, मैं एक बात आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मैं पटना में दानापुर के डी.आर.एम. से मिलने गया था। मैंने उनसे कहा कि जो ट्रेनें पटना से बक्सर, पटना से मोकामा और पटना से गया जाती हैं, जब ये ट्रेनें दिन में चलती हैं तो उनको गाँव के लोग कहीं भी, बिना किसी स्टेशन के हाथ देकर रुकवा देते हैं।

(2टी/एनबी पर क्रमशः)

NB/TMV/2T/4.10

श्री राजनीति प्रसाद (क्रमागत) : कहते हैं - गाड़ी रोको, हम आ रहे हैं और जहां वे चाहते हैं, उतर जाते हैं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : आपका 5 मिनट का समय था, अब 4 मिनट हो चुके हैं।

श्री राजनीति प्रसाद : जब मैं वहां DRM से मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जब मैं DGP से मिलने गया, तो उन्होंने भी कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दिन में जो ट्रेनें पटना से मुकामा, पटना से गया और पटना से बक्सर जाती हैं, उन ट्रेनों का कोई मालिक नहीं होता है, वे कहीं भी रुक जाती हैं,

उनमें से लोग कहीं भी उतर जाते हैं। यह बड़ी समस्या है। वहां जितनी फोर्स थी, वह पूरी फोर्स उठाकर आप बंगाल में ले गई हैं और बिहार में आज RPF की कोई फोर्स नहीं है, यह मुझे बताया गया है। मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में कुछ स्पष्टीकरण दें।

उपसभाध्यक्ष जी, दूसरी बात यह है कि हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि आप ट्रेन से ज्यादा चलते हैं। चूंकि मैं गरीब प्रदेश का आदमी हूं, इसलिए ट्रेन से ज्यादा चलता हूं। जब मैं ट्रेन में चलता हूं, तो मुझे दो बातें याद आती हैं - एक तो यह कि पता नहीं आज कौन सा खाना खाने के लिए मिलेगा और दूसरा यह कि यह ट्रेन कब पहुंचेगी। मैंने आज ही सवाल किया था कि आप कितनी भी स्पीड से ट्रेन को चलाइए, यह कहा जाता है कि right time पर पहुंच रही है, लेकिन आधे-आधे घंटे, एक-एक घंटे, डेढ़-डेढ़ घंटे तक ट्रेन outer पर खड़ी रहती है। इस बारे में आप जरूर विचार करिए।

उपसभाध्यक्ष(प्रो. पी.जे. कुरियन) : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राजनीति प्रसाद : उपसभाध्यक्ष जी, मुझे 2 मिनट और दे दीजिए।

उपसभाध्यक्ष : आपके 6 मिनट हो गए हैं, बाकी सभी लोगों ने 5-5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दी है।

श्री राजनीति प्रसाद : उपसभाध्यक्ष जी, अभी हाल के दिनों में बिहार में ट्रेनों के अंदर लूटमार हुई है। आप कहते हैं कि इसे देखना बिहार का काम है। ट्रेन आपकी, ट्रेन में सभी चीजें आपकी, पटरियां आपकी, RPF आपकी और वे लोग RPF की uniform पहनकर ट्रेन में डकैती करते हैं। आपकी intelligence कहां गई? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस ओर ध्यान दीजिए।

उपसभाध्यक्ष : आपकी बात हो गई, पांच मिनट हो गए, बहुत ज्यादा समय हो गया।

श्री राजनीति प्रसाद : उपसभाध्यक्ष जी, एक आखिरी मुद्दा उठाकर मैं अपनी बात आधे मिनट में खत्म करूंगा। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में एक रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम Sambhal है, Sambhal के आगे कोई भी गाड़ी नहीं जाती है। यहां पर रेल लाइन खत्म हो

जाती है। आज़ादी से लेकर आज तक यहां से कोई भी पैसेंजर ट्रेन दिल्ली तक नहीं चली है। Sambhal से मुरादाबाद के बीच पैसेंजर ट्रेन चलती है। मेरी रेल मंत्री महोदया से गुज़ारिश है कि चूंकि इस इलाके में ज्यादातर गरीब और अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, इसलिए जो भी पैसेंजर ट्रेनें मुरादाबाद और दिल्ली के बीच चलती हैं, उनमें से किसी ट्रेन को Sambhal तक चलाया जाए। धन्यवाद।

(समाप्त)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Shri Anil Madhav Dave. Your party's time is over. So, you take only two or three minutes.

श्री अनिल माधव दवे (मध्य प्रदेश) : सर, मैं 5 मिनट का समय लूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN: Your party's time is over. Then I am not calling you.

श्री अनिल माधव दवे : उपसभाध्यक्ष जी, मैं विशेषकर मध्य प्रदेश के संबंध में आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले ऐसे हैं, जिनके अंदर आज़ादी के 60 सालों के बाद भी रेल सेवा नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के दो हिस्से ऐसे हैं, जहां रेलवे की सेवा नहीं है। एक है - धार, झाबुआ, बड़वानी और खरगौन। चूंकि आप खरगौन की हैं, इसलिए मैं आपका पक्ष भी रख रहा हूं। दूसरा हिस्सा है - मंडला, डिंडोरी, बालाघाट और छिन्दवाड़ा। कहने को इनके किनारे से रेल गुज़रती है, लेकिन रायसेन ऐसा ज़िला है, जहां आज तक रेल नहीं है। कहने के लिए कोई कह देता है कि उसके बाजू में एक किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है, लेकिन अगर हम समग्र विकास की ओर ध्यान दें, तो मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के budget allocation प्रस्तावों में आज नहीं तो भविष्य में अवश्य इसको शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए।

(2U/VNK पर क्रमशः)

श्री अनिल माधव दवे (क्रमागत): दूसरा, विशेष करके झाबुआ-खरगौन-बड़वानी-अलीराजपुर वाला जो क्षेत्र है, इसके अंदर हमें कभी न कभी रेलवे पर आधारित उद्योगों के संबंध में भी सोचना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही उपेक्षित है। मैं दो-तीन बजट से देख रहा हूँ कि शायद कुछ हो जाएगा, शायद कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी तक उस विषय में कुछ नहीं हो पा रहा है।

महोदय, सुबह भी मैं इस बात को कह रहा था कि रेलवे के वर्क कल्चर के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ समय से ऐसे लोगों ने इसका नेतृत्व कर लिया है, जिनके कारण तीन अलग-अलग विषयों के अंदर बात बिगड़ गई है। False Financial Facts Budget के अंदर रख करके, जिसके लिए आपने कहा था कि मैं white paper दूंगी, लेकिन वह उतना white नहीं बनता है, जितना white बनना था, वह dirty white था। यह अच्छा होता, अगर वह total white बन जाता, जिससे कम से कम यह मालूम पड़ता कि किसी के प्रयत्नों के कारण रेलवे की मूल ढ़ाचागत व्यवस्था के अंदर एक बहुत बड़ी खराबी आई है। हमने human resource के मामले में जिस प्रकार का recruitment किया है, भारत के अंदर केन्द्र सरकार के जितने भी संस्थान हैं, उन सब के अंदर अगर कहीं सबसे अच्छा काम का वातावरण था, तो वह रेलवे में था। चूंकि मैं रेलवे कर्मचारी का बेटा हूँ और मैंने रेलवे क्वाटर्स में अपना जीवन जीया है, इसलिए मैं जानता हूँ कि working की दृष्टि से रेलवे का atmosphere कितना अच्छा था। पिछले 20 सालों के अंदर रेलवे के अंदर एचआर के क्षेत्र में recruitment के लेवल पर गड़बड़ हुई है। उसके अंदर कभी कोई आता है और कहने लगता है कि रेलवे में कुल्हड़ मिलेगा। कहां है भैया, कुल्हड़? आज की तारीख में डिब्बे के अंदर पीने का पानी नहीं है, बाकी की बात तो छोड़ दीजिए। कोई कहता है कि खादी की चादर मिलेगी, हम गांधी के प्रवर्त्तक हैं। जिन लोगों ने खादी की चादरों की बात की, सुबह हम शताब्दी एक्सप्रेस की बात कर रहे थे, शताब्दी एक्सप्रेस के अंदर से "वैष्णव जन तो तैने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे"

गीत इसलिए हटा दिया गया कि यह गीत सांप्रदायिक है। बताइए, अब यह कोई तरीका है काम करने का। (समय की घंटी)।

सर, मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि रेलवे के वर्किंग कल्चर के ऊपर ध्यान दे देंगे, तो मुझे लगता है कि चीज पर्याप्त हो जाएगी। (समय की घंटी)।

सर, मैं अंतिम बात कह कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। अगर आप आने वाले financial year के अंदर इतना कर दीजिए कि डिब्बे में पीने के लिए साफ पानी मिल जाए। रेलवे लाइन के दोनों तरफ ट्रेक पर बोलतें फिंकी रहती हैं और हर रेलवे स्टेशन पर बच्चे उसी को रिपेक करके एक-एक, दो-दो रुपए में पानी का बोतल दे रहे हैं, इस environmental hazard के कारण लोग गलत पानी पी रहे हैं। ममता जी, इतना कर दीजिए। मध्य प्रदेश की बातों की ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया और अगर राष्ट्रीय स्तर पर वर्क कल्चर के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, तो बहुत ठीक होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

श्री ईश्वर सिंह (हरियाणा): सर, रेलवे हमारे देश की एक जीवन रेखा है। रेलवे से आम आदमी का वास्ता है। हमारी रेल मंत्री बधाई की पात्र हैं। ये एक सफल और निपुण मंत्री साबित हुई हैं। मैं इनको बधाई देता हूँ। कई चीजें हैं, जैसे आपकी सादगी है, ईमानदारी है, आपको बहुत सख्ताई से मुकाबला करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले भूमि की बात करता हूँ। रेलवे के अंदर 75.7 परसेंट भूमि रेलवे स्टेशनों, रेलवे कलोनियों, रेल लाइन, रेल पथ, आदि की संरचना में गई है और 10.5 परसेंट वृक्षारोपन में गई है। यह रेलवे मिनिस्ट्री खुद भी मानती है कि 15 परसेंट भूमि बिल्कुल खाली है, जो कि किसी भी प्रयोग में नहीं लाई जाती है। मैडम, जब ऐसी भूमि कई सालों से खाली पड़ी हुई है और किसी प्रयोग में नहीं लाई जाती है, तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि वह भूमि भूमिहीन लोगों को दे दी जाए। वह पट्टे पर दे दी जाए या लीज पर दे दी जाए या हिस्सेदारी पर दे दी जाए, इससे एक तरफ तो राष्ट्र को फायदा होगा और दूसरी तरफ जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिलेगा। विशेष कर जो SC

और ST क्लास के लोग हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, मेरा आपसे यह निवेदन है कि उनको यह भूमि allot कर दी जाए। वे इसके मालिक नहीं बनेंगे, वे आपको आपका हिस्सा भी देंगे और आपकी मल्कियत को भी संभाल कर रखेंगे, क्योंकि ऐसी भूमि पर अवैध कब्जे हो रहे हैं।

(2w/MP पर क्रमशः)

MP/2W/4.20

श्री ईश्वर सिंह (क्रमागत) : मेरी दूसरी request आपसे यह है कि जैसे अभी उपसभाध्यक्ष महोदय ने कहा कि आपका हरियाणा छोटा सा स्टेट है, इसलिए आपको बोलने के लिए एक मिनट मिलेगा। हरियाणा बेशक छोटा है, परंतु देश के अंदर उसकी अहम भूमिका है। हमारा स्टेट धान का कटोरा है और वह wheat का बहुत बड़ा दरिया है, जो सारे देश को भरता है। हमारी फसल का एक-चौथाई हिस्सा देश में जाता है। राजस्व भी हम सबसे ज्यादा देते हैं लेकिन जहां तक यात्री सेवा में हमारा हिस्सा होना चाहिए, वह नगण्य है।

मैडम, आपने पिछले सैशन में कुरुक्षेत्र के लिए announce किया था। आज जिस सीट पर आप बैठी हैं, उसी सीट से आपने कुरुक्षेत्र के लिए announce किया था। ...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : ईश्वर सिंह जी, चेयर पर मैडम नहीं बैठी हैं। आप चेयर को address कीजिए।

श्री ईश्वर सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मैडम को सम्बोधित कर रहा था कि पिछले सैशन में ...(व्यवधान)... सर, पिछले बजट में मैडम ने कहा था कि कुरुक्षेत्र को 1st class station घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन दुख की बात है कि जो गीता की स्थली है, जहां हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है, जहां सूर्य ग्रहण मनाए जाते हैं, उसको इस साल छोड़ दिया गया है। दूसरे, एक बात सुनने में यह आई है कि एक विशेषज्ञ समिति बनी है, उसने 64 multi functional station घोषित किए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह कहना चाहता हूं कि मैडम, कुरुक्षेत्र से ढांढ, पबनावा, टीक, कलायत आदि जो स्टेशन हैं, मैंने इन स्टेशनों पर खुद जाकर देखा है कि पीने की पानी की कहीं सुविधा नहीं है। सीवरेज की कहीं

सुविधा नहीं है। वे कहते हैं कि सीवरेज स्टेट का महकमा है और सीवरेज का रेलवे स्टेशनों के साथ कहीं connection नहीं जुड़ता है। सभी स्टेशनों के साथ ऐसा है। सभी रेलवे स्टेशनों ने सीवरेज की अपनी व्यवस्था की है, जो कि नगण्य है और जो गांव के स्टेशन हैं, वे पानी की व्यवस्था के बिना इसी तरह से अधूरे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सबसे बड़ी बात यह कहूंगा कि जो कुरुक्षेत्र से वाया पटियाला वाया चीका-गुला एक रेलवे लाइन मंज़ूर की है, वह इस बजट के अंदर लाई जाए। इससे हरियाणा का काफी portion पंजाब के साथ जुड़ेगा। एक और अहम बात यह है कि नरवाणा से कुरुक्षेत्र तक अंग्रेज़ों के जमाने से एक लाइन निकली है, आज तक उसको डबल नहीं किया गया, उसका विद्युतीकरण नहीं किया गया, माल-भाड़े में सबसे ज्यादा आमदनी वहां है, यह आपका रिकॉर्ड बताता है, परंतु यात्री सुविधा के मामले में सदियों से यहां यात्रियों के लिए, कर्मचारियों के लिए पानी नहीं है। ..(समय की घंटी).. सर, एक मिनट... मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि रेलवे में जो सबसे बड़ा defect है, वह ठेकेदारी प्रथा है। ठेकेदारी प्रथा में स्क्रैप है, लाइन बिछाने का काम है, infrastructure का काम है, कार-पार्किंग तक का काम है। इस ठेकेदारी प्रथा की वजह से रेलवे महकमा ज्यादा बदनाम है, इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। यह महकमा जब अपने हॉस्पिटल बनाता है, अपने स्कूल बनाता है तो इन कामों को भी वह अपने अंडर में ले और जी.आर.पी. ...(समय की घंटी)... सर, जी.आर.पी. एक ऐसा महकमा है, जैसा सुबह मैडम ने कहा कि यह स्टेट का महकमा है, इसके अंदर करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा है। वहां का ही आदमी जो स्टेशन पर तैनात है, वह जानता है कि कौन चोर है, कौन डकैत है, वह ज्यादा शुल्क देकर ...(समय की घंटी)....

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : बैठिए....बैठिए।

श्री ईश्वर सिंह : सर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे टाइम दिया, परंतु टाइम भी आपने तीन ही मिनट का दिया, धन्यवाद। (समाप्त)

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह (झारखंड) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं माननीय रेल मंत्री महोदया से आग्रह करना चाहता हूं और मैंने पहले भी बार-बार आग्रह किया है कि मैं झारखंड और देवघर का रहने वाला हूं और आपका पड़ोसी भी हूं। उसी लाइन से होकर कोलकाता हावड़ा ट्रेन जाती है, हम उसी लाइन पर स्थित हैं। देवघर झारखंड का सबसे पवित्र और famous तीर्थ स्थान है।

(2X/SC पर क्रमशः)

2x/4.25/sc-ks

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह (क्रमागत) : हम बराबर यह मांग करते रहे हैं कि झारखंड में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जब आप मंत्री थी, उस समय रेल लाइन के निर्माण की जो आधारशिला रखी गयी थी, अभी तक वह लाइन अधूरी है। उस लाइन को पूरा किया जाए। दूसरा राजधानी एक्सप्रेस उधर से तीन दिन Jasidih रुकती थी, उसे एक दिन कर दिया गया है। आपसे आग्रह है कि इसे तीन दिन किया जाए। महोदय, Jasidih में बहुत बड़ी आबादी है, वहां पर 17-18 हजार की population है। उसको जोड़ने के लिए, समपार पर रेल फाटक बनाने के लिए मैंने लिखा था कि मैं अपने एमपी फंड से पैसा दूंगा। लेकिन आज तक रेल मंत्रालय ने इसका जवाब नहीं दिया कि आप हमारे पैसे का उपयोग करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं। इस प्रकार से यह काम नहीं हुआ। महोदय, देवघर-दुमका-रामपुर रेल लाइन को अतिशीघ्र पूरा किया जाए। इसी तरह से गिरीडीह-हजारीबाग-रांची रेल लाइन, देवघर-बांका-सुल्तानगंज रेल लाइन, जमालपुर रेल कारखाना को भी उन्नत किया जाए - यही मेरी मुख्य मांग है। महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए दो मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं मंत्री महोदया से आग्रह करूंगा कि अपने पड़ोसी पर भी ध्यान दें। धन्यवाद।

(समाप्त)

SHRI BHARATKUMAR RAUT (MAHARASHTRA): Thank you, Sir, for giving me time. It was because of miscommunication; I thought that the Nalanda University

Bill was coming up first and so, I did not give my name. I will give my demands only in bullet points to Mamta *didi*.

Firstly, I must thank her for giving a railway station in the Konkan region of Konkan Railways. Konkan in Maharashtra has four districts, namely, Thane, Raigad, Ratnagiri and Sindhudurg. All trains passing through this region were not getting stations. Now, you have given one station. I am happy about it. But I am rather surprised how it happened that you have given the station; the train stops at Kankrauli in the Sindhudurg district. But it has no booking facility. There is no quota of seats available at Kankrauli Railway Staion. So, what is the point? So, my demand is that you should provide the booking facility at this railway station.

My next point is about recruitment. You have regional Railway Recruitment Boards. My request to you is that, for recruitment in class III and class IV, unskilled and non-engineering staff positions, you must recruit only local people. There is no point in a person coming from the south and going to the north or from the east to the west and so on. That is not useful. Therefore, the selection for recruitment of non-engineering staff must be done from amongst the local people.

Coming to my third request, in the last Budget, Madam, you had given 105 extra local trains for the suburban railway of Mumbai. We all clapped. I thumped the benches. Where are those trains? What happened to them? Almost half the year has gone by and not one new train has started. I can understand your problem. If we have to have 105 extra local trains, you should have those many tracks. There are no tracks. Where will you run those trains? Trains can't run on

roads! Therefore, don't promise anything unless you are very sure of what you can do.

My last point is on behalf of all the MPs. We, MPs, get railway booking. My request to you is, allow us the online booking facility. That online booking facility is not available to us. If we give our IC number, we should be able to get online booking. That is our day-to-day requirement. Please, accept it.

(Ends)

श्री राम कृपाल यादव (बिहार) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने बहुत कृपा की। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया का ध्यान केवल कुछ प्वाइंट्स की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैडम हमारी दीदी हैं। महोदय, बिहार के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थीं, जो शायद pending पड़ी हुई हैं। मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा कि कौन सी महत्वपूर्ण योजनाए हैं, मैडम को मालूम है। कई महत्वपूर्ण रेल लाइनें बिछानी थीं, कई फैक्ट्रीज़ थीं, जिनकी चर्चा माननीय सदस्य श्री राजनीति प्रसाद जी ने की है। उनकी तरफ अगर मैडम का ध्यान चला जाए तो बड़ी कृपा होगी। सर,मैडम तो विशाल हृदय की व्यक्तित्व हैं।

(2वाई-एमसीएम पर क्रमशः)

SC/MCM-KGG/2Y/4-30

श्री राम कृपाल यादव (क्रमागत) : और आम लोगों की तरह हैं। मैं समझता हूं कि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, देश की आजादी के बाद से वहां कोई इण्डस्ट्री नहीं लगी है और उसका हक भी मारा गया है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। महोदय, मैं आपके माध्यम से मैडम से यह निवेदन करुंगा कि आपके मन में बिहार के प्रति भी वही भावना है, जो बंगाल के प्रति है, क्योंकि बंगाल और बिहार कभी न कभी भाई रहे हैं और यह उसी का पार्ट है। जो महत्वपूर्ण योजना है फैक्टरी सहित, उस पर आप कृपया विशेष ध्यान दें, ताकि वहां के

आर्थिक विकास में गति हो और बिहार विकास में थोड़ा आगे बढ़ सके। मुझे यह ही निवेदन करना है।

पटना जंक्शन के ठीक बगल में एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, जहां किडनी और हार्ट के इलाज के विशेष इंतजाम होंगे। यह सिर्फ रेलवे स्टाफ के लिए ही नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण योजना है। मगर इसका काम धीमा पड़ गया है, जबकि इसका उदघाटन भी हो गया है। केवल आउटडोर काम हो रहा है। अतः हॉस्पिटल के काम में गति आए और जिस परपज़ से इस हॉस्पिटल का निर्माण कराया जा रहा है, उसकी उपयुक्तता हो सके, उसके लिए हम मैडम से निवेदन करेंगे।

दूसरा, मैडम, पटना जंक्शन पर आप जाएं। मैं तो निवेदन करुंगा, आप तो रेल से सफर करती हैं तथा स्पेशल ट्रेन को भी आप अवॉइड करती हैं। कभी, इन दिनों कई महत्वपूर्ण अवसर मिले हैं, मगर आपकी व्यवस्तता रहती है। मैं आपसे निवेदन करुंगा कि पटना जंक्शन पर आप जरा एक बार आ जाइए, जो हालात वहां के हैं हम उसका यहां वर्णन नहीं कर सकते। पटना जंक्शन के ठीक सामने एक शौचालय का निर्माण करवाया गया है। लेकिन वहां तक जाना भी मुश्किल है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वहां आप जाएं या अपने किसी प्रतिनिधि का भेजकर इसको दिखवाइए कि किन हालात में पटना जंक्शन की स्थिति है। ---------(घंटी) वहां लाखों लोग आते-जाते हैं लेकिनन वहां सफाई की स्थिति बदतर है।

बिहार के अंदर पैसेंजर्स ट्रेन्स की हालत भी बहुत खराब है। वहां जो लोकल ट्रेन्स चलती हैं उनकी बत्ती बंद रहती है, उनके शौचालय की स्थिति बहुत खराब है, उनकी खिड़कियां टूटी रहती हैं। मैडम, आप तो आम लोगों की तरह हैं, वह फर्स्ट क्लास वाली मैडम नहीं है, जो हमारी दीदी है। मेरा निवेदन यह होगा कि कम से कम आप उस पर जरूर ध्यान दें.....(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay, please sit down. (Interruptions)

श्री राम कृपाल यादव : खाली पाइंट्स ही हैं, मैं खत्म कर दूंगा, दो पोइंट और हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Your time is over, please sit down. (Interruptions)

श्री राम कृपाल यादव : बस खत्म कर दूंगा, दो पाइंट और हैं।.....(व्यवधान) मैं कोई भाषण नहीं कर रहा हूं, केवल आपके माध्यम से दीदी का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं और शायद पहली दफा हमको मैडम के सामने रेलवे पर बोलने का अवसर मिल रहा है। इसलिए मैंने निवेदन किया है। एक और महत्वपूर्ण मामला है, जिसके बारे मैं मैंने मैडम से व्यक्तिगत रूप से उनके चैम्बर में जाकर के निवेदन किया था। पटना में विभिन्न जगहों से दिल्ली से, कोलकाता से ट्रेन का जो कोटा निर्धारित था उनका कोटा आधे से कम कर दिया गया है, जबकि इतनी बड़ी तादाद में वहां की आबादी है, वहां के लोग बाहर ज्यादा रहते हैं। जब कोटा खत्म हो जाएगा तो लोग कैसे जा पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन यह होगा कि या तो कोटा फुलफिल करने का काम कीजिए।.....(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष : बस,बस।

श्री राम कृपाल यादव : सर, अंत में मैं निवेदन करुंगा कि पटना के दानापुर में जो डी0आर0एम0 कार्यालय है.....(व्यवधान) बस, मैं खत्म कर रह हूं। वहां जो कर्मचारियों के रहने के आवास हैं उनकी स्थिति बद से बदतर है। कृपया उस तरफ भी ध्यान दीजिए। इन्ही चंद शब्दों के साथ मुझे विश्वास है कि जब मैडम जवाब देंगी तो इन पर गौर करेंगी। अन्त में, सर.....(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN: Mr. Yadav, it is not going on record, please sit down. (Interruptions)

श्री राम कृपाल यादव : *

---

* **Not recorded.**

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Salim Ansari now. (Interruptions) What is this? (Interruptions) बाकी लिख कर दे दो।.....(व्यवधान) सुनिए, बाकी लिख कर दे दो।.....आप सुनते नहीं हैं।.....बैठो, बैठो, टाइम नहीं है।.....(व्यवधान) Mr. Yadav, it is not good. (Interruptions) Please sit down. It is not going on record; Mr. Salim Ansari now. (Interruptions)

श्री सालिम अन्सारी (उत्तर प्रदेश) : माननीय डिप्टी स्पीकर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे टाइम दिया।.....(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN: Mr. Rajniti Prasad, if a Member or a leader gives an assurance to the Chair, it should be honoured. That is what I am saying. You spoke from your party, yet you requested that Mr. Yadav be given two minutes. Instead of two, I gave him more than four minutes. But, even then, he is not obeying the Chair. It is not proper. Please take note of it.

(Followed by gs/2z)

GS-TDB/2Z/4.35

श्री सालिम अन्सारी(उत्तर प्रदेश) : शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। आपने मुझे दो मिनट बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री, कुमारी ममता बनर्जी का ध्यान उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की ओर ले जाना चाहता हूं। पूर्वांचल अति पिछड़ा है और वहां पर मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन है। वह दो किलोमीटर लम्बा है और दो किलोमीटर चौड़ा है और वहां एक किलोमीटर लम्बा प्लेट फार्म है। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जब जिंदा थे, तो 1995 में मऊ जंक्शन को टर्मिनल बनाने की घोषणा की गई थी। यह बनारस और गोरखपुर के बीचों बीच पड़ता है। मैं माननीया रेल मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 1995 की वह घोषणा, जो मऊ को टर्मिनल बनाने के लिए की गई थी, उसका क्या हुआ ? वहां पर पर्याप्त जमीन है, वहां पर पर्याप्त सब कुछ है, अगर मऊ को टर्मिनल बनाया जाए, तो इससे वहां की जनता को

काफी फायदा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का दिल है। टर्मिनल बनाने के बाद वहां से तमाम ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। रेलवे के पास मऊ में बहुत जगह है, वहां पर एक किलो मीटर लम्बा रेलवे प्लेटफार्म है, यह मैंने आपको पहले ही बताया है। उससे 40 किलो मीटर दूर आजमगढ़ पड़ता है, जहां से कैफियात एक्सप्रेस बनकर चलती है। वहां के लोगों की यह डिमांड है कि कैफियात एक्सप्रेस को मऊ से चलाया जाए। मऊ में पहले रेलवे का loco-shed था, उसमें रेलवे के डेढ़ हजार कर्मचारी काम करते थे, अब वह loco-shed खत्म हो गया है। वहां पर रेलवे की सारी प्रापर्टी वैसे ही पड़ी है। अगर ममता दीदी मऊ जंक्शन की ओर थोड़ा-सा ध्यान दे दें और मऊ में रेलवे टर्मिनल बना दें, तो मैं समझता हूं कि इससे बनारस पर भी लोड कम पड़ेगा और गोरखपुर पर भी लोड कम होगा। मेरी मांग है कि मऊ टर्मिनल को फंक्शनिंग किया जाए, वहां से ट्रेनों को मूव किया जाए, क्योंकि वहां पर आपके पास पर्याप्त मात्रा में जमीन है, यही मुझे कहना है। धन्यवाद।

(समाप्त)

SHRI SILVIUS CONDPAN (ASSAM): Mr. Vice-Chairman, Sir, as you know, the North-Eastern Region, except Railway, does not depend on any other mode of transportation for its development. We fully depend upon the Railway system. I would like to draw the attention of the hon. Railway Minister that the people of the North-East depend only upon the Railway system for their economic development. The Railway system which was started during the British regime, today it has not seen more and more development after 60 years of Independence. So, I draw the attention of the hon. Railway Minister, through you, Sir, to all these problems we have. Sir, whatever points have been submitted by my friend from Assam, Shri Kumar Deepak Das, because you are cutting down our time, I fully subscribe to all his submissions. But, from my side, I again

reiterate that many projects of national importance are pending for implementation in the North-Eastern Region. I request the hon. Railway Minister to use her good offices in the Ministry so that all the projects of national importance in the North-Eastern Region are implemented quickly. These are the projects of national importance, these are committed projects to the people of North-East, but they are not seeing the light of the day. So, I once again request the Railway Minister, I am not going to elaborate it because there is no time, to expedite all the projects of the North-Eastern Region. Sir, with these submissions, as you had said that I should confine to the time-limit, I have confined to it, I conclude my speech. Thank you very much, Sir.

(End)

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (ASSAM): Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister that in her Budget Speech she had announced that there would be a Wagon Factory in Guwahati on PPP mode. I want to know from the hon. Minister the present status of this project, and I would like to request the hon. Railway Minister – we have already requested it in the last Budget Session – that instead of taking up this project on Public-Private-Partnership, it should be taken up by the Railway Department itself.

(Contd. by 3a-kls)

KLS/3A-4.40

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (CONTD): In her budget speech, the hon. Railway Minister announced that there will be a master plan for the North Eastern Region and in consultation with the North Eastern Region Planning Commission

she is going to implement this project. I want to know from the Minister from where finance is coming because there is no reflection at all in the General Budget about this plan, and secondly, budgetary provision for the North Eastern Council has not been increased. So, I want to know for this plan where is the money coming from. One of the most interesting things of our region is that there are about 9000 posts of Grade IV and Grade III posts which are vacant in the NF Railway which has headquarters at Maligaon, Guwahati. You know the problems of the North Eastern Region. Insurgency problem of the North Eastern Region is known to everybody. One of the basic reasons for the insurgency of the North Eastern Region is unemployment. Looking at the unemployment, I would like to know whether the Railway Minister is going to announce a special recruitment policy in the interest of the North Eastern Region because we have seen all the times the youth of the North Eastern Region are deprived. Not during your time but before that more than 200 youths were appointed in the NF Railway without any advertisement, without any interview. Out of these 200 youths not a single boy was selected from the North Eastern Region. This is the reason we are suffering a lot. We would like to request the hon. Railway Minister to kindly declare a special recruitment policy considering the problems faced by the youths of the North Eastern Region. (Time-bell) I would take only one minute, Sir. Sir, there are a lot of projects announced as national projects and one of these projects is the Bogibeel bridge. The foundation stone of this bridge was laid in 1997. But till today this bridge has not been completed. I would like to request the hon. Minister to give some attention on the projects for the North Eastern

Region like the Bogibeel bridge, like broad gauge lines and implement the projects of the North Eastern Region as early as possible. The last request I would like to make to the hon. Minster is to introduce electrical rail line and double line in the North Eastern Region. Guwahati is the hub of North Eastern Region and there should be a superfast train, a bullet train, between Guwahati and Mumbai because the highest number of cancer patients of our country is coming from the North Eastern Region. Looking at the number of cancer patients, will the hon. Minister introduce a bullet train between Guwahati and Mumbai? Thank you.

(Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Before hon. Minister's reply, I think Shri Ahammed wants a small intervention for clarification. Yes, please.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI E. AHAMMED): Sir, the Railways and its employees are having excellent relationship and Railways is one institution which has even set apart Rs.55,000 crores of rupees for their salary increase because of the Pay Commission. An hon. Member of this House, Mr. Rajeeve, while speaking here said the Railways has not paid the festival allowance, the Onam allowance to the employees. It is totally incorrect. As a matter of fact, there is a system prevailing in the Railways, the railway unions and the management, they would discuss and do it. As a matter of fact, what happened was that the salaries for the Railways staff are given early during festival season on their request. As they requested, the salary was given on 20th, that is, today, as per their earlier request. That is also the engineering wing of the staff of Trivandrum Division. No other people have come forward.

Whoever wants, the Railways is ready. My friend has tried to create a bad impression about Railways. I do not know why he has done it. He also referred my name. It is quite unfortunate. I just wanted to dispel the impression that he sought to create here against the Railways. Thank you.

(Ends)

(Followed by 3B/SSS)

SSS-LT/4.45/3B/

THE MINISTER OF RAILWAYS (KM. MAMATA BANERJEE): I am grateful Sir, to the hon. Members. मैं पार्लियामेंट की आभारी हूं कि आप लोगों ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, बहुत सारी इम्पोर्टेन्ट बातें भी की हैं, लेकिन यह हमारा कोई जनरल बजट नहीं है, यह जो डिस्कशन है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेन्स चाहिए, स्टॉपेज चाहिए, ये डिमांड्स हर दफा कर सकते हैं, You can make it. लेकिन यह जो है, यह It is just a supplementary demand. Technically, it is Rs. 398 crores. It is for the North-Eastern project and again it will be reimbursed from the Finance Ministry and according to our Budget announced we kept a provision for the Commonwealth Games. But, yesterday also I clarified in the Lok Sabha that we are leading partners of Common wealth Games but, we will see the credentials, then, we will think about the matter. But, because of the Budget announcements, we have to keep the provision. We have kept the provision and there are some technical infrastructural projects which we announced in the Budget. It is only a technical thing. पर जितने भी सजेशन्स मिले हैं। think, sometimes if we speak also इसमें अच्छे सजेशन्स भी मिले हैं। So, it is good to listen. लैसन और लर्निंग में कभी-कभी थोड़ी अच्छी चीज भी मिलती है

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

Thank you very much to all our friends. Twenty MPs participated in Supplementary Demands. If I mention their names, it is Shri Avinash Rai Khanna from BJP party, Shri Nandi Yellaiah from INC, Shri Naresh Chandra Agrawal, BSP – I am not mentioning the party names – Shri Moinul Hassan, Shri S. Thangavelu, Shri Ranjitsinh Vijaysinh Mohite-Patil, Shri Mahendra Mohan, Shri Ram Kripal Yadav, Shri A. Elavarasan, Shri Achuthan, Shri Kumar Deepak Das, Shri Pyarimohan Mohapatra, Shri Rajniti Prasad, Shri Anil Madhav Dave, Shri Ishwar Singh, Shri Jai Prakash Narayan Singh, Shri Bharatkumar Raut, Shri Ram Kripal Yadav, कभी-कभी एम.पी. का नाम बोलने से वे भी रिकॉर्ड में आ जाते हैं। ...(व्यवधान).. It is good to give credit to them also.

SHRI SITARAM YECHURY: I think you have not mentioned the name of any CPI (M) Member.

KM. MAMATA BANERJEE: I have already mentioned Mr. Moinul Hassan's name. Then, Shri Salim Ansari, Shri Silvius Condpan and Shri Birendra Prasad Baishya spoke. About 25 Rajya Sabha MPs participated. Thank you very much for giving your good comments. लेकिन सर, एक बात सच है कि कभी-कभी we are discussing why cleanliness is not there, why coaches are not available, why the food is not good, why every stoppage is not available, why train is not running at the proper time. I appreciate all of them. Yes, you need to discuss the matter. It is the concern of the House. It is not only the concern of the House but the concern of the people of this country. I appreciate that. मुझे भी लगता है, लेकिन बात एक है। जब छोटा बच्चा होता है, तो उसकी एडुकेशन के लिए, ऐसा पहले नहीं था, लेकिन अभी उसकी

हायर एडुकेशन के लिए पहले से इंश्योरेंस करके रखते हैं, पहले से प्लानिंग करके रखते हैं, मेडिक्लेम बनाते हैं। देखिए, एम.पी., एम.एल.एज. में सभी को तो एडवांटेज नहीं मिलती है। एम.एल.ए., एम.पीज. को एडवांटेज रहती है। जब तक वह एम.एल.ए, एम.पी. रहता है, एक्स एम.पीज. रहता है, तब तक रहती है। जो मैंने देखा है, उसके हिसाब से एम.पीज. के लिए मेडिकल फेसिलिटीज थोड़ी सी कम है, एम.एल.ए. को मेडिकल फेसिलिटी ज्यादा है। यह बहुत सारे स्टेट्स में डिफर करती है, अभी वह बात नहीं है, लेकिन आम इंसान के लिए इतनी फेसिलिटी नहीं है। अभी प्लानिंग करके मेडिक्लेम करते हैं कि अगर हमारी जिंदगी खतरे में आ जाए I can at least go for treatment. आप हमको बताइए। I am Railway Minister for the last one year plus one or two months. Earlier, I worked for one year and five months. I quote Abraham Lincoln in this regard. "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you cannot fool all the people all of the time." (Contd. by 3C/NBR)

AKG-NBR/3C/4.50

KM. MAMATA BANERJEE (CONTD.): Why am I quoting this? If you say only in this House that आपने क्यों नहीं किया, why are you staying in Kolkata? Why are you not in Delhi? You tell me why have you people not done this. We are the citizens of this country. We have just celebrated the 64th year of our Independence. आपने किया, तो कुछ-न-कुछ तो हुआ, लेकिन अभी हमारी आबादी बढ़ रही है, population बढ़ रही है, infrastructure बढ़ रहा है। I am not blaming any of my predecessor, because I don't play political blame game. I don't believe in that. I am not blaming. I can say so many things. I can also raise my figure at some people. मैंने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि मेरी political boundary क्या है। मैं नहीं बोलना चाहूँगी। मैंने यहाँ आने के बाद जो देखा, I cannot disclose all these things to you. I am sorry,

because there are some internal problems and there is also some internal beauty and duty. कभी country की security की बात होती है, तब हम बाहर चर्चा नहीं करते, क्योंकि इसमें हमारी country की इज्जत की बात होती है, हमारी country की security की बात होती है। वैसे ही रेलवे भी एक चीज है, जिसे lifeline of the nation कहा जाता है। हर चीज़ हम बाहर नहीं कहते हैं।

जब मैं यूपीए-II के टाइम second time रेलवे मिनिस्टर हुई, मैंने पूरी चीज़ देखी। इसके बाद मैंने सोचा कि planning करना जरूरी होता है। If you do not do planning for the future, आज अगर कोई मुझे कहे, We need this. Yes, demand तो है, कोच दो, रेक्स दो, ट्रेन दो, लाइन दो, तो planning नहीं होने से हम कहाँ से ले आएँगे? हम पहले भी कह चुके। I feel, sometime, sad for this. अगर कपड़ा खरीदना है, तो दुकान में मिलता है, अगर आप साबुन खरीदते हैं, तो दुकान में मिलता है, लेकिन रेल का कोच दुकान में नहीं मिलता है, अपने देश में बनाने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि पूरी चीज़ें नहीं मिलती हैं। हम जो वैगन का ऑर्डर देते हैं, वह कहीं नहीं मिलता है। Even the coaches are not available. हमारे पास coaches की shortage है। हमारे पास 55 हजार के करीब हैं, लेकिन हमारी shortage आज भी है। हमारे पास 5 हजार से ज्यादा और होने चाहिए। Every year demand बढ़ रही है। पहले पैसेंजर्स 1.8 मिलियन थे, अभी वे 2 करोड़ से ज्यादा हो गए। कभी आप लोगों ने सोचा कि जब 2 करोड़ 20 लाख पैसेंजर्स हो गए हैं, एक करोड़ से दो करोड़, double हो गए, because the Railways is the only passenger-friendly transport system. आसमान में, if you calculate the seating availability of all the airlines throughout the country, including private, it may be between 25,000 to 30,000 passengers go by air and the Railways carry 2 crores! Sir, can you imagine the network, the vast area, more than 8,000 stations, 17,000 trains? It is not a matter of joke. It is a vast network. लेकिन हम लोगों ने शुरू किया, यह 53 हजार से 64 हजार पर आ गया है।

इसको बढ़ाना है। हमें Socially desirable projects करना है, इसको गाँव-गाँव से लेकर जाना है, suburban system भी और बढ़िया होना है। जैसे मैं कभी-कभी सोच रही हूँ कि कानपुर से बनारस क्यों नहीं local होगा, बनारस से लखनऊ क्यों नहीं होगा, ऐसे छोटे-छोटे काम। इनको पूरा करने के लिए अभी बहुत सारे vision आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए planning करने की जरूरत है। इसीलिए मैंने यहाँ आने के बाद जो पहला काम किया, मैंने Vision 2020 किया, क्योंकि मैंने commitment किया था। मैंने 3 महीने-6 महीने के अन्दर आपको Vision 2020 इसलिए दिया कि 10 साल के अन्दर कितने किलोमीटर लाइन हो सकती है, 10 साल के अन्दर कितनी इंडस्ट्री हो सकती है, 10 साल के अन्दर कितने कोच मिलने चाहिए, 10 साल के अन्दर कैसे accidents को रोक सकते हैं, 10 साल के अन्दर कैसी employment potentiality हो सकती है, I covered everything in the Vision 2020 document. I request all my colleagues of this House to please go through that vision document.

What we have done in one year? हम लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने catering policy के बारे में कहा। मैंने नई catering policy बनाई, announce भी कर दिया, लेकिन पुरानी चीज़ से नई चीज़ में आने में थोड़ा टाइम लगता है। हम लोगों ने 6 महीने टाइम लिया। इसके लिए हमें best kitchen बनाना है। अगर अच्छा खाना बनाना है, तो best kitchen बनाना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम एक दिन के लिए खाना बनाएँगे।

(3डी/डीएस पर जारी)

-AKG/DS-USY/3D/4.55

कुमारी ममता बनर्जी (क्रमागत): हमें 10 लाख पैसेंजर्स को खाना देना है तो वह एक दिन में तैयार नहीं होता है। सर, 10 लाख लोगों के लिए खाना तैयार करना एक मुश्किल बात होती है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। We need good people and good infrastructure for that. इसके लिए हमने कैटरिंग पॉलिसी को चेंज किया है और हमने न्यू

पॉलिसी अपनायी है। हम चाहते हैं कि रेल का खाना अच्छा मिले, इसकी क्रेडिबिलिटी तथा क्रेडेंशियल्स बनी रहे और पहले की तरह इसकी अच्छी इमेज़ हो। इसके लिए हमने वादा किया था और हमने पॉलिसी अनाउंस कर दी।

सर, हमने एक साल के अंदर व्हाइट पेपर लाने की बात कही थी। Somebody may be happy and somebody may not be happy. But this is not my political White Paper. It is not a black list. It is a truth. Even the CAG has also appreciated that White Paper. तीसरा प्वायंट यह है कि हम एक साल के अंदर कैटरिंग पॉलिसी को लेकर आये। चौथा प्वायंट यह है कि हमने रेलवे में रिक्रुटमेंट के लिए नयी पॉलिसी बनायी। One of our friends from Assam, and also some other friends, raised a point regarding local employment. हमने जो पॉलिसी बनायी है, उसमें यह व्यवस्था है कि एक दिन में examination होगा। अगर examination एक ही दिन होगा तो बिहार से बंगाल, बंगाल से महाराष्ट्र या महाराष्ट्र से चैन्नई कोई नहीं जा सकता है। The regional people will automatically get an opportunity, इसलिए हमने नयी रिक्रुटमेंट पॉलिसी अनाउन्स कर दी। And, you will be happy to know कि हमारा बैकलॉग है, लेकिन वह बैकलॉग पिछले 10 सालों से पूरा क्यों नहीं किया गया? I cannot do it in a day. सर, इसमें नोटिफिकेशन होता है, प्रोसैस होती है और जब हम एम्प्लायमेंट का नोटिस देते हैं तो वह कभी CAT में चला जाता है, कभी कोर्ट में चला जाता है, कभी SAT में चला जाता है और कभी हम रैट हो जाते हैं। यह भी होता है। इसमें कभी-कभी लीगल प्रॉब्लम होती है, कभी पॉलिटिकल प्रॉब्लम होती है, कभी लोकल प्रॉब्लम होती है और कभी-कभी टेक्निकल प्रॉब्लम भी होती है। इसलिए हमने यह प्रोसैस शुरू कर दिया। यह ग्रुप "सी" में भी शुरू हो गया है और सेफ्टी कैटगरी में भी शुरू हो गया है, लेकिन हमारे जो 21 न्यू रिक्रुटमेंट बोर्ड्स हैं, इनमें 20 जगहों पर ग्रुप "सी" का examination भी हुआ और एक जगह में गड़बड़ हुई तो लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। अगर 21 जगह होगा, तो क्या एक जगह गड़बड़ नहीं होगी? अगर कोई गड़बड़ करेगा तो

उसको पकड़ा जाएगा। अगर कोई आदमी गड़बड़ करे तो उसको पकड़ना भी तो जरूरी है? इसके लिए you should appreciate. हमने काम की शुरुआत कर दी है। हमारी जो सेफ्टी कैटगरी है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। Our slogan is correct that safety never sleeps. इसके लिए हमने जान-बूझ कर ऐसा स्लोगन दिया। सेफ्टी को strengthen करने के लिए ही हमने ऐसा स्लोगन दिया। Some people may be unhappy, but I am not unhappy about that. हमको हमारे स्टेट में अच्छा मैसेज दिया जाता है, लेकिन इधर आप लोग थोड़ी गड़बड़ करते हैं, ठीक है। मैं केवल कोलकाता में रहती हूँ, कोई काम नहीं करती हूँ तो क्या इतनी सारी पॉलिसीज़ ऐसे ही बन गईं? ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जिन्हें मैं बताऊँगी। इसीलिए हमने safety never sleeps कहा। सेफ्टी कैटगरी के लिए जो बैकलॉग था, मैं तो एक साल से हूँ, पहले के लोगों ने उसे क्यों नहीं किया? उसमें 10 सालों से भर्ती क्यों नहीं की गयी? Maybe, there were some problems. I am not blaming anybody, लेकिन यह एक दिन में तो नहीं हुआ? उसमें भी सेफ्टी को ध्यान में रखने के लिए हमने अभी एक नयी पॉलिसी अपनायी। हमारे रेलवे में बहुत सारे सेफ्टी कैटगरी के स्टाफ हैं और जो voluntarily retire करते हैं, उनके लिए Safety-related Employment Guarantee Scheme की तरह ही हमने एक Safety-related Retirement Scheme भी बना ली है। अगर कोई आदमी 50 साल की उम्र में कहता है कि I am not be able to do my job as a Gangman and I want to offer my services to my son, he is eligible, मैं रिटायर होना चाहता हूँ, तो हम उसको मौका देंगे। इसका मतलब यह कि इसमें दोनों चीज़ें हो जाती हैं, एक तो employment for the railway employees will be guaranteed, especially in the safety category, इसके लिए उसको काम करने की इच्छा भी ज्यादा होगी तथा वह और भी अच्छा काम करेगा, यह हमारा विश्वास है। सेफ्टी कैटगरी के लिए हमने ऐसा किया है। Voluntary retirement के लिए we are proud of our employees' union. We have a recognized union. It is their proposal. They came to us. उन employees को प्रॉयोरिटी देने के लिए हमने

उनके मुताबिक काम किया। We have approved that policy for employment. As far as other recruitments are concerned, they are in process. So far as fulfilling the notification and other Government processes are concerned, they will be done at right time. ये हमें करना है। हमने एक और काम किया कि अगर नोटिफिकेशन करने में टाइम लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। Mr. Kapil Sibal is here.

(Contd. by 3e/PK)

PK-NB/3E/5.00

कुमारी ममता बनर्जी (क्रमागत) : वैसे वे HRD मिनिस्टर हैं, लेकिन basically Shri Kapil Sibal is a big lawyer. He knows, if there is a legal case, तो एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। इसलिए हमने एक short cut रास्ता अपनाया, not negatively but positively. हमने यह किया कि हमारे जितने भी Act Apprentice **हैं, हमने उन सबको भर्ती कर दिया। मुझे पता नहीं है कि वे यू.पी. के हैं या बिहार के हैं या महाराष्ट्र के हैं या पंजाब के हैं। पूरे हिंदुस्तान में रेलवे के जो भी** Act Apprentice हैं, हमने उन सबको भर्ती करने का फैसला किया है। यह हमारे railway employees की बात है। इसके बाद हम लोगों ने Ex-servicemen के लिए कहा है कि उनको हम safety and security में लगाएंगे। इसके लिए जो भी मौका मिलेगा, उस मौके पर हम यह काम करेंगे, हमने यह पॉलिसी अपनाई है।

इसके बाद मैं प्लानिंग की बात करती हूं। हमें प्लानिंग करनी है। कोई स्टेशन है, वहां पानी नहीं है, यह बात सच है, किसी स्टेशन में बैठने की जगह नहीं है, यह बात भी ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं यहां नहीं रहती हूं। Do you know 15 दिनों के अंदर हम लोग safety के बारे में पूरे रेलवे बोर्ड की मीटिंग करते हैं। Yes, I am attending the meeting

every 15 days. If I do not know the job, how do I do it? Politically, आपको हमारे खिलाफ जितना भी बोलना है, आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि Every 15 days, I , personally, meet the full Railway Board alongwith the Safety and Security officials. Every 15 days, I do it. इसीलिए safety के बारे में We have taken so many decisions.

Now, I come to the Konkan Railway anti-collision device. जब मैं 1999 में मिनिस्टर थी, for one year and five months, that time, I had ordered for the pilot project regarding the Konkan Railway anti-collision device. I went personally to Madgaon to see the device. Then, I ordered. लेकिन अब इसको 10 साल हो गए हैं, एक ही final हुआ है, उसके आगे नहीं हुआ। अब पिछले एक साल से चर्चा चल रही है और अभी तीन जगहों पर हाल ही में चालू हुआ है। अभी नॉर्थ फ्रंटियर में चालू हुआ, 1,700 किलोमीटर के रूट में, लेकिन By the 1st of September, in three areas, that is, Chennai, Hubli and Secunderabad, यहां पर भी anti-collision device काम करेगा। इतनी जल्दी हम लोगों ने यह काम किया है। Similarly दो सालों के अंदर unmanned level crossing की समस्या solve हो जाएगी। देखिए, TPWS के लिए हमने बजट में बहुत पैसा दिया है। Train Protection & Warning System के लिए भी हम लोगों ने बहुत पैसा रखा है। इसको करना जरूरी है, लेकिन करने में समय लगता है। आज अगर मैंने बजट में इसके लिए रुपया रखा है, तो उसके बाद टेंडर करना है, यदि कोई complaint करे, तो दोबारा टेंडर करना है। अगर दो बार टेंडर आता है, तो इसी में छह महीने से एक साल तक का समय लग जाता है। गवर्नमेंट का कोई process होता है और process में delay भी होता है। अब जहां तक world-class stations का सवाल है, world-class stations के जो norms हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें टेंडर करना पड़ता है। इसी तरह से MFC के लिए भी टेंडर करना पड़ता है। अगर हमें टेंडर करना पड़ता है, तो इसमें समय लग जाता है। यह time हमें

maintain करना है, अगर नहीं करेंगे, तो आप कहेंगे कि आपने illegally यह काम कर दिया। हम क्या करें? हमारे लिए तो गवर्नमेंट का सिस्टम follow करना जरूरी है और इसमें थोड़ा समय लग जाता है। आज कहने से कल तक नहीं होगा। आपको पहले रेलवे के सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें 6 महीने से एक साल तक का समय लग सकता है, because of the tender and other processes. But it is under process. इसके लिए हमें कहने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे कई साथियों ने कहा कि We are not giving importance to safety. That is, absolutely, wrong. In 2003, the SSRF was created. It was about Rs.17,000 crores, लेकिन इन सब funds को हमें 31,000 करोड़ रुपए करना है और By 2013, we have to complete all the safety funds. During these days, we have completed more than Rs.29,000 crores. Only Rs.2,000 crores are left out. It will be completed by 2013. I say that even before that time it will be completed. The Government has to follow some process and we are doing it very quickly. Sir, we are giving all the required importance to safety aspects because this is an important area. Sir, as far as rail accidents are concerned, I mentioned about the anti-collision device. It is not foolproof till now. We have asked the Konkan Railways to take care. See the foolproof system. We will place the order if it is foolproof.

(Contd. by PB/3F)

PB-VNK/3f/5.05

KM. MAMATA BANERJEE (CONTD.): That is why we are waiting for that also because, I think, even if you accommodate it now, it will take 3-4 years' time to complete. But there is some system which is already working in Chennai, Mumbai and we have also tried it in the suburban areas.

Then, Sir, I come to the points made by my friend from CPI(M), Mr. Moinul Hassan. He is a very good person. I appreciate him for his concerns. Of course, he is my opponent; but still I will give him 100 per cent marks. This is the beauty of democracy. I want to appreciate him. He said a series of accidents took place in the last 14 months. I want to just clarify that. It is a fact that the number of accidents is now declining. If you see the number, you will find that it is declining. Here I can quote the figures because here it is necessary to give the correct figure. Otherwise, I would not have quoted that. Sir, if you see the figures of total number of train accidents, you will see that in 2002-03, it was 269; in 2003-04, it was 249; in 2004-05, it was 169; in 2005-06, it was 169; in 2006-07, this number was 123; in 2007-08, it was 129; in 2008-09, it was 115; and in 2009-10, it was 100. I can also give you figures with respect to these four months, which is 32 and 26, but since the year is not yet complete, I cannot give you the details about 2010-11. We have to wait for that. Sir, only because of these two incidents in two months, the death toll has increased. I am sorry; I condemn these incidents. Whoever they may be, I condemn it. I don't know who are these people who have done it; but I condemn this attitude. The reason why I am saying it is because these are not accidents. In Gyaneshwari-bound accident, 160 people died. I don't know who are these people; somebody may be from Bihar; somebody may be from Himachal; somebody may be from Kanyakumari; and somebody may be going from Maharashtra to Bengal. Why has their life been lost? Why? It is due to sabotage. I am sorry to see the death toll. I always appeal to my friends to please fight with me politically. I can give reply to all your political

questions outside. But don't play politics with me. इतने आदमी को मत मारो, किसी के जान से खेल मत करो, हमको यह पसंद नहीं है। Sir, we are shocked or rather everybody should be shocked for those incidents. Everybody should condemn it. Sir, I cannot give you all the details because the investigation is going on. We handed over this case to the CBI. Let them give their complete report. After their report, we can tell you the details. So, as per our *parampara*, मैं नहीं कह सकती हूँ। That is why I am not telling it; but it is a sabotage. You can condemn that. The people have been killed. We can condemn that. This is not an accident. It is an incident. Even for Sainthia incident also, we requested the Home Ministry to allow the CBI inquiry. We want to know the actual reasons. Seeing these two incidents not only me but all the countrymen are shocked. Really we are shocked, Sir. I have never seen this type of thing. I agree, Sir, that sometimes accidents are caused by human errors. We cannot deny that. Sometimes accidents happen due to that also. If you keep so many cars with you, sometimes, that may be bad also. सर, बोला जाता है कि सिग्नल इतना failure क्यों होता है। Sir, we must also appreciate that 17,000 trains run per day. अगर किसी में थोड़ा सा सिग्नल गड़बड़ हो गया, तो खराब हुआ, लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है। हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। Sir, if you see the figures of road accidents, it is about 1,40,000. Railways is a passenger friendly mode of transport. About 17,000 trains run every day. अगर बड़ा कुछ होता है, इसमें भी इतना नहीं होता है, तब भी हम 1000 से ज्यादा कभी cross नहीं करते हैं। Just compare it with 1,40,000. लेकिन तब भी हम लोग नहीं करते हैं। Even one life is important to us. इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जो incident हुआ है, that is not accident. Incident is incident. इसके लिए sabotage और बात-बात पर जान पर खेलना

किसी के लिए भी ठीक नहीं है। यह देश के लिए भी खतरा है। Sir, today I am the Railway Minister. Tomorrow, I may not be here. Any of my friends can come; any political party can come; any Government can come. But if such an incident takes place, I will feel sorry for it. My heart will cry.

(Contd. by 3g/SKC)

3g/5.10/skc-mp

KM. MAMATA BANERJEE (contd.): My heart is crying for the victims and for every family member of the victims. We express our condolences to all the family members. I am aware that no amount of financial help can compensate for the loss of lives. But there can be no compromise on safety and security of the Railways लेकिन तब भी उनके परिवार हैं। हम लोगों को कभी-कभी future के लिए परिवार को भी देखना पड़ता है। We even tried giving compensation and made special announcement for employment from among the victims' families in the Railways. They should get, at least, something for their future. यह हम लोगों ने किया है। My hon. colleagues have covered the point about drinking water; वह मैं भूल गई, वह प्वाइंट छूट गया। उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि 8000 स्टेशनों में हम इसको ... मगर रेलवे के पास इतना पैसा नहीं है। रेलवे केवल commercial नहीं है, इसकी social obligation भी है। अभी पेट्रोल-डीज़ल में रेलवे का 1000 करोड़ रुपया गया। इलैक्शन हुआ, उसमें गया, बाद में हम लोगों ने बढ़ाया नहीं। हम तो गवर्नमेंट में एक साथ ही हैं, यह भी हमारी ही गवर्नमेंट है, लेकिन हमने नहीं बढ़ाया, तो 1000 करोड़ रुपया हमारा ज्यादा expenditure हो गया। इसके बाद रेल रोको, रास्ता रोको, बंद आदि में हमारा 1000 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके बाद this time, in view of the Sixth Pay Commission, we have paid Rs.55,000 crores out of our internally generated funds to the workers.

In view of the Sixth Pay Commission, we have incurred an additional expenditure of about Rs.15,000 crores towards pension liabilities and other things. सर, ऐसी परिस्थिति है। The Railways is not only a commercial organization, it has social obligations too. रेलवे बहुत सारे concessions देता है, चाहे इज्ज़त हो, चाहे artist's concession हो, चाहे नौजवानों को concession हो, चाहे cancer patient को concession हो, हमारे जो भी concessions हैं, Railway gives the concessions. इसका किराया भी कम है। यह cheapest है, लेकिन हम इसको aero plane के साथ कभी compare नहीं कर सकते हैं। रेलवे cheapest है, लेकिन हमें लगता है कि इसको थोड़ा सुंदर होना चाहिए, थोड़ा अच्छा होना चाहिए और उसके लिए अभी से प्लान रहेगा तो after one or two years you would see the result. I can assure the House that after one year you would get to see the service of the Railways, because we are working hard. This year, we have put in place a catering policy; we have put in place a recruitment policy; for economic sharing in private participation for the construction of new railway lines, we did not have money. इतनी मनी कैसे मिलेगी? लेकिन अगर कोई coal mines connect कर सकता है, if the industries want to invest their money, we are willing to give them economic share for a new line. Even that policy is clear. The automobile hub policy is clear; the catering policy has been cleared; the recruitment policy is clear; RDSO policy is clear; a white paper has been laid; Vision 2020 is clear. So, there are so many policies that we have cleared. Within this year, we have tried our level best to clear all these policies and I am happy to say that things have started rolling. You would get the results and see the results. अगर other stations की घोषणा की है, तो वह होगा। अगर multi functional बोला है, तो वह होगा। थोड़ा tender वगैरह में टाइम लगता है। World class बोला है तो होगा, मगर जो

trains budget में announce होती हैं, उनको एक साल लगता है। We have to run all the trains with the finances available to us. Even during the last Budget, I had said we would run 121 trains, and we ran about 118 trains. 3 में रेलवे लाइन का काम complete नहीं हुआ, इसीलिए उनको छोड़ दिया, लेकिन 100 परसेंट हम लोगों ने कर दिया। अभी भी जितनी trains हमने announce की हैं, within the financial year, it would be completed.

Sir, my friend , Mr. Raut, talked about Mumbai कि हमने मुम्बई में आपको देखा, इतना clapping किया कि इतनी trains दीं, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा, तो देखिए, 101 sub-urban local trains का बोला था, already 80 trains चल गईं। So, you must have that information. Sometimes, you do not get the information. तो trains चल गईं। अब आपका गणपति का festival है, हमने कितनी trains दीं, आपको पता है? We are providing for a number of trains. I would like to wish everybody on Onam, Ganapati festival and Ramzan also, हमारे मुस्लिम भाइयों के रोज़े होते हैं, तो हम सबको देते हैं and we maintain a friendly relationship with everybody.

Sir, I could touch upon all the issues. One hon. Member spoke about eviction, land bank के लिए बोला, I appreciate the point. ईश्वर सिंह जी बोले।

(3H/SC पर क्रमशः)

HK-SC/3h/5.15

कुमारी ममता बनर्जी (क्रमागत) : लेकिन महापात्र जी ने भी कहा। He raised some good points also. ईश्वर सिंह जी ने land eviction के बारे में कहा। हम लोगों ने लैंड बैंक भी तैयार किया है, 1 लाख 12 हजार का लैंड बैंक हम लोगों ने तैयार किया है। जैसे हमारी इंडस्ट्री लगाने की जरूरत हो तो हम forcefully मारने नहीं जाएंगे, हम उसको अपनी जमीन से करेंगे।

इसके लिए we have set up our land bank also. Even for dedicated Freight Corridor, we are giving about 12,000 acres of land from the land bank. So, we are trying our best. हम लोग यह सब कर रहे हैं। Eviction के बारे में कहा गया। हम कैसे eviction करें? अगर कोई आए तो क्या हम उस पर गोली चलाएंगे? यह हम लोगों से नहीं होगा। हम लोगों ने physically क्या सोचा कि हमारे बहुत से गरीब आदमी जो रेल लाइनों पर रहते हैं जिसके कारण रेल का चलना भी मुश्किल हो जाता है। उनके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम तैयार किया है जिसे हम पहले पायलट प्रोजेक्ट के माफिक देखेंगे। We have already discussed this matter with the Urban Development Ministry कि हमारा जो eviction लाइन पर है, अगर यह एक-दो जगह पर successful हो जाएगा तो हर जगह पर भी हम इसे करेंगे। इससे हमारी रेल लाइन भी क्लीयर हो जाएगी और जो गरीब आदमी हैं, उनको रहने का राइट मिल जाएगा, हक मिल जाएगा। हम लोगों ने इसे implement करने के लिए एक योजना तैयार की है और इस योजना का नाम है - सुखी गृह। उसमें क्या होगा कि जो लोग रेलवे लाइनों पर रहते हैं जिसके कारण उनकी जिंदगी खतरे में है - इससे रेल को भी खतरा है लेकिन रेल से भी ज्यादा उनकी जिंदगी खतरे में है - उनके लिए अगर हम लोग अर्बन मिनिस्टरी के साथ और म्युनिसिपल कारपोरेशन के साथ अम्बेडकर योजना में कर सकते हैं तो रेलवे की जमीन पर ही उनके लिए क्वार्टर बनाएंगे और उनको हम बिना पैसे के उन लोगों को दे देंगे। हम उनको एक-एक रूम दे देंगे, democratic rights भी देंगे और रहने के लिए जगह भी देंगे। ऐसा करना रेलवे के लिए भी अच्छा होगा और जो गरीब आदमी हैं, जिनकी जिंदगी खतरे में है, वे लोग भी सोचेंगे कि हमारा कोई address नहीं था, हमारा कोई मकान नहीं था, रोटी-कपड़ा है या नही है, मकान भी नहीं है, पर अब हमारे सर पर एक छत रहेगी। इस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर योजना के माफिक एक रूम हम उनको देंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने तय किया है। ऐसे बहुत सारे काम हैं लेकिन I only replied whatever our hon. Members

asked. To the north frontier we are giving all importance. With these words, I will request ...(Interruptions)...

श्री उपसभापति : सबका रिप्लाई नहीं मिलेगा।..(व्यवधान)..

कुमारी ममता बनर्जी : सबसे ज्यादा किया है लेकिन लॉ ऐंड ऑर्डर के मामले में मैं कहना चाहती हूं, I appeal to all of you...(Interruptions)...लॉ ऐंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है लेकिन I will request all the State Governments including Bihar, UP, etc. ...(Interruptions)...मैं क्या बोलूं, जो बोल सकती हूं, मैंने बोला। मैंने उनसे कहा कि आप लोग देखिए कि रेल में जो सफर करते हैं, आपकी स्टेट से सफर करते हैं, पैसेंजर्स को सिक्योरिटी देना जरूरी है, मेहरबानी करके आप उन्हें सिक्योरिटी दीजिए। Security is not with the Railways. हम जी.आर.पी. को पैसा देते हैं। ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : अब कुछ नहीं जाएगा।..(व्यवधान).. आप रिप्लाई मत कीजिए।..(व्यवधान)..

KM. MAMATA BANERJEE: With these words, Sir, I request that the Bill be returned.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

> That the Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2010-11 for the purpose of Railways, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2, 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

KR. MAMATA BANERJEE: Sir, I beg to move:

That the Bill be returned.

The question was put and the motion was adopted.

(Ends)

SHORT DURATION DISCUSSION ON LARGE SCALE ILLEGAL MINING IN THE COUNTRY

SHRI SITARAM YECHURY (WEST BENGAL): Sir, I rise with a very heavy heart to raise this discussion on illegal mining in the country. I rise with a very heavy heart because this is the sixtieth year of our becoming Republic.

(Contd. 3j/KSK)

KSK/5.20/3J

SHRI SITARAM YECHURY (CONTD): We have given ourselves this Constitution and enacted ourselves as a Republic saying that we, the people, will protect the dignity of not only the country but every individual citizen of this country. But, what we see in this illegal mining is large-scale plunder, large-scale loot and the rape of the mineral resources of our country. This is not an issue confined to any one particular mineral wealth of our country. Though the names of Bellary and iron ore illegal exports have been figuring in the news in a big for a long time, it is with great anguish that we have to note that this is happening with every particular mineral resource that is there in our country. I will only like to point out that in

some of the unstarred questions, there is a wealth of material that has been presented to this House. On the 2nd of this month, the Union Minister, Shri Handique, had actually answered a question on whether there were 42,000 cases of illegal mining detected in eleven States during the last year. I quote Mr. Handique's reply, "The Indian Bureau of Mines has constituted Special Task Force teams and conducted inspections in 106 mines in the endemic areas of five States of Karnataka, Andhra, Orissa, Jharkhand and Gujarat." And, the instances of what they have done in these illegal mining cases have all been listed by the Minister. Again, Sir, in an unstarred question on the 9th of this month, the Minister has detailed the illegal mining of coal in the States of West Bengal, Jharkhand, Maharashtra, Chhattisgarh, Orissa and Assam. Likewise, in a number of such answers to unstarred questions, the Government of India and the Ministry have pointed out that whether it is from the North-East, or any other part of our country, this sort of illegal mining is taking place. It is rampant in all the mineral resources of our country. So, I am not confining myself only to the hi-profile things that are happening in Bellary and with the iron ore, though that is very important. I will come to that. But, what is happening in the name of illegal mining is not merely a small degree of illegality that is being committed or a petty crime, it is a gigantic loot of resources of our country. Now, in the 60th year of our Republic, are we to permit such a loot in our country? Therefore, Sir, this issue merits, in my opinion, and that is what I would like to argue in the short time that I have in initiating this discussion, that we require an out of the box solution to protect and safeguard our country's mineral resources. For this, we shall have to

learn from what the other developed countries are doing. You look at the United States of America. It does not touch its oil reserves. Today, it imports all its requirement of oil, keeping its oil reserves for a future date when such an emergency arises, when it requires to fall back on its own reserves. Look at our neighbour, China. It imports many of these mineral resources from across the world, but it keeps its resources intact so that when it needs to fall back on them, there is a fall-back option. What are we doing, Sir? We are mercilessly looting our resources and selling them abroad illegally with some people making super profits, profits of a phenomenal rate. This sort of loot that is taking place in our country can be described as nothing else but 'crony capitalism'. The Prime Minister, standing here in this House, has said, "India can ill afford crony capitalism." If the Prime Minister is true to his own words, I think, the time has come for us to pay proper attention to this loot that is taking place, and the time has come, as I will argue now, for us to nationalise all mineral resources in our country and ban all export of mineral resources from our country. If anybody wants to use our mineral resources, let them come here and set up their factories, let them add value to our mineral resources on our land, let them provide employment for our people, let them generate productive resources in our country so that we will gain rather than exporting these minerals to their countries and increasing their productive capacity at our cost. So, this is what I want to establish that we have to learn from other countries. Today, the time has come to nationalise all our mineral resources and ban any sort of export of our mineral resources.

Here, Sir, various steps have been taken by the Government in terms of saying that much of this loot that is taking place is because of law and order problems that are State subjects. (continued by 3k - gsp)

GSP-GS-5.25-3K

SHRI SITARAM YECHURY (**CONTD.**): And, if law and order is the State subject, it is the State Governments, which are primarily responsible. This tossing of the ball between the Central and the State Governments cannot be afforded any longer. The only way we have got to solve this problem is by nationalizing our mineral resources. Let us take the issue of Bellary. In the case of Bellary and the illegal export of iron ore, all of us know, how rampant it has been. Sir, it is very revealing that the incumbent Chief Minister in a 21-page reply to some of the questions raised in the State Assembly on the 10th of July this year, has said that in the past seven years, more than 30 million tonnes of iron ore was illegally exported from the State of Karnataka. More than 30 million tonnes of iron ore from one State alone! Even if you take a conservative price of US $ 50 per tonne in the international market, it turns out to be US $ 1.5 billion, or, Rs. 7,500 crore of exports in these six to seven years from one State, Karnataka, and, only from one area where the Obulapuram mines are located. This is the scale of loot. He has also informed that it is not confined to any one particular political dispensation. He said that the earlier Congress Government, which was there, had issued notifications for 33 mining permits. The Janata Dal (Secular) Government that followed had issued notifications for 19 mining permits. There were nine beneficiaries under the President's Rule, and, the rest of the notifications were

issued by the current BJP-led Government. Whether it is Congress, Janata Dal (Secular), BJP or the President's Rule, you have such notifications. (Interruptions)

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Illegal export took place only in BJP-regime. (Interruptions)

SHRI K. B. SHANAPPA: No, no. That is not true. (Interruptions)

SHRI RUDRA NARAYAN PANY: What is happening in Orissa? (Interruptions)

SHRI SITARAM YECHURY: I am coming to Orissa, *Pany Saheb*. Don't worry.

श्री रुद्रनारायण पाणि : आप उड़ीसा के बारे में बोलेंगे ? वह आपकी बगल में बैठे हैं। ..(व्यवधान).. आप वहां पर सरकार के साथ हैं। ..(व्यवधान)..

श्री सीताराम येचुरी : मैं इन्हीं की बगल में बैठा हूं। ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : आप बैठ जाइए। ..(व्यवधान)..

श्री के. बी. शणप्पा : आप बेल्लारी का रेफरेंस दे रहे हैं। आप सबका जिक्र कीजिए। You have to mention everybody. (Interruptions)

श्री उपसभापति : आप बोलने दीजिए।..(व्यवधान)..

SHRI RUDRA NARAYAN PANY: Sir, he is so intellectual, he is so intelligent, he should not say like this. (Interruptions)

श्री उपसभापति : वह क्या बोलेंगे ? यह आपसे पूछ कर नहीं बोलेंगे। ..(व्यवधान)..

SHRI BAISHNAB PARIDA: The State of Orissa has taken... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. (Interruptions) Please sit down. I will not allow. (Interruptions) Nothing will go on record. आप बीच में इस तरह से इंटरेप्ट मत कीजिए। उनको जो कहना है, वह कहेंगे। आपको जो कहना है, आप कहिएगा। ..(व्यवधान).. Why are you interrupting?

श्री रुद्रनारायण पाणि : *

श्री उपसभापति : जो आप चाहते हैं, वह वैसा नहीं बोलेंगे। ..(व्यवधान)..

श्री सीताराम येचुरी : सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि शायद आप देर से पहुंचे हैं। आपके आने से पहले मैंने कहा कि यह किसी एक प्रांत तक सीमित नहीं है, न किसी एक मिनरल तक सीमित है। मैंने जिन States के नाम गिनाए, उसमें उड़ीसा का नाम भी गिनाया। मैंने उड़ीसा का नाम लिया और मैं फिर कहूंगा कि जब हम कोल पर आयेंगे, तो उसमें किस तरीके से illegal

mining हो रही है, उसके बारे में बतायेंगे। आप फिक्र मत करिए। मेरी चिंता पूरे देश की है, सिर्फ बेल्लारी की ही नहीं है। इसीलिए यहां से शुरू किया है कि पूरे देश में हमारे जो मिनरल रिर्सोसेस हैं, उन मिनरल रिर्सोसेस का राष्ट्रीयकरण करने की जरूरत है और उस मिनरल रिर्सोसेस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाने की जरूरत है। सर, मैं अभी बेल्लारी के बारे में बता रहा था, क्योंकि यह सबसे बड़ा glaring case है, जो हमारे सामने आया है। And, what does the Chief Minister's statement says, Sir? It is amazing. Look at this. 20, 49,961 tonnes of iron ore was illegally exported in 2003-04; Similarly, the figures are: 52,39,528 tonnes in 2004-05; 21,71,492 tonnes in 2005-06; 47,44,645 tonnes in 2006-07; 57,61,048 tonnes in 2007-08; 33,96,000 tonnes in 2008-09, and, 71,27,937 tonnes in 2009-10. It is amazing. And, if you take the current rate, which is US $ 150 per tonne, this is what my friend Pyarimohan Mohapatra suggests, this value goes up to around Rs. 22,500 crore.

(Contd. by YSR-3L)

*Not recorded.

SHRI SITARAM YECHURY (CONTD.): Sir, this is the sort of loot that is taking place in our country, and various agencies of our country were involved in trying to examine it. The hon. court, the judiciary had intervened. They had appointed a Central Empowered Committee to go into this issue, particularly Obulapuram mining in Andhra Pradesh, and in Karnataka. But it was mainly in Andhra at that point in time. And what conclusion did the CEC come?

"The CEC after examining the matter is of the considered view that the demarcation of the boundaries of the five of the above mining leases and the conclusion reached by the State of Andhra Pradesh that M/s OMC is not involved in any illegal mining in the forest areas outside its mining lease areas suffers from the following serious defects and inconsistencies -- please underline this -- and is not at all in conformity with the approved mining leases:"

And they give you a list of various pages of recommendations. Finally, it recommends, "Keeping in view the facts and the circumstances as brought in the report you (Chief Secretary of Andhra Pradesh) are advised to take immediate steps to stop the mining operations, including transportation of already mined material from the six mines dealt with in the CEC's Report."

Orders come for stoppage of that. But nothing happens. And this was ordered in November 2009. After that, you just heard me saying, 71-odd lakh tonnes has actually been exported illegally. This is the manner in which every agency seems to be collaborating with this loot. What is amazing is the report of the Lokayukta of Karnataka. He says that he asked his officers to seize some of

these illegally transporting trucks. And what does the report say, Sir? It says that the officers conducted raids and seized 99 trucks with illegally mined ore and 40 sacks of forged documents. On the basis of that, 8.5 lakh tonnes of ore were already purchased by 11 companies for export and even when the High Court was considering the matter six lakh tonnes of ores were shipped outside. The court is seized of the matter. The court is saying that you stop the export. The trucks are seized. The iron ore is seized. The iron ore is kept at certain place and from that place nearly six lakh tonnes of iron ore vanishes. It vanishes under the very nose of the very Government, the very High Court, and the very authorities. Then you have an amazing statement by the Chief Minister which was reported by the media, so I cannot authenticate it. But it was reported in the media that the Chief Minsiter has said that it got washed away in the rains. (Interruptions) I said I read it in the media. (Interruptions) That is why I am not authenticating it. But the point is that the whole business is being dealt with such lack of seriousness where every arm of our constitutional legality -- and that is why I began with 'We the people' -- the Judiciary, the Executive and the Legislative Assemblies of the concerned States are all involved in the matter, are all seized of the matter. But yet the iron ores keep disappearing. Just look at the clout that exists as far as these people are concerned. (Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: When your turn comes, you can say that. Please don't interrupt.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I want, through you, the entire House to understand the gravity of the situation. It is not a question of scoring points

whether the rain washed it off or somebody stole it or somebody took it away. The issue is that my country's resources, your country's resources are being looted like this. Are we to permit it? Don't try and pick holes in trying to say whether this is right or that is wrong. The point is that the mineral resource of my country has vanished. This is your wealth. This is my wealth. This is our wealth. How has it vanished? And why has it vanished?

My point, which I think that all of us must take very seriously, is this. Can we afford this sort of a loot and plunder of our country's resources?

(Contd. by VKK/3M)

-YSR/VKK-LP/3m/5.35

SHRI SITARAM YECHURY (CONTD.): And that is why, I am raising this issue. Yes, the question of accountability, the question of who is responsible for this, all that needs to be addressed and the guilty needs to be brought to book. Whatever this august House will recommend, I hope, the Government will respond seriously to that and take it up and will not pass on the buck by merely saying that it is State Government's problem or party's problem. That is not the issue. Every single party which has been holding Government in different States is responsible. We have seen how illegal mining of coal is happening in our country. Please look at the collateral damage. Let me now come to the question of what is the damage it is causing. To use an American phrase, collateral damage is happening to our country. What is the result of this? It has been pointed out that an estimated amount of 1.6 lakh hectares of forest land has been diverted for mining in our country. Our Minister of Environment, otherwise a very outspoken person, is not

here at the moment. (Interruptions) I wish he ought to have been here. (Interruptions) Sir, 1.6 lakh hectares of forest land has been diverted for mining. Of this, for example, take iron ore mining alone. We are talking about Obulapuram. (Interruptions) I am coming to Vedanta. If you are talking of Obulapuram...(Interruptions)...

श्री रुद्रनारायण पाणि : आप उड़ीसा नहीं जाएंगे। ..(व्यवधान)..

श्री सीताराम येचुरी : मैं जाऊंगा। ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : वे कह तो रहे हैं मैं जाऊंगा, फिर क्यों बार-बार यह बात उठा रहे हैं..(व्यवधान)..आप बैठिए।

श्री सीताराम येचुरी : सर, मैं जाऊंगा। मैं बिना आमंत्रण के भी जाऊंगा। आप तो बुला नहीं रहे हैं, मैं उसके बावजूद भी जाऊंगा। Sir, for iron ore mining alone, apart from the forest area of 1.6 lakh hectares that has been diverted for mining, 77 million tonnes of water has been used up in one year of 2005-06. It is only for iron ore mining. How much would this affect? This would have met the daily needs of nearly three million of our people who do not have potable water near their households or habitations. This is collateral damage that is happening. And, what has happened in one year of 2006? Sir, 1.84 billion tonnes of waste was dumped in our country. It was in just one year and this waste is not disposed of. Whether this has toxic material or not is never investigated. This sort of waste is dumped in our lands which affects our agricultural productivity and fertility of our soil. So, look at the collateral damage in terms of forest depletion, in terms of water that has been used up which is a scarce resource in many parts of the country, in terms of dumping on your arable and fertile land whereby you cannot produce food. And,

Sir, this is not all. Collateral damage goes beyond the economy and physical resources. You have a collateral damage that is now occurring in the entire quality of our country. The riches from illegal mining are actually influencing our political system. To an extent, it becomes unbearable for any one of us -- I am sure, Sir, it is as applicable to you as it is to me -- that it is impossible today to contest elections in the State from where you come. With the amount of money that is being used, all the money that is collected through illegal mining has gone in there. There are phenomenal amounts of money. It puts to shame the limits that the Election Commission has put on the expenditure in election and all this is finding its place in politics. It is distorting our political system. The collateral damage is not only to ecology or resources, but, it is also to our polity. It is distorting our political system by the use of this sort of money which is also distorting your democracy, in the sense, people are no longer voting on the basis of the positions of the political parties or on the basis of the issues that political parties articulate, but on the basis of which political party has how much resources at their command and on that basis, you have people voting and it is distorting the democracy. So, what has begun with illegal mining is actually having a collateral damage on your entire system, not only on your economy.

Sir, now, I would come to other point and I want this House to seriously consider this point. Sir, you take the physical map of our country and map out the areas where you have Maoist violence today. In every single area that you map out Maoist violence today, you will find that it is a mineral-rich area, particularly coal, in the States of West Bengal, Chhattisgarh, Bihar and Orissa where thousands of

hectares of land are being given away to these companies and corporates in order to exploit these mineral resources.

(Contd. By MKS/3n)

MKS-AKG/5.40/3N

SHRI SITARAM YECHURY (CONTD.): And in most of these areas where our tribal people, our tribal brothers and sisters habitat, when their interests are affected, whether it is only a particular issue of Orissa that you are talking about, where large-scale tribal persons are displaced, where, in the name of mining, not only forest depletion is taking place but even tribal habitations are being shifted despite the scheduled areas in which they live and despite the protection, 'that you cannot displace them', that the Indian Constitution gives. Despite all that, you have thousands of these facilities being relocated for mining interest! The discontent that is generated in them works as a fertile basis for the growth of anarchic and violent activities of the Maoists. So, you have a collateral damage in terms of political forces that are completely antithetical to the parliamentary system.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How much more time will you take?

SHRI SITARAM YECHURY: I am concluding, Sir. It is a serious matter. You know, normally, I won't take too much time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I know that.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I am grateful to you because on many occasions, you are on record to say that 'I do not normally waste time. I only take it when I passionately feel about something very serious.'

So, what I am saying, Sir, is, whether it is the question of illegal mining or whether it is the question of illegal bauxite mining -- and there is a new report that has now been prepared by a team of experts that bauxite mining in Orissa is being handed over to certain corporates -- whether it is the question of iron ore or whether it is the question of, in-between the North-East, very sensitive areas where this illegal mining is going on, all these put together, the only one aspect which I think all of us have to seriously apply our mind to is that it is no longer a loot of our precious resources alone, it is no longer sleaze and corruption where some people are making huge, big bugs at the expense of our country and our resources, but it is also an issue that is permeating ever single sphere of our polity and our democracy. OUr polity is not being spared; our democracy is not being spared; all this is being distorted because of this illegal mining. So, stopping illegal mining is not merely a question of protecting our resources and punishing the guilty, but stopping illegal mining is also the question of protecting modern India, Sir. If, to stop illegal mining, in order to protect modern India in this sixtieth year of our Republic, we say that we, the people, give ourselves this Republic, we, the people, should be able to safeguard our Republic too, and if we have to safeguard our Republic, there is, today, no other way, Mr. Deputy Chairman, Sir, than to nationalise all of our mineral resources. Nationalise all of our mineral resources. Ban the export of all mineral resources. Any company, any corporate in the world is most welcome; he can come here, use our resources, add the value and produce finished products in our country, give jobs to our people and enrich our economy by enlarging our productive capacity. So, you have the value

addition done inside the country. Ban the exports of our mineral resources and nationalise these resources. There is no other way through which we can protect ourselves, our Republic and our resources. Therefore, I beseech, through you, Sir, the Government to take this bold step. If they take this bold step, the people of our country will pay to them. ...(Interruptions)... The people in the country will continue to recognise them like their illustrious predecessor. It may have happened with the Left support then, in 1969, but when the illustrious predecessors nationalised the coal mines, when they nationalised the banks, see the result; that is what we, in India, are today. So, take these measures; take these steps. It will go down in history as not only protecting our resources but also as protecting our country, its democracy and its polity. And with that gravity, I want the Government to take this issue into consideration, and they will find full support from us if they proceed to nationalise these resources and ban the export of our mineral resources from our country. I hope the Government will, at least, consider it seriously. I mean, I would not only like the Government to accede to my point, but you, please, also ask them to, at least, consider it seriously and to ensure that our country is not allowed to be looted in the manner in which it is being looted today. Thank you, Sir. (Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Mr. Yechury. Now, Shri Aayur Manjunath. He is going to speak in Kannada. ...(Interruptions)... Shri Aayur Manjunath to speak in Kannada.

(Followed by TMV/3O)

** **Pp** 631 **onwards will be issued as a supplement.**

SHORT DURATION DISCUSSION ON LARGE SCALE ILLEGAL MINING IN THE COUNTRY(CONTD.)

-MKS-TMV-DS/3O/5.40

SHRI AAYANUR MANJUNATHA(KARNATAKA): Thank you, Sir. I will speak in English and Kannada, mixing both. (Interruptions)... मैं हिन्दी में भी बोल सकता हूँ, लेकिन आपको सुनने में दिक्कत होगी।

Sir, as you are aware, the issue of over-exploitation of the mines and illegal mining have been a major concern of the mineral-rich States of our country. Despite the efforts by various State Governments, illegal mining could not be stopped. The name of Karnataka State was mentioned by my senior colleague, Shri Sitaram Yechury. Karnataka State is the first State which has imposed a ban on exports of ore and requested the Prime Minister of this country to stop exports. We met him personally, submitted a letter and requested him to stop exports of ore.

Sir, it is a fact that 1.64 lakh hectares of land is used for mining. More than 2.5 crore people have been displaced. They belong to the Tribal community. As a result of this activity, most of the Tribal people have been compelled to join hands with the Naxalites, anti-social elements and the Maoists. It has created a big security problem to the country. To avoid the anti-social activities through illegal mining, a ban should be imposed on exports.

At the same time, I would like to bring to the kind notice of the Chair that there are more than 15,000 illegal mines throughout the country. It is not one or two. He has mentioned Obulapuram. But it is not in Karnataka. It is in Andhra Pradesh where there is a Congress Government. He has mentioned about illegal mining in Obulapuram. But it does not belong to Karnataka. (Interruptions)... As far as my knowledge goes, the main beneficiaries of illegal mines and mining are our Congress leaders. They are the main beneficiaries throughout the country. As far as my knowledge goes, a mine owner is also a Member of this august House. He comes from that line. (Interruptions)... I am not prepared to take his name. (Interruptions)... Illegal mining is creating so many problems.

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, there is one point. There may be mine owners. But he should talk about illegal mining. He should not talk about Congress leaders generally. He should say clearly that it is illegal mining. That is the point. (Interruptions)...

SHRI AAYANUR MANJUNATHA: What I am mentioning is that illegal mine owners are here. (Interruptions)..

SHRI S.S. AHLUWALIA: Then, do you want to hear the names? (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ahluwaliaji, don't interrupt. Please sit down. (Interruptions)...

SHRI S. S. AHLUWALIA: Then, why is he provoking? He will give you the specific names. Are you interested to hear that?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, please.

SHRI AAYANUR MANJUNATHA: Mining has also resulted in the destruction of forests.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please don't politicise this.

SHRI AAYANUR MANJUNATHA: Yes, Sir. It has also resulted in disappearance of water sources, especially, depleting underground water table. Mining poses a great threat to human habitats, especially, the Tribal community. The toxic by-products of mining, when they enter the atmosphere, will create acute health problems to the people.

(Contd. by 3P/VK)

VK/3P/5.50

SHRI AAYANUR MANJUNATHA (CONTD): Mining is never eco-friendly. It leads to negative effects despite following the best precautionary measures. Hence the Centre for Science and Environment, in its report, has recommended a strict ban on mining to preserve ecological balance. Recently, the English fortnightly, Frontline, has published a detailed report on nefarious activities of mining mafia across the country. Therefore, I request the Government to put a ban on illegal mining and export of iron ore. * Hon'ble Deputy Chairman, Sir, it is a matter of great concern that illegal mining is rampant in our country. Unfortunately nobody is concerned about its adverse impact on the country's economy and its social and political fall outs. The livelihood of our people particulalry tribals, backward

---

* **English translation of the original speech made in Kannada..**

community are greatly affected. Illegal miners are encouraging anti social elements like naxalites, maoisists with tainted money to create disturbance in the border areas. They are a big threat to the safety and security of our country.

Sir, illegal mining operations are going on in 7 or 8 states in India. But I am proud to say that Karnataka is the only state in the country, which has shown its concern to protect national resources by imposing ban on export of iron ore from Karnataka. I congratulate the Hon. Chief Minister of Karnataka for taking such a bold step. Hon. Chief Minister has even said that the mining licenses would be issued to those persons who come forward to utilize our mines for value addition.

Deputy Chairman Sir, I would like to know from the Government of India through you as to how many persons in the entire country are operating these minings and how many of them have not taken permission from the Government. Details about the domicile and political affiliations of those who resort to illegal mining should be made available to this august House. Hon. Member Shri Sitaram Yechuri in his speech said that there are 42,000 illegal mining cases booked in the country. I request the Government to give the details as availabe in the FIRs.

Sir, it is very very unfortunate that illegal miners are looting the country's wealth by displacing about 2.5 crore of backward and tribal people. These hapless people are not given any kind of protection. They do not have land for

cultivation or food to eat or houses to live in. In order to protect such people Hon. Chief Minister of Karnataka has taken bold step. Henceforth Mining license would be issued only for value addition. It would help us to utilize our national resources within the country and create employment opportunity. It would generate more reveue to our exchequer. Our Hon. Chief Minister Shri Yeddyuarappa has written a letter to Hon. Prime Minister of India making a request to impose a ban on export of iron ore in the entire country and to nationalize all the mineral mines of the country.

Sir, it is unfortunate that sincere efforts of the Government of Karnataka to curb illegal mining are not being recognized. Instead, some people are criticizing us. But we all know that they had joined hands with mining mafia when they were in power.

Hence, I urge upon the Union Government to take stringent action against those involved in the illegal mining and to punish them. Finally, I would like to impress upon the Government to take strong measures to protect our national resources and save the country from illegal mining.

Thank you.

(**Ends**)

(Followed by 3q)

DR. K. KESHAVA RAO (**ANDHRA PRADESH**): Sir, while I share the total feelings and the facts that Mr. Yechury has presented, believe me, I am in the same mood; I am not trying to make any debating point, nor am trying to indulge in some kind of a game plan by saying that this man has done wrong, or, that man has done wrong. All of us in this House, I am sure, are equally concerned about what is happening in the country. It is a plunder and loot, -- that is what Mr. Yechury feels -- but there is the other side of the coin. Let us look into that. Any money, easily gotten money, the concomitant of it is that it has a greater draconic role to play in his own hands. Whatever has happened in Karnataka or a few other States, -- there is a big hype about Karnataka -- I am not trying to blame the BJP at all because the friends here sitting on the BJP benches are known for their honesty and transparency. And, as they have themselves said, as the Chief Minister has also said, illegal exports have to be banned. I am not trying to blame anybody. The most perplexing and paradoxical part of this debate is this. Every one, right from the Prime Minister, the UPA Chairperson and the Union Minister, who is present here, says so. He has said the same in the Lok Sabha, "I agree that a widespread illegal mining is going on. It is so widespread that it shocks my conscience." The Supreme Court says so in so many words. The CVC says so. The other Civil Courts say so. The DFO says so. The Environment Minister, in his own 13 letters, written to the Karnataka Government says so. And, all the Members say so. Yet, it goes on. What is exactly happening in this country? The illegal mining, which we are talking about, is not only loot and plunder, but it

is also the easy money that you have. It can be converted into gold and any kind of money. Sir, I don't have the facility and privilege, like Mr. Yechury has at his desk. Otherwise, I have a lot of materials which pinpoint to the kind of irregularities that are there. I am only trying to mention the reports, which have come from Karnataka, that bring out the truth. Let us also appreciate; the Lok Ayukta, Karnataka, had come out with the Report that he has read. It also shows that they also have some kind of a feeling, some kind of a sentiment and commitment to see to it that it must end. But, all the same, that is not enough at all because there are methods and means for the so-called mafias, the mining mafias. The mafias have invented their own methods. After all, what is an illegal mining? You take a permit; after all, the IBM gives it. There is the Geology Department that looks into and finds out where exactly the minerals and the resources are. It has its own study. It also fixes the quantum that you must take out of it. Yet, when you look at the facts that Mr. Yechury has mentioned, the figures that he has given, -- I have to skip them; I have to discard those papers because that will take a lot of time -- I should tell you, what has happened is, if you are to look at the Karnataka issue, -- I am only taking it as an example of how those people operate -- if you try to find out how illegality can be probed into; the question is, seven times more than what is permitted has gone as an export. Now what kind of a thing has been exported? There are mines where you don't have prime deposits; in Andhra Pradesh, that is what we call, a diversified thing, which our Minister and others know about it. These are not fine deposit iron ore. You are a mine owner of that area. Yet all your exports are fine materials. Where

did they come from? It means that there is also a scope that you, in the name of that permit, in the name of that holding, in the name of that lease, can bring things from outside; whether they are legitimate or not, we would not understand it.

(Continued by 3R)

3r/6.00/ks

DR. K. KESHAVA RAO (**contd.**): It is for inquiry agencies to know; you tried to export them.

So, while going into those details, I am tempted to, first, jump to the conclusion -- which Mr. Yechury has mentioned and which the hon. Member from the BJP has also mentioned -- that there has to be an end to this. And the end is -- I don't know whether it is nationalization or not -- that you stop the export and use the material for value addition within the country. If some foreign country likes to use your material, it can have its plant here as well. This will end, to a large extent, this kind of illegality in the mining sector.

Sir, he mentioned the figure of 42,000 metric tonnes. I would not like to go into that because there are three very shocking reports that have come. One is of the Supreme Court. The other is from the Chief Minister of Karntaka. And the third one is from the CEC. Karnataka Chief Minister's report would be very interesting for the simple fact that he had been so truthful even amidst all the crises that he was facing. He talks about a total illegal transportation of about 71 lakh metric tonnes. And, as you said, it does not belong only to the period for which the BJP Government is responsible, it also touches the periods of other Governments.

But the issue that we are discussing here today is not what a particular man has done or not. Why have, perhaps, Obulapuram, or, one of the friends' brothers' names are coming in, is for the simple reason that there is a political dimension added to this illegality. One is, here are a few gentlemen who are politically in-charge of a mine-rich area. And I am quoting all these facts which have come out in the reports of the Lok Ayukta, the Chief Minister and from what has been said on the floor of the Assembly. So, there is nothing like wild allegation that is being made. Even if there are a few allegations, please forgive me; I am sorry if they are not backed by facts. But this is what has been reported. The point is, they become the in-charge of that area. And it might have happened anywhere. It has happened to some extent in Andhra. I am in-charge of Jharkhand and it is happening in Jharkhand. I do not know much about Chhattisgarh but it is happening in Chhattisgarh. I know what is happening in Orissa in which Mr. Pany is interested. The second phase permission has not yet been given and, yet, the factory comes out with it, whether it is Vedanta or some other. You have referred to Goa. Though the land belonged to the State under the Portuguese Act, it is you who got the concessions, once your Act came into the picture with amendments. The land belonged to the Government but it has been sold and transferred to Vedanta. All these kind of things have happened. They may not directly be concerned with illegal mining, but they are concerned with illegal mining activity.

So, today, this is the kind of thing that the Chief Minister says. The Karnataka Chief Minister accepts that this is one of the biggest shocks that he has

had in his life, of the illegal mining in the State. I mean, he was talking about the overall scenario and about the State as well. He admitted that illegal mining was taking place in the State in a very high order. Then, he gives the figures. Then, I am quoting the DFO report of the same place which says, "ground excavations do not tally with the permits issued by the Department of Mining and Geology", to which I referred. This report includes two States, Andhra Pradesh as well as Karnataka. I am not trying to run away from the situation in Andhra Pradesh. Again, more iron ore has been brought from the Karnataka mines; although the permits allowed were of a limited value, the exports were much higher than what exactly was permitted. That they came from Karnataka, has been admitted by DFO of Andhra Pradesh. But this is done by a company belonging to Karnataka.

(contd. by kgg on 3s)

Kgg/3s/6.05

DR. K. KESHAVA RAO (contd.): The man in power can do anything; this is what has been done. The report also says that 57 officers were transferred from the district. Please introspect on what can happen if this kind of nexus develops between the politicians and the mine owners, or if politicization of the entire business takes place. There is one issue which we need to understand in this. Just imagine what kind of an impact the easy money, ill-gotten money can play a role. We bring the name of Karnataka again not to undermine or criticize it, but to caution the entire country. This money can interfere in our democratic institutions very badly. All of us have read about our neighbouring State; I know perfectly well the kind of political game these people wanted to play, planning to overthrow the

Government because of their money power, the same kind of designs they tried to play in Andhra Pradesh, the same kind of game played in Jharkhand. We need to be cautious; we need to gear up ourselves to face this kind of challenges. This impact is again because of illegal mining.

Sir, as far as these figures are concerned, all this has started only in 2003-04, as one friend said, only because of exports. Sure, when China increased the prices at a time when the price was at 400, it went up to 4000, naturally everybody looked to the iron ore mines where it was easily available, whether Obulapuram or other places. But, what happened is, in Obulapuram, even the State borders were changed! It happened because the permits were available in one State and the ore was available in another State. If what my friends have said is correct, it could be the reason also—if a particular State did not like to give them the place to mine but to give the permit, you would change the entire boundary and take areas of the other State and say that this land belongs to Andhra Pradesh and try to mine there! This can be done. It can be Chhattisagarh and Jharkhand border, Jharkhand and West Bengal border which are mine rich, resource rich. It is not only iron ore, as Mr. Yechury said. It can be aluminium, bauxite, sand, I do not know much about chrome; it could be for black granite too. In Andhra Pradesh, let me tell you, it all started with Chilkuria, Ongole district for black granite. I am not trying to score points but to drive home a point. Once the High Court referred to black granite being mined illegally, the Chief Minister had to resign and go. He was a very sensitive Chief Minister; only his name was mentioned and he did not stay there! My suggestion is not to say that Mr. Yeddyurappa should go. I am

saying that everybody is saying that such and such a thing is happening right by the Ministers themselves. And, those Ministers, according to the reports available, are trying to feel that they are bosses to the Chief Minister, which none of us, whether from this party or that, likes. But it is happening. Thanks to the wise leadership of the respective parties, nothing could really go that wrong at the particular point of time.

Sir, we are trying to discuss this illegal mining from two angles. One is the loot and plunder of the national resources which needs to be stopped. Every one of us knows the facts and figures for the last 6-7 months; we are being fed by the media all kinds of atrocious and scandalous things going on in this field.

(Contd. By tdb/3t)

TDB/3T/6.10

DR. K. KESHAVA RAO (CONTD.): Number two is, the worst role that this kind of an easily-gotten money is playing. This thing needs to be looked into. It is one thing which happens whenever this illegal thing takes place. Just now, I was trying to tell the hon. Minister, who after having looked into it, have said on the floor of the Lok Sabha that these activities are in his knowledge. He admitted that he is aware of all these kinds of activities. He said that he has announced a Commission of Inquiry to look into the entire thing in 18 months' time. I personally, though sitting in this side of the House, in the Treasury Benches, would like to remind the hon. Minister that this kind of an Inquiry Commission report will not help in the issue of this dimension and in an issue of this intensity. Let me remind the hon. Minister that everyday illegal mining, the export value of which is worth

Rs.20 crores, is being done by one company. This is the export value of the mined product. In 18 months, nearly Rs.7000-Rs.8000 crores would be going to these illegal mining mafia. So, this has to be looked into. So, what should be done? What needs to be done is, either we need to be bold enough to come to some kind of a policy decision to stop these exports or we need to think that for a particular time wherever these areas have become grey, wherever there are some kinds of allegations, wherever there are some complaints and wherever there is a need of inquiry, we can totally ban mining. We can stop it with absolutely backup mechanisms. The hon. Minister was just now saying that the police would stop it. The police would never stop it as long as the local powerful people are holding these mines. The police is under the control of the State. I am not trying to immediately find fault and saying that these brothers are corrupt. But, the question is, we need to look into this and learn from our own experiences as to what machinery has to be introduced at these places. So, what we need to do is to have some kind of a new mechanism, if you are trying to do it. First of all, 18 months' time for this Inquiry Commission is not necessary because you have in your hand all the reports of inquiries and investigations. Even Andhra Pradesh has announced the CBI inquiry, it is one of them. So, these kinds of things would only delay the issue. And we need to look into the issue without further delay.

Sir, I would like to tell you about the other impact of this illegal activity. Now, these people are getting into reserved forest areas. It is estimated that permits are being given for something like one lakh acres of land which are otherwise reserved forests. The response of the Minister of Environment and

Forests of the Central Government is that 'they have not been given the permits and the rights. They are illegal; there are encroachments. The State Forest Departments have to protect these encroachments, and these reserved forest land cannot be used for mining purposes. All the maps which are made and the topography sheets which have so far been identified need to be put aside.' This is what the Central Ministry has sent to them, but without any result.

Then, again, the same Minister writes that mining is continuing in the forest areas of Sindhu and Bellary in spite of our reminders. Why is the Forest Department, bla, bla, is saying the same thing. Again there is the same answer. Even the Supreme Court's curb on the Obulapuram mining ore, mining around the Karnataka's Bellary district has not made any dent on the powerful Reddy brothers' business. This is the letter of the Central Government. I am reading from the letter of the Central Government. Why they used those names, I don't know. But, they have said that reports have been received that 30 per cent iron ore is being illegally mined by other six miners. This is again an investigative kind of a report.

(Contd. by 3u-kls)

KLS/3U-6.15

DR. K. KESHAVA RAO (CONTD): So, this kind of investigation which you are trying to say that the Commission of Inquiry will find, I say much of it, 70 to 80 per cent of it is already in your hand. It is for you in your wisdom to know whether you still need to buy some more time to get into this. Sir, the modus operandi of these people - although I am not very much interested in finding fault with one person or

the other - is that this particular gentleman against whom the court has sent arrest warrants once. Again he challenged that in the court and the court has rejected it finding fault with the State Governments for not bringing him to book. Then again he does not appear. Seventeen times the court gives the order, non-bailable warrants, but nothing happens to him. He is as much a fine Minister as ever. Why I am saying this is that once you wield power in a State, more so with the kind of money that you have, with this kind of money, these agencies, however strong they are in the enforcement, become weak before your money. So, we have been talking of not regular mining thing. So, I would have, along with Mr. Yechury, really found fault with the exploitative methods of the monopoly houses. But this is more than that. Why do the monopoly houses have something which we can find fault with and can go legally against? Here is an activity which will defy every kind of moral legal order. This is what exactly is available in this kind of a scenario. Then, Sir, this kind of mining, which I am telling, I am jumping because many of the facts Mr. Yechury has given, so I will not elaborate. Now, Sir, this is again, because I am talking about one lakh acre., it could be one lakh acre because another friend said it is 1.57, but whatever acreage it is, the thing is the vegetation is being affected, the tribal lives are being affected and 2.5 crores tribals have been displaced, according to an hon. Member in this House. While sharing his concern, let me, for instance, say if all the 2.5 crores become Naxalite, then the of Naxalite figure will be much more and you and we would have been more bothered than as they are trying. They would not join. Let our concern go to them, let us share their agony, let us share this way, let us share their condition,

miserable condition. But the question today is that their lives are being displaced with no rehabilitation because in these illegal activities, we do not get into the rehabilitation schemes. Even if the Government has given it, it is not there in Karnataka, Andhra, and Jharkhand which I know to be sure that not like that we have what is known BRM. BRM, Sir, is another instance where something like 1,47,000 acres of forest land..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Keshava Rao, there are other three speakers from your side. I am just reminding you.

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, I just want your time. How much time do you want to give me, Sir? ...(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Till the discussion is over. ...(Interruptions)..

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, this kind of forest land is now being encroached upon. Now the easiest method devised by these mafias, you take the name of a State agency like in Andhra Pradesh, Andhra Pradesh Mining Development Corporation, in Karnataka, Karnataka Mining Development Corporation, in Jharkhand, Jharkhand Mining Development Corporation, in Orissa, Orissa Development Corporation. You first share those lands taken by them and you get in subcontract with them and APMDC man or the MDC man will be sweeping all through and you do whatever you like. It has been proved in the records, in the letters of the Ministry, including the Mining Ministry, the Minister is here. So, this kind of backdoor operations that have become popular now like in many other places in Jharkhand, Andhra and I do not know much about Karnataka in this

case, these two areas have become popular where everybody is utilizing the name of a State agency.

(Contd 3W/SSS)

ASC-SSS/3w/6.20

DR. K. KESHAVA RAO (CONTD.): Sir, whatever it is, one thing is sure, I cannot sit in the Rajya Sabha and try to advice or suggest on to the other States but, nonetheless, there are two views there. Government wants to be very firm as it looks, Government wants to be honest as it looks, but, the same time there are elements. These elements emanate from the very genesis which is draconian. So, these have to be curbed. These people have no name. They don't belong to any party. They don't belong to any sections of the society. They are nothing but criminals of the first order and hence if we have to face the issue squarely, the only thing is, let us have a ban on exports of iron ore, manganese and anything which are sensitive and let not any new permit be given in the eco-sensitive zones. Thirdly, Sir, if at all you try to give permit, because development has to go on, then, what we need to do is, give them value addition so as to help them.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, I have to go for breaking my fast. Hence, Dr. K. Keshava Rao will occupy the Chair if the house permits.

(THE VICE-CHAIRMAN (DR. K. KESHAVA RAO) in the Chair)

श्री गंगा चरण (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, आज illegal mining देश की एक बड़ी समस्या बन गई है। इस illegal mining से और भी समस्याएं पैदा हो रही हैं। आज नक्सलवाद का जन्म भी वहीं हो रहा है, जहां illegal mining हो रही है। एक तरफ लोग illegal mining से

करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और दूसरी तरफ वहां के स्थानीय लोग दाने-दाने के लिए मोहताज हैं। इसलिए सरकार को इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं उन सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने यहां discussion में भाग लिया है। सरकार को इस समस्या के बारे में बहुत ही गंभीर होना चाहिए, क्योंकि देश की जो अमूल्य खनिज सम्पदा है, उसका अवैधानिक तरीके से दोहन हो रहा है। जो पैसा देश के खजाने में जाना चाहिए,वह खजाने में न जाकर, कुछ माफियों के पास, उनसे जुड़े हुए तथा जिनका गठजोड़ है, कुछ नेताओं और कुछ अधिकारियों के पास जा रहा है। जिस तरह से कर्णाटक का मामला आया है और illegal mining से जुड़े हुए नेताओं के नाम आए हैं और अधिकारियों के नाम आए हैं, हमारे लिए यह शर्मनाक बात है।

(Contd. by LT/3X)

LP/3X/6.25

श्री गंगा चरण (क्रमागत) : सर, इल्लिगल माइनिंग से देश के राजस्व का ही नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि देश के पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। वहां जंगलों को काटा जाता है और उस जगह पर डायनामाइट लगाकर विस्फोट किए जाते हैं। माइनिंग की जो गाइडलाइन्स हैं, उन गाइडलाइन्स का पूरा उल्लंघन किया जाता है। यह अफसोस ही है कि जिससे देश को अपार राजस्व का लाभ हो सकता है, उस पर आज तक कोई प्रभावकारी नीति नहीं बनी है, कोई पॉलिसी नहीं बनी है। वह बात चाहे कोल माइनिंग की हो, आयरन माइनिंग की हो, ब्लैक ग्रेनाइट की हो, खास तौर से वेस्ट बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, यहां पर अमूल्य खनिज संपदा का भंडार है, लेकिन अफसोस है कि हम उस अमूल्य खनिज संपदा का सही तरीके से दोहन नहीं कर रहे हैं, उससे राजस्व का लाभ अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। हमारे एक सदस्य के प्रश्न के उत्तर में, जो कोल माइनिंग से है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो रेड डाली गई है, ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, वेस्ट बंगाल एण्ड झारखंड में अवैध खनन की जो रिकवरी हुई है, वह 8,161 टन की हुई है। इसकी

कीमत लगभग 96 लाख है। इसी तरह से यह अफसोस की बात है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, नॉर्दन कोल फील्ड लिमिटेड, वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, साउथ-ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, नॉर्दन-ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, महानंदी कोल फील्ड लिमिटेड तथा कोल इंडिया लिमिटेड, इन सारी कंपनियों के जो अधिकारी हैं, इनके द्वारा ही अवैध खनन हो रहा है, कोयले की अवैध ढंग से निकासी हो रही है । सरकार को अवैध खनन को रोकने के लिए तत्काल कोई कानून बनाना चाहिए, एक पॉलिसी बनानी चाहिए। सरकार को एक ऐसा सख्त कानून बनाना चाहिए कि इस धंधे से जुड़े हुए जो माफिया हैं, उन माफियाओं की संपत्ति को सी.बी.आई. के द्वारा जांच कराकर जब्त किया जाए, उनको जेल में डाला जाए और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत उनको बंद किया जाए। जब सख्त कदम उठाए जाएंगे, तो यह बंद होगा। इन माफियाओं के तार जिन नेताओं से जुड़े हैं, जिन अधिकारियों से जुड़े हैं, उनकी संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए। इन लोगों ने अपार संपत्ति अर्जित कर ली है और यह अवैध धन आज हमारी राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है। इस मुद्दे पर सभी लोग इसीलिए चुप हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर लोगों की इन्वोल्वमेंट है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर बहुत अमूल्य खनिज संपदा है, इसमें प्लेटिनम भी है, यूरेनियम भी है, इनका भी अवैध कारोबार है, यदि हमने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो माफियाओं का एक सशक्त ग्रुप खड़ा हो जाएगा। जिस तरह * चाहे वे पोलिटिक्स में हों, अन्य किसी क्षेत्र में हों, मीडिया के क्षेत्र में हों या सोशल वर्क के क्षेत्र में हों, जिस तरह से उन्होंने किसी क्षेत्र में कब्जा कर लिया है, उसी तरह से भारत में हमारी पार्लियामेंट पर, हमारे लोकतंत्र पर इनका कब्जा हो जाएगा।

AKG/3Y पर क्रमागत)

---

* **Not recorded.**

श्री गंगा चरण (क्रमागत) : पहले पॉलिटिक्स में समाज में सेवा करने वाले लोग आया करते थे, फटेहाल लोग आया करते थे, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग एमएलए/एमपी बन जाते थे। वे शासन/प्रशासन से अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ते थे।

उपसभाध्यक्ष (डा. के. केशव राव) : अगर आप समाप्त करें, तो अच्छा है, क्योंकि आपकी पार्टी के एक और speaker हैं।

श्री गंगा चरण : ठीक है, सर।

लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोक सभा और राज्य सभा में राजनीति पर पूँजी हावी हो गई है। अब पैसे वाले लोग ही राजनीति में आ रहे हैं। जो समाज की सेवा करने वाले लोग हैं, जो गरीबों, झुग्गी-झोपड़ियों, किसानों और मजदूरों के बीच काम करने वाले लोग हैं, वे आज एमएलए/एमपी नहीं बन पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अवैध खनन या और भी चीजों से जो गलत ढंग से पैसा पैदा कर रहे हैं, उन्होंने हमारी सत्ता पर, हमारे लोकतंत्र पर भी कब्जा कर लिया है। यह गम्भीर विषय है। इस पर हमें चिंतन करने की जरूरत है। सारे politicians, जो सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो स्टूडेंट राजनीति से या लेबर पॉलिटिक्स से या किसान आन्दोलन से निकलते हैं, वे अपनी सारी जिन्दगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन आज वे एमएलए/एमपी नहीं बन पाते हैं और संसद का या विधान सभा का मुँह नहीं देख पाते हैं। आज वे लोग, जो ठेकेदार हैं, जो खनन माफिया हैं, जो बिल्डर्स हैं, जो अन्य तमाम कारोबार से जुड़े हैं, वे आ रहे हैं। इसलिए आज illegal mining के subject पर जो discussion है, उसमें इन सब चीजों को जोड़ते हुए मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि यह राजनीति को प्रभावित कर रहा है, इसलिए हमें गम्भीर होने की जरूरत है और इस पर हमें सख्त-से-सख्त कदम उठाने की जरूरत है। थैंक्यू सर।

(समाप्त)

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA (ORISSA): Mr. Vice-Chairman, Sir, having listened to my colleagues I agree with whatever has been said by Mr. Yechury, Mr. Manjunatha, yourself and my friend, Mr. Ganga Charan. These are dealing with symptoms of the issue, that is, what has happened? But let us go into the core issue, why it has happened; what really has happened. What is illegal mining? Illegal mining has happened because of the laxities of the enforcement machineries of both, the State Governments as well as the Central Government. I do not defend any Government. You have the IBM. Ninety per cent and plus of illegal mining is over-production, without mining approval from the authority i.e., IBM. The IBM, the Directorate of Mines, the Department of Mines, everyone gets dispatch figures, everyone gets production figures. In the beginning, a mine owner is allowed to produce one lakh tonnes in a particular year, and, then, goes on and produce 8-10 lakh tonnes because there is a boom in the market. China was taking fines, which were lying in hillocks. It did not know how to dispose it of. Now, it is selling it off and making plenty of money. You receive the production figures. You also receive the dispatch figures. The IBM, at least, gets the production figures. The State Secretary receives the dispatch figures, which are going to ports for exports and which are going to other places in the country. Why were these figures not co-related? Over the years, over the decades, the cross-checking has fallen into disuse. Nobody was bothering. This is the biggest part of the illegal mining. Today, questions are being raised by the very people, who are doing the illegal mining, that they are sending one lakh tonnes and they are mining two lakh tonnes; they are mining less than that; they had been giving

all the figures in proper forms. What has happened now? Nobody had questioned us. But, now, you are arresting us!

(Contd. by 3z -- PK)

-USY/PK/6.35/3Z

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA (CONTD.): That is the plea they are taking before the investigating authorities. This is one aspect of illegal mining. The second aspect of illegal mining is this. Because there is a boom, prices are very high, now, go into the reserve forests or go beyond the mining areas. Some mine owners have crossed their boundaries. They have mined areas either in the buffer zone or areas belonging to the corporations or belonging to other mine owners.

Thirdly, other than the mine owners, mafias developed. When they found all these things going on, they also indulged in making easy money. As mentioned very clearly by you, Sir, easy money was the main thing. So, it went on. It has to be remembered that a lot of these mines are not approachable. Everybody in that area, from Constable to Forest Guard, whosoever it was, made money. I am aware that a lot of people have made money in the process. I do not want to point fingers to anybody. Though some of my friends are tempted to point fingers at others. I do not point fingers at others until *prima facie* evidence is available against them. My Chief Minister has ordered a vigilance inquiry, police inquiry.. (Interruptions)..

SHRI RUDRA NARAYAN PANY: At what level?

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: At all levels...(Interruptions).. If you are involved, you will not be spared. If you are involved, Mr. Pany, you will not be spared. If I am involved, I will not be spared. ..(Interruptions).. Nobody will be spared. ..(Interruptions)..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. K. KESHAVA RAO): Mr. Mohapatra, actually, your time is over, but you can speak for one more minute.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: Sir, please give me some time.

THE VICE-CHAIRMAN: Please do. ..(Interruptions)..

SHRI SITARAM YECHURY: He comes from that area.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: I come from a coal mining area.

THE VICE-CHAIRMAN: Please stick to the time-limit.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: So, what I am saying is, a lot of things are being put in place by the State Governments, by the Central Government, but there is a lot of politicization which is taking place. Everybody was making easy money. The Central Government also went for easy money. It mopped up something about Rs.250/- per tonne as export duty, without seeing what was being exported and how was it being exported? Five Chief Ministers including the Chief Ministers of Orissa, Karnataka, Rajasthan, Jharkhand, Chattisgarh and Madhya Pradesh have been knocking at the doors of the Central Government saying, "Please get us .."..(Interruptions)..

THE VICE-CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: Sir, I am the only Member from my Party.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. K. KESHAVA RAO): That is why we gave you five minutes. But you have taken eight minutes. All right. You take another one minute. ..(Interruptions).. Please. I cannot allow Mahapatra *ji*. Your time is five minutes. You have taken eight minutes.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: Mr. Yechury was allowed for 15 more minutes.

THE VICE-CHAIRMAN: Certainly not. I will call the records. That will not do. You take double the time you were allotted. I said five minutes but you take double of that. Now, carry on.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: So, I have three more minutes. Okay, fine. So, all these new systems have been put in place. But at the time when there was a boom, did the Central Government think of obtaining technology, using fines in this country? Or, everybody was happy that Oh, China needs so much because of Beijing Olympics, so, let the boom continue. Why was the royalty of 30 per cent demanded by these six Chief Ministers denied? Thirty per cent of the easy money made by the mine owners could have come over to the State Governments, to the poor States.

(Contd. by 4a/SKC)

4a/6.40/skc

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA (contd.): Why was it not done? After the bird had flown, after the prices came down, you are putting it as 10 per cent. What for? Now, you need to look at the issues on their face value. Look at illegal mining as a phenomenon; look at Dhanbad; look at all these things that are

happening around us. I come from a coal-mining town, Talcher. I have seen, as a child in the pre-Independence days, people working in the private mines coming in the evening with some coal and selling it off. It is easy money; multiply it a million times. This has happened. The enormity of the crime that was being committed was not appreciated at any time, either by Delhi or by other States. (Time-bell)

I would request you that instead of being with the mine-owners, be with the people. Please enforce mining plans when you talk of rehabilitation of tribals. Mining plans require that mining is done in a scientific manner, so that as you mine, you continue rehabilitating the mine. If you rehabilitate the mines, people would get back their lands. You won't have unrest. But mining plans are violated. It is 60 years now; nobody has looked into this issue. To check mining plan violations with the IBM is the Government's responsibility. State Governments have failed. We have arrested all the officers starting from the Director of Mines. Why haven't you arrested any one of your officers? That is my question.

(Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. K. KESHAVA RAO): Mr. Ramalingam; you have three minutes.

SHRI K.V. RAMALINGAM (TAMIL NADU)* : Hon'ble Vice Chairman Sir, I thank you very much for granting me this opportunity to express my views on behalf of my party AIADMK, in this discussion on large scale illegal mining. India is a land of so many resources. Our founder Dr. Puratchithalaivar M.G.R. has said in a song,

What is the resource that is lacking in this country

Why should we extend our hand to foreigners

A flag with a particular symbol should fly everywhere

And that is the symbol of food that denotes absence of scarcity".

If all the resources of our nation are properly utilized, all social problems such as scarcity, hunger, famine and poverty will be alleviated from our nation.

Coal is available in Jharkhand which accelerates the economic development of the state. Though many parts of Andhra Pradesh have been affected by drought, the presence of mineral resources in that

---

* **English translation of the original speech made in Tamil.**

state pave the way for economic development thereby providing employment to the people of that region. The granite stones obtained from Karnataka help the economic development of the state. Due to the Neyveli Lignite Corporation in Tamil Nadu, power generation has increased. A recent survey says that coal is present at Ullundhurpet, an area nearby Neyveli. If such coal resources are excavated, it would strengthen the economy of Tamil Nadu. When land is acquired for mining, proper compensation ought to be paid to the landowner in addition to providing employment to one member in that family. The Government should legislate a law accordingly. In Namakkal district of Tamil Nadu, many layers of platinum are found. Platinum is a precious metal. If proper efforts are taken to excavate this mineral, it would promote the economic development of the state and also guarantee employment to the people of that region.

Similarly, if all the mineral resources are excavated and are brought to international market, it would help the growth of economy. If the mineral resources are excavated only with the sole intention of amassing wealth, it would lead to environmental pollution. It also affects the health of the common people to a great extent.

Export industry occupies a prominent place in our country's economy. The granite stones exported from our country have become famous throughout the world. But, there should be a limit for the excavation of these granite stones. Mining should not be done to the extent of degrading the environment, bypassing all laws. The environment should be the consideration during mining instead of income.

Water resources are vital for the growth our agriculture. Presence of water resources varies across the various states of India. Some states have perennial rivers. But some states have to depend on their neighbouring states for obtaining water. Issues such as failure of monsoon, inter state disputes regarding sharing of water etc. affect the agricultural production. But without considering these issues, sand mining is done illegally which leads to drying of river water. In Tamil Nadu, sand mining is done at a large scale. As a result, water from rivers could not flow into the canal which is above the riverbed. Therefore, agriculture is affected in Tamil Nadu. Due to the mining of sand from river bed, sea water gets mixed with river water. The quality of ground water also changes due to extensive

sand plundering. Ground water turns unusable due to its increasing salinity. Due to large scale sand plundering in various parts of Tamil Nadu, ground water table is affected. People can not get safe drinking water.

In my district Erode, Coconut is grown in large number. Coconut trade is the livelihood of farmers in my district. The farmers are already in distress for not getting proper support price for the coconut produced. Due to sand plundering, ground water is also polluted. This in turn spoils the quality of the coconuts produced. When such poor quality coconuts are brought to the market, the farmers can not get proper procurement price.

As sand plundering is done above the level fixed by law, severe damages occur. The sand filters the polluting substances of the rain water that reaches ground water table. But due to sand mining, the polluting substances of water that reaches the ground water table were not filtered. The ground water table also gets polluted with the result that water becomes impotable. Such situation is experienced in Dharmapuri, Krishnagiri, Vellore and Kanchipuram districts of Tamil Nadu where the river water is not potable. People are affected by

many diseases due to the contamination of water in these areas. Palar River bed is also polluted.

Smuggling of mineral resources has increased throughout the country. Everyday smuggling of mineral resources is done through railways. Proper steps need to be taken to prevent such smuggling. Recently a media report has informed that due to the over mining of red sandstone near a bird sanctuary in Rajasthan, the bird sanctuary's compound wall has developed cracks and it is likely to collapse any time. The smugglers did not spare even bird sanctuaries.

Agriculture in Tamil Nadu is facing a severe water crisis as the Cauvery water dispute is not resolved between Tamil Nadu and Karnataka. More than 70 per cent of agricultural land in Tamil Nadu remains uncultivated. Thousands of truck loads of sand is mined in Tamil Nadu. They pay for two units of sand at quarries but take away more than five units of sand. According to law, more than two units of sand should not be carried in a truck. But the law is not followed. This illegal mining of sand not only causes revenue loss to the Government but also damages the roads, making them unfit for smooth travel. Therefore, road accidents also increase. In Cauvery

river bed, particularly in Karur and neighbouring districts, sand is plundered at a large scale. As a result, the farmers are suffering due to shortage of water and price rise. Agricultural production is affected. Enviornment is polluted.

When our party's general secretary Hon'ble *Puratchithalaivi* Amma was the chief minister of Tamil Nadu, she regulated sand mining and prevented plundering. She also increased the revenue of the Government by allowing sand mining rights only to the Government. In addition to this, rainwater harvesting was made mandatory by her. This was done with a good intention to provide safe drinking water. She also filed a case in the Supreme Court to get sufficient water from Cauvery for protecting farmers of Cauvery delta.

Now some journalists have exposed the plundering of granite in Tamil Nadu with the connivance of the rulers in Tamil Nadu State Government. Attacks and filing of fake cases against such journalists have become a continuing story in Tamil Nadu. The rights of sand mining in Tamil Nadu are given to some benamis of the ruling party men in Tamil Nadu. They plunder in crores of rupees with the connivance of the State Government. The sand which is plundered

illegally in Tamil Nadu is exported to Maldives. The Union Government should look into this issue and take strict measures against those plunderers in order to protect the mineral resources, sand resources, water resources and all other natural resources of the nation. With these words, I conclude my speech. Thank you. (**ENDS**)

(Followed at 4b/hk)

HK/4b/6.45

THE VICE-CHAIRMAN (DR. K. KESHAVA RAO): Mr. Raja, you have only three minutes.

SHRI D. RAJA (TAMIL NADU): Sir, the House has taken up this serious issue for discussion. Like natural gas, minerals and ores are national assets. They are the wealth of the nation. They are the common wealth of our nation, not the common wealth of the Games.

(Contd. by 4c/GSP)

GSP-MP-4C-6.50

SHRI D. RAJA (contd.): Sir, the illegal mining is one way of plundering the national wealth, looting the national wealth, as said by my previous speakers. To understand the dimension of the problem, I would like to simply quote the statement made by the Minister a couple of days ago in this very House.

The second para of the statement says, "Due to a combination of reasons in recent years, the incidence of illegal mining has grown considerably. This

problem is acquiring organised dimensions and may lead to a nexus with criminal and anti-national elements in some of the States including those affected by Left Wing Extremism."

This is an official statement made by the Minister in this very House. If that is so, it is a crime and there is a nexus with criminals and anti-national elements. How is this crime being allowed to continue like this? I squarely say that it is the failure of the Central Government as well as the respective State Governments. The Indian Bureau of Mines identified some 17 States where such illegal mining is going on. The worst affected States are Karnataka, Andhra Pradesh, Orissa, Jharkhand and several other States including West Bengal for coal mining also. Around 15 to 20 million tonnes of coal is illegally mined annually by the coal mafia, which has stronghold in coal-bearing regions, especially, in Jharkhand and West Bengal.

I am not getting into the details but this crime continues, the loot of the nation continues. What are the reasons? Are we not having enough laws to curb this crime, to put an end to this crime? We have enough laws. The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, you have in your hands. The Minerals Concession Rules, 1960, you have in your hands. Forest Conservation Act, 1980, you have in your hands. Apart from these, you have the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974; the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974; the Environmental Protection Act, 1986; the Forest Rights Act, etc. All these laws are available. With all these laws, how can we fail to fight

this menace, fight this crime? I think, it is basically, primarily the failure of the Central Government as well as the State Governments.

Now, Sir, I come to one or two small points before I conclude. Now, Obulapuram, Bellary is being referred to mention how this illegal mining of iron ore is done. It is not the question of export only. There are some crucial questions. Why does the customs duty continue to be five per cent, which is so low, on iron ore? Why does the royalty continue to be so low? Several Members spoke on this issue. These are certain practical steps which the Central Government, with powers in its hand, can take, or, which the State Governments can take. But why do they fail? I have a doubt that there is a nexus between the politicians, criminals, and, I don't know who these anti-national elements are. The Minister has identified it here. It is a nexus between criminals and anti-nationals, and, also a nexus with politicians also. When I say, politicians, I do not name any political party. Definitely, we are not there. The problem is that the political will on the part of the Union Government... (Interruptions)...

SHRI RUDRA NARAYAN PANY: Mr. Raja, you are an associate in Orissa.

SHRI D. RAJA: Who? (Interruptions) Even when we associate.. (Interruptions)

श्री रुद्रनारायण पाणि : आपका चुनाव गठबंधन था। ...(व्यवधान)... In the elections, you were the associate. (Interruptions)

उपसभाध्यक्ष (डा. के. केशव राव) : पाणि जी, मेरी मदद कीजिए। ...(व्यवधान)... पाणि जी, ज़रा मदद कीजिए। टाइम कम है। ...(व्यवधान)... राजा जी, बोलिए। No, no. Raja, let us go with this. (Interruptions) पाणि जी, ज़रा मदद कीजिए। Right, right.

SHRI D. RAJA: Mr. Pany, even if we associate, we never fail to fight against the wrong things.

(Contd. By YSR-4D)

-GSP/YSR/6.55/4D

SHRI D. RAJA (CONTD.): You shared Government with them. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. K. KESHAVA RAO) : Mr. D. Raja, you have already taken double the time.

SHRI D. RAJA: Sir, due to paucity of time, I will not go into the figures as to how much iron ore has been illegally mined and exported and all these things. It is a serious crime. It is a betrayal of country's interest. How can the Central Government and the State Governments remain mute spectators, or collaborators, to this huge crime? That is my question. I do not think the Central Government is not aware of the crime and those criminals or the respective State Governments do not know who the criminals are. Then why did both the Governments keep quiet? Why are they not taking any serious action against these people? In fact, it is a serious thing. There are some Ministers of the Government. Once I raised this issue on the very same floor. What happens to the code of conduct for Ministers? If they are doing mining illegally, how can they continue to be Ministers in a particular State Government? I raised this question and there was no answer from the Government. Illegal mining, ill-gotten money, and super profit earned through illegitimate means affect the very polity of the nation. It affects the democracy of our country. This has to be fought. I ask the Government this question. What action is the Government going to take? You

have said that you are going to constitute an Enquiry Commission. That Enquiry Commission will be given 18 months' time. What kind of enquiry do you want to do? The facts are before you. It is known to everybody. And the Government should not behave as if it is naïve, not knowing all these things. What is the Enquiry Commission going to do? Why are you giving it 18 months' time? It should have a short time-frame, say, three months, or six months. Catch hold of the criminals, take firm action, and save the nation. We are asking the Government that since you are in power, so you have to save the nation. You nationalise it. It is national wealth. You nationalise it and save the nation.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. K. KESHAVA RAO): You and Mr. Yechury have said it.

SHRI D. RAJA: If you don't save the nation, people will not save you. With these few words, I conclude. Thank you, Sir.

(Ends)

SHRI M.V. MYSURA REDDY (ANDHRA PRADESH): Sir, the illegal mining of coal, iron ore, granite, and sand is being done in broad daylight. But we are discussing 'illegal mining' during night time.

Sir, in 2006, I opened this Pandora's box of irregular sanctioning of iron ore mines to OMC company and encroachment on forest land and on land belonging to other people.

But now the scope of the discussion is entirely different. With due apology to the Chair, as an example, I want to show the photograph of a Sunkulamma temple.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. K. KESHAVA RAO): You should not show it.

SHRI M.V. MYSURA REDDY: I know that. SB Logistics exported ten million tonnes, and ILC Company Limited exported ten million tonnes. I know that Dalmia surrendered 1,200 acres of land because now the mineral has vanished from that area. I know about the companies. But because of decency, decorum, and procedure of this House, I don't want to mention the names. This wealth has gone to China and they earned, as you told when you spoke from that side, twenty crore rupees per day.

Of course, I know that Karnataka Chief Minister is in a piquant situation. He's willing to wound, but afraid to strike. Anyhow, he banned the export of minerals out of Karnataka.

Sir, the *Deccan Herald* exposed on 6th that lorries were queued up at Hagari check post.

(Contd. by MKS/4E)

MKS-MCM/7.00/4E

SHRI M.V. MYSURA REDDY (CONTD.): Thousands of lorries were carrying iron ore to Andhra Pradesh border for export from the Andhra sea ports. Sir, since you are occupying the Chair, I do not want to mention, but in Karnataka, the Karnataka Congress people had made a Maha Padayatra demanding, I think so, the ban of export of iron ore. But it seems as if the lorries are coming to Andhra and are going to the sea ports. Why the Andhra Government did not ban the export of iron ore from our sea ports, I do not understand, Sir. Probably, they

may be interested in reconciling the Odarpu Yatra while the Karnataka Congress people are doing the Maha Padayatra! ...(Interruptions)... Sir, in Zero Hour, on 25th November, 2009, I raised this subject of illegal mining and irregular sanctions; how they were looting the country's wealth, but the Government did not take cognizance of that. But Mr. Deve Gowda, our ex-Prime Minister, also raised this matter in Zero Hour, but I am happy that the Minister gave a reply to him. In that reply, the illegal mining activities in Rajasthan, Orissa, AP and Karnataka he had accepted. One thing more, Sir. Meanwhile, in the Ministry of Finance, the Department of Revenue also recognised this thing, and I quote from the Memorandum:

> "It was decided that Customs Commissionerates shall share the details of minerals exported through the Ports within their respective jurisdiction with the concerned State Governments on a periodical basis."

But I do not know whether they are reconciled with the State Governments or not. They might have been reconciled. But what is the extent of illegal mining of iron ore that has been exported to the other countries? That also might have been known, Sir. Now, the Minister has made a statement that he is going to form a Commission on illegal mining, Sir. Will the Minister explain the terms of reference? What more substantial evidence does this Government require to curb this illegal mining? The Commission is an eyewash and also part of delay tactics, Sir. There is not need of setting up a Commission. They can straightway ban the export of iron ore and coal also. It is unfortunate, Sir, that he was expressing that the technology, in India, is not available. Sir, I am sorry to cement; the pithead

pelletization technology is available in India even with low grade iron also. This is almost misleading the House as you were also expressing while sitting on this side. Regarding Bayyaram ... (Time Bell) ... I am concluding, Sir. The Minister, in the other House, gave a statement:

> "We gave the reservation to the Government of Andhra Pradesh for A.P. Mineral Development Corporation. Reservation means merely blocking the area for a certain length of time for conservation."

Sir, the Andhra Government issued a G.O.Ms.No.64, on 30-06-2010. I quote:

> "In the reference 4th read above, Government of India have conveyed the prior approval for reserving Iron Ore bearing areas of 56690.00 hectares in Bayyaram, Garla and Nelakondapally Mandals of Khammam district for exclusive exploration for 10 years in favour of M/s Andhra Pradesh Mineral Development Corporation Limited under Section 17A(2) of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act."

These people entered into an MoU with Rachana Steel.

(Time Bell) I am concluding, Sir. In half-a-minute, I am concluding.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. K. KESHAVA RAO): You can take one minute and conclude.

SHRI M.V. MYSURA REDDY: Thank you, Sir. The illegal iron ore mafia, economically, is so strong that they are corrupting the political system; they are corrupting the bureaucracy. They have extended their tentacles to the judiciary also.

(Contd. by TMV/4F)

SHRI M.V. MYSURA REDDY (CONTD.): I am sorry to comment like this. They are looting the national wealth. That is why I have to comment like this. The Government gets revenue to the tune of Rs.2 crores to Rs.10 crores per million tonnes of iron ore which is exported. If value added goods are exported, the Government would get Rs.250 crores by way of excise duty, VAT, etc. That is why, in the interest of the nation and in the interest of the future of the nation, I suggest auctioning of iron ore blocks through a bidding process for captive consumption, banning export of raw iron ore and allowing export of value-added goods. As regards the irregularities, I also demand an inquiry into the irregularities. But there is no need for a commission. The Government may constitute a JPC for a statutory probe into illegal mining. Thank you.

(Ends)

श्री के.बी. शणप्पा (कर्णाटक) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय। यहां पर illegal mining के ऊपर चर्चा शुरू हुई है। सबके दिमाग में यह आ रहा है कि हिन्दुस्तान में जहां भी deposits हैं, चाहे मैंगनीज हो, आयरन हो, गोल्ड हो, लाइमस्टोन हो, यूरेनियम हो, जो कुछ भी धरती मां ने अपने पेट में छुपा रखा है, उसके बारे में, आप सब समझ रहे हैं कि हर चीज़ को illegally निकाला गया है। मैं ऐसा नहीं समझता हूं। जब-जब इसकी जरूरत पड़ी तब तब कुछ legally निकाला गया है। यहां पर सीताराम येचुरी जी ने इसका उल्लेख किया। हम तो समझ रहे थे कि ..(व्यवधान)..

श्री राजीव शुक्ल : आपके हिसाब से illegal mining नहीं हो रही है ? ..(व्यवधान)..

श्री रुद्रनारायण पाणि : आप इनकी पूरी बात सुनिए। ..(व्यवधान)..

श्री के.बी. शणप्पा : एक मिनट, आप मेरी पूरी बात सुनिए। ..(व्यवधान).. आप बड़े आदमी हैं। ..(व्यवधान)..

श्री रुद्रनारायण पाणि : शुक्ल जी, ये नॉन हिन्दी स्पीकिंग स्टेट से हैं। वह हिन्दी में बोल रहे हैं। ..(व्यवधान)..

श्री राजीव शुक्ल : वह हिन्दी में बोल रहे हैं, इसकी तो हम प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। ..(व्यवधान).. लेकिन हिन्दी की आड़ में आप चोरी को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। ..(व्यवधान)..

श्री के.बी. शणप्पा : आप क्या बोल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरी बात सुनिए तो सही। ..(व्यवधान).. आप पता नहीं कहां थे, अभी दिखाई दे रहे हैं। ..(व्यवधान).. आप बीच में दखलअंदाजी कर रहे हैं। ..(व्यवधान).. सर, मैं इस बहस में ज्यादा नहीं पड़ना चाहता हूं। उड़ीसा में illegal mining हुई है और दूसरी जगहों पर, जहां-जहां deposits हैं, वहां पर illegal mining हुई है। कर्णाटक को मुद्दा बनाकर हर कोई यहां पर बेल्लारी की बात कर रहा है। कर्णाटक असेम्बली की बैठक तीन महीने पहले हुई। वहां पर इसके बारे में जोरदार बहस हुई। Mr. Vice-Chairman, Sir, you and everybody here in this august House have seen the scene. वहां के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि "भाई साहब, आप लोग जनता की तरफ से प्रतिनिधि बनकर आए हैं। हमको मेजोरिटी से लोगों ने चुनकर भेजा है। आप लोगों ने 55 साल कर्णाटक में राज किया। हमें ढाई साल हो गये। आपकी अपोजिशन पार्टी को किस तरह से हाउस में फ्लोर पर बिहेव करना चाहिए। Mind your business and tolerate us. Whatever problems that you have, you bring before me. I am here to answer your questions. Whatever document you want, I am here to provide you". Regarding illegal mining activities in Bellary, the Bellary brothers were made the target. Why? Do you mean to say that they are the only people who are exploiting the deposits? मेरे पास बहुत डाक्युमेंट्स हैं। यहां पर चर्चा चली, नॉन-

पालिटिकल चर्चा चली, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं उस prospective के बारे में नहीं सोचता हूं, ढाई साल में वहां की गवर्नमेंट लोगों की समस्याओं के साथ जूझ रही है।

(ass-vk/4g पर जारी)

VK/4G/7.10

SHRI K.B. SHANAPPA (CONTD): They are very near to the people and approaching them. They have made hundreds of plans for the development of SCs, old people, ladies, Anganwadis. He has almost attending to all of them. He wants to do the best possible for the people of the State. Forgetting all these things, the mudda of Bellary has come all of a sudden. मैं यह नहीं समझता कि इसके पीछे कोई राजतंत्र नहीं है। मैं 1957 में 8वीं क्लास में पढ़ता था। That was the first elected Communist Government in Kerala. But the Centre was not happy to see that Government. They wanted to destabilize that Government. A Communist Government was elected by the people of Kerala, not by any revolution. Ballot revolution took place. That Government was approaching the people with progressive ideas. But the people sitting in Delhi could not tolerate it. At the same time, in Congo, there was the Government of Patrice Lumumba. The CIA planned to destabilize the Government in Congo. A lot of plots had taken place and we know it, the politicians here know it. I am going to talk in that perspective. For the first time in South, a BJP Government has been brought by the people of Karnataka. Do you think that the people sitting here in Delhi are happy? We have ruled Uttar Pradesh. We are in Himachal Pradesh, Uttaranchal, Gujarat, Bihar and Madhya Pradesh. The people sitting in Delhi never thought that the BJP will

enter Karnataka. All of a sudden, a lot of change has taken place in South and that has become the gateway of South. We have not only formed a Government in Karnataka, but also we have given a popular Government there. I do not want to mislead this House, Sir. In 50 years, I have seen many Chief Ministers. As they could not tolerate the Government in Kerala in 1959 under the name of vimochanasamaram; they started it because they opposed the Education Bill of Prof. Mundasseri. Mannam Pandnabhan was the leader. Shrimati Indira Gandhi was the President of the Congress Party here. So, that Government was destabilized. यह जो conspiracy है, I am feeling यह BJP गवर्नमेंट वहां पर किस तरह से काम करने लगी। इसका influence बाजू के स्टेटों में भी जाएगा। Ultimately, it is politics. Bellary is a mudda. When the Chief Minister said, "You come over here. Let us have a dialogue. I am prepared to talk about whatever you want". कितनी illegal mining हुई, किधर-किधर से हमारे जमाने में हुई?

आपकी तरफ से कितने लोग हैं जो आज आपके साथ बैठकर उधर पुकार रहे हैं। मैं उसका पूरा ब्यौरा दूंगा। आपने सीन देखा होगा, अपोजिशन लीडर goes like this. जब तक आप dialogue के लिए तैयार नहीं हैं, जब आपके मन में पाप है, आप वहां पर बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होंगे। बिना चर्चा किए, आपके सामने गवर्नमेंट के विचार कैसे आएंगे? You ask for the documents from the Chief Minister. Being the Leader of the Opposition, you have got every right to ask for it. You have got the Cabinet darja. You have left all these things. You have given a slogan, " जब तक आप राजीव प्रताप को नहीं निकालेंगे, हमारा मूवमेंट जारी रहेगा और रोडों पर जाएंगे, बेल्लारी में जाएंगे। क्यों, बेल्लारी में उनका क्या है? उनका तो धन्धा चलता है आनन्दपुर डिस्ट्रिक्ट में। ओबलापुर आनन्दपुर डिस्ट्रिक्ट में है।

(क्रमशः 4H/LP पर)

श्री के.बी.शणप्पा (क्रमागत) : इन्होंने ओपनली कह दिया on the floor of the House, अगर वहां पर मेरा माइन्स का छोटा सा भी धंधा चल रहा है तो आप इंक्वायरी कराइए, आप जो भी पनिशमेंट देंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। उनका धंधा आंध्र प्रदेश में चलता है। आपको भी मालूम है कि आंध्र प्रदेश में किनके साथ उनका धंधा है। आप लोग मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? Who are the people who are encouraging them? अपने रिकॉर्ड्स को लेकर आइए, हमारे पास भी बहुत कुछ रिकॉर्ड्स हैं। If the Chair permits,...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. K. KESHAVA RAO): Not necessary.

SHRI K.B. SHANAPPA: I don't want to highlight the names of people...(Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA: The Chair knows it.

SHRI K.B. SHANAPPA: I have got it. The Chief Minister has already highlighted the names of people, who are in the Treasury Benches here, and in the Opposition there...(Interruptions)

श्री राजीव शुक्ल : .ट्रेजरी बेंच...(व्यवधान)..लोग इतने साफ-सुथरे कैसे हो गए..(व्यवधान)..ट्रेजरी बेंच ...(व्यवधान).. ब्लेम करने के लिए यह कौन सा तरीका है.(व्यवधान)..

श्री रुद्रनारायण पाणि : आपको पता है..(व्यवधान)..

श्री राजीव शुक्ल : आपको पता नहीं है, आप चुप रहिए..(व्यवधान)..अहलुवालिया जी बोलने के लिए बैठे हैं..(व्यवधान)..आपके रूडी जी हैं..(व्यवधान)..

श्री रुद्रनारायण पाणि : आप चुप रहिए..(व्यवधान)..

श्री मोहम्मद अली खान : आप क्यों लड़ रहे थे, बात बराबर की है..(व्यवधान)..

श्री रुद्रनारायण पाणि : आप ऊंची आवाज मत निकालिए..(व्यवधान)..

श्री मोहम्मद अली खान : हमें भी ऊंची आवाज में बात करने का हक है..(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (डा. के. केशव राव) : खान साहब, आप बैठिए प्लीज..(व्यवधान)..आप बोल सकते हैं..(व्यवधान)..आपको पुकारने की क्या जरूरत है..(व्यवधान)..

श्री राजीव शुक्ल : आंध्र वाले साफ-सुथरे हो गए..(व्यवधान)..

श्री एस.एस. अहलुवालिया : सर, अच्छी भली डिबेट चल रही थी, अगर राजीव शुक्ल जी बीच में आकर पिन प्रिक करेंगे तो यहां पर लोग चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हैं..(व्यवधान)..

श्री रुद्रनारायण पाणि : मैं निवेदन करता हूं..(व्यवधान).. शुक्ल जी वहां बैठे हैं..(व्यवधान)..पार्लियामेंट के अंदर ..(व्यवधान)..सदन के अंदर ड्रामा करते हैं..(व्यवधान)..कंफ्यूज करते हैं..(व्यवधान)..

श्री राजीव शुक्ल : पार्लियामेंट में बहस से क्या मतलब ..(व्यवधान)..आपको कुछ पता है? ..(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष : राजीव जी, बैठिए..(व्यवधान)..

श्री रुद्रनारायण पाणि : यह नहीं चलेगा..(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष : यह ठीक नहीं है..(व्यवधान)..उनको कुछ बोलने दीजिए..(व्यवधान)..

श्री एस.एस.अहलुवालिया : सर, सदन पहले से चल रहा है..(व्यवधान)..सदन की कार्रवाई शांति से चल रही है। फर्स्ट स्पीकर के टाइम में पहले से ही राइडर लगा दिया गया है एक-दूसरे पर नाम लेकर मत बोलिए। अगर आप नाम सुनना चाहते हैं..(व्यवधान)..

श्री के.बी.शणप्पा : नाम भी बताएंगे।

श्री एस.एस.अहलुवालिया : अगर आप नाम सुनना चाहते हैं, लिस्टिड नंबर सुनना चाहते हैं, तो देखिए, यह बैग पूरा भरा हुआ है, अगर कहेंगे तो खोलकर दिखाता हूं। ..(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष : नहीं, नहीं, हो गया है।

श्री एस.एस.अहलुवालिया : हमारे पास सब कुछ है, किंतु फोटो सहित दिखाऊंगा, फिर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, इसलिए शांत रहिए।..(व्यवधान)..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. K. KESHAVA RAO) : Shanappaji, the hon. Leader of the Opposition should speak. You must leave some time for him. Please have consideration because there are a lot of things to be said.

श्री के.बी.शणप्पा : सर, शुक्ल जी, बीच में आकर मेरे टाइम को ले रहे हैं। ..(व्यवधान)..

THE VICE-CHAIRMAN: You have already taken fifteen minutes. आप कंक्लूड कीजिए।

श्री के.बी.शणप्पा : मैं यह कह रहा था कि आपने शायद महाभारत की कथा सुनी होगी, the eyes of the enemy, that is, the Kauravas, were on Bheema. महाभारत की कथा में Bheema was the man who saved Pandavas, when they were in trouble. He killed all the 100 Kauravas with his *Gadha*. आप लोगों ने उन लोगों को टारगेट बनाया, जिनको फिनिश करने से वे अपने आप में लड़ेंगे और हमारा उल्लू सीधा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा।

(Continued by KS/4J)

4j/7.20/ks-akg

SHRI K.B. SHANAPPA (Contd.): You may allow me to read the letter written by the Chief Minister or...(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: You may place it on the Table; that would do. Anybody can use it. (Interruptions) You may lay it. Whoever wants to use it can use it.

श्री के.बी. शणप्पा : सर, मैं दो मिनट में बोल दूँगा। ... (व्यवधान) ...

THE VICE-CHAIRMAN: You have to keep time in mind. (Interruptions)

श्री के.बी. शणप्पा : एक मिनट, सर। हम लोग 2008 में आए। इससे पहले 1998 से लेकर 2004 तक आपकी गवर्नमेंट थी और कौन चीफ मिनिस्टर थे, आपको मालूम है। 2004 के बाद जो गवर्नमेंट आई, that was a coalition Government with the JD(S); your Chief

Minister was there. Till 2007, the Government was led by the Congress in coalition with the Janata Dal (S). उनके जमाने में क्या-क्या हुआ, मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बात छेड़ी गई है कि किनके जमाने में कितना लूटा गया।

उपसभाध्यक्ष (डा. के. केशव राव) : एलओपी साहब बोलेंगे, शणप्पा जी प्लीज़ समाप्त कीजिए।

श्री के.बी. शणप्पा : कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 2004 की ... (व्यवधान) ... I am going to complete it, Sir. Kindly allow me to...

THE VICE-CHAIRMAN: How much time do you want?

श्री के.बी. शणप्पा : सर, पाँच मिनट दे दीजिए। ... (व्यवधान) ...

THE VICE-CHAIRMAN: No, no; this is impossible. Please understand me.

SHRI K.B. SHANAPPA: Forty-three cases were... (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: No, no. Shanappabhai, please understand me. (Interruptions)

SHRI K.B. SHANAPPA: Permissions given were seven; notifications issued were 33. During Kumaraswamy's time: 47 cases were referred; 22 were given... (Interruptions) ...19 were given permission. गवर्नर के जमाने में, 15 दिन तक गवर्नर थे, उनके जमाने में सबसे ज्यादा illegal mining का issue हुआ। (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: Mr. Yechury referred to all that. He has referred to the Governor and all that. (Interruptions)

SHRI K.B. SHANAPPA: Sir, Yeddyurappa has categorically stated... (Interruptions) Just one minute more, Sir, and I am concluding. From 2008 till today, he has issued only two permissions. One did not materialize at all and, in another, they have asked for the goldmine. Both of them have not materialized and we are saying that this is the Government during whose time all the illegal

mining activity has been carried out. I am sorry to say this. So, kindly bear this in your mind that he has come out openly to request the Prime Minister of the country कि सर, अगर कहीं भी ये चीज़ें चल रही हैं, तो आप हमारे कान पकड़िए, बुरे लोगों को नियंत्रण में रखिए और एक सेंट्रल कानून बनाइए। Illegal mining को बंद कराने का कोई भी रास्ता आप निकालिए, तो हम आपकी तरफ हैं।

इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। थैंक्यू सर।

(समाप्त)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. K. KESHAVA RAO): Please, it is over. Thank you. Shri Anil Lad.

SHRI ANIL H. LAD (KARNATAKA): Sir, I would like to disclose that I am in the mining business, as this disclosure is required under the rules of the House. सर, हम लोग 1956 से बेल्लारी में mining कर रहे हैं। 1956 से हमारी family mining में है। आज illegal mining के ऊपर जो लोग बोल रहे हैं, वह 2002 से चालू हुआ है। सर, मैं इसका कारण सदन को बताना चाहता हूँ। 2002 में जब globalization हुआ, real estate economy बढ़ी, जिसमें iron ore और स्टील की माँगें भी बढ़ी। There was a technology from China with the help of which small sponge iron units were coming up in Hyderabad, Bellary and other such places. Two hundred to three hundred industries came up around Bellary and Hyderabad. The required investment was only Rs.20 and Rs. 25 crores. A lot of people put up industries. For this industry, the material required was hard tumbler material. उसमें जितनी भी बेल्लारी के आस पास माइन के नीचे की जमीन है, उस जमीन में पत्थर आने लगे हैं। I know a lot of Members have spoken about it.

(4के/डीएस पर जारी)

श्री अनिल एच. लाड (क्रमागत): खेतों में हमारे जो फार्मर्स हैं, जब उनको पता चला कि उससे उनको अच्छा धन मिल रहा है तो उन्होंने उसको निकालना चालू किया। Then mining was started by a lot of companies. सर, विदाउट परमिट माइनिंग, इल्लीगल माइनिंग है। जो आदमी mining concession लेता है और वह उसे परमिट से निकालता है या सेल करता है, that is legal, लेकिन जो illegally sale करता है, that is illegal. It started in 2002. Today, the newspaper, Vijay Karnataka, says that in 2004-10, near about 3 crore tonnes of material has been illegally mined. सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि my friend-colleague said now that the BJP Government in Karnataka is in power only for two years now. I would like to correct that. They were in a coalition Government from 2006-onwards with JD(S) headed by Mr. Kumaraswamy. The Deputy Chief Minister was Mr. Yeddyurappa. Please understand this. The mining * is a threat to democracy.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. K. KESHAVA RAO): The word * will not go on record.

SHRI ANIL H. LAD: This was released in 2006 and it appeared in all the newspapers. CNN-IBN has done a lot of reporting on illegal mining. (Interruptions)

SHRI K.B. SHANAPPA: Sir... (Interruptions)

SHRI ANIL H. LAD: Sir, he was not in power. (Interruptions)

---

*Not recorded .

THE VICE-CHAIRMAN (DR. K. KESHAVA RAO): Allow the hon. Member to continue. (Interruptions) Mr. Shanappa, hon. LOP would be responding to your points; he knows how to respond.

SHRI ANIL H. LAD: Sir, he is taking my precious time. (Interruptions) In 2006, I was an MLA and from my district only one among the Reddy brothers was the District Minister during that time also. This illegal mining, Sir, the illegal mining to the extent of 71 lakh tonnes which was done in 2009-10; the Karnataka Chief Minister admitted in the Assembly that the illegal mining had happened. Hon. Justice Santosh Hegde had been interviewed by CNN-IBN and he frankly said that there was no law and order in Bellary, "If I want to go and survey, I require police protection.' These are the words he spoke.

Sir, I would like to say what our contention is. The Lokayukta can survey only where the mining has been done. Ultimately, they can only submit a report indicating the quantity that is moved out. सर, बेल्लारी में कोई पोर्ट नहीं है। अगर बेल्लारी से कोई माल कहीं जाना है तो कम से कम 500 किलोमीटर दूर जाकर उसको रवाना करना पड़ता है। Bellary is connected with 6-7 ports. The Government should take note of the quantity of material that has been exported from which port, whether there was a legal permit or not; they have registered Singapore, Hong Kong, Malaysian benami companies. आज उधर आयरन ओर्स की प्राइस 150 यूएस डॉलर है, तो उन्होंने इसे over-invoice करके 200-220 डॉलर कर दिया। इल्लीगल माइनिंग का जो कैश पैसा था, वह इधर से हवाला से होकर उधर गया और फिर उधर से यह पैसा ऑफिशियल होकर इधर आया। I would like to say, if the Lokayukta, Justice Santosh Hegde can go into all these details, it would be nice. I am saying that even the CBI

cannot go into this because it is very, very technical. What I am saying is, let there be an inquiry even on us which includes the permits that we have, on the quantities we have exported, where we have exported, whether we have done under-invoicing or over-invoicing. There is MMTC also. Every month, there is a GSM pricing. It can be ascertained in which month what is the export. Say, in the month of June, the price can be $90; in the month of March, it goes to $180. So, there is a lot of variation in the prices. My esteemed friends are saying that the permission should be given only on value addition.

(Contd. By tdb/4l)

TDB/4L/7.30

SHRI ANIL H. LAD (CONTD.): Sir, recently, a global meet was held in Karnataka. I request all the hon. Members to listen to this. Sir, the person who is Minister in-charge in Bellary colludes his hands with Andhra Pradesh, and says, "I will put one steel plant in 2006 in Cudappa" Sir, today, we are in 2010, and the plant is not existing there, and a lot of mining leases have been issued on that plant. Again, today, in Karnataka, there is a global meet. Arcelor Mittal comes and says, "I will invest Rs.30,000 crores in Bellary". The Minister from that District who has a company in his wife's name said, "We will invest Rs.36,000 crores". Sir, I would like to say in this House that when I am a mine-owner for the last 44 years, and I don't have that kind of money, how can the Minister say "I can invest Rs.36,000 crores in Bellary, and Rs.30,000 crores in Cudappa"?. So, wherefrom this Rs.66,000 crores coming? I would like to know from my friends whether you have

given permission to the company for investment of Rs.36,000 crores in Karnataka or not. You have to agree to it.

SHRI K.B. SHANAPPA: Let the Customs and Income-tax authorities investigate it. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. K. KESHAVA RAO): Let him say whatever he wants to say. ...(Interruptions)... Mr. Lad, you please address the Chair.

SHRI ANIL H. LAD: Sir, a high-level committee has been formed in the State to scrutinize all these plants. Lot of investors have come and put applications in Karnataka. The Karnataka Government rejects these applications, and says, "We don't have water and land in the State of Karnataka". In the next three months, they give the permission for these two big plants, Sir. It is being given by diverting 84,000 acres of agricultural land. This agricultural land is being diverted for setting up industries. Can we imagine that 84,000 acres of green agricultural land is being diverted? Bellary's temperature in summer goes up to 45 degree centigrade. In Bellary, we have the JSW's biggest steel plant from 1993. Every year, they are asking the Government of Karnataka to give them a lease, but the Government of Karnataka is not giving the lease to JSW. But, without a plant, they allotted the land and even given the mining leases for this company. Please understand, this is not a small scandal. This is going to be the biggest scandal in the name of value-addition. We have plants, but we have not been allotted mines. We have put our application, but we have not been allotted the land. So many other people have also applied for that. Sir, what I am saying is, this high-level committee... (Interruptions)

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, we have been hearing the hon. Member. He was kind enough to disclose his interests, when he started, but in the course of the speech, he can't start making a grievance that his company has not been allotted the lease. This is the direct conflict of interests. (Interruptions) I can quite understand the concern of the hon. Members. This issue has been raised by Mrs. Karat earlier also. On generic issues concerning the industry to raise it, but then to start making a grievance of your own lease being granted or not being granted, that is the direct conflict of interests, which should not be allowed. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. K. KESHAVA RAO): It is a matter of expression. (Interruptions) The word "I" brought the personal angularity to it. Let us avoid that. (Interruptions) Please conclude your speech.

SHRI ANIL H. LAD: Just a minute, Sir. The Andhra Government conducts a CBI Inquiry. The person who is saying that he is ready for any inquiry, goes to the High Court and gets a stay on the CBI Inquiry. Today, they are saying that they are as pure as 24 carat gold, and they have not done any such thing. (Time-bell) Sir, the Lokayukta mentioned in its Report that 99 illegal mining happened in Bellary. Sir, I would like to quote here one thing. The Lokayukta used this GPS-72 equipment to survey our lands. When the lands were allotted to us, it was surveyed by chain and the land was given to us.

(Contd. by 4m-kls)

SHRI ANIL H. LAD (CONTD): When a GPS survey was done, even if the Parliament is surveyed by this equipment, there will be a variation in that. On that we have gone to court and got the stay. ...(Interruptions)..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. K. KESHAVA RAO): Let us avoid personal angularity to it, okay. ...(Interruptions)..Let us not bring personal angularity to the debate. ...(Interruptions).. Please, your time is also over. ... (Interruptions)..

SHRI ANIL H. LAD: Sir, I would like to say मैं अपनी जगह पर illegal mining नहीं करने दूंगा। There are barren lands, forest barren lands पर जाकर illegal mining हुआ है। One Dalimia mine which is twelve acre mine which is available in Hospet उधर से बहुत सा माल चोरी हुआ है। Sir, I want this survey to happen very fast. Thank you.

(Ends)

THE VICE-CHAIRMAN: Mr. Shantaram Laxman Naik. ...(Interruptions).. You have three minutes. ...(Interruptions).. You can take one minute extra, total four minutes. ...(Interruptions)..

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (GOA): Thank you, Sir. I will start by referring to Mr. Sitaram Yechury's statement asking for nationalization. See, I am also basically a socialist man in person. I would like the national wealth to be in the hands of the State. But seeing what is happening in the public sector, the vast corruption which is there, we are not able to manage, admittedly, many of our public sector undertakings. If we are able to manage the public sector, then the nationalization could have been the solution. Secondly, you were asking for a ban on export. Today we don't have capacity and that capacity will take years

together for utilizing our iron ores. Sir, a place like Goa where only low grade iron ore is there, that is not utilized at all in the country because there is no scope. Therefore, there is no other alternative than to export low grade iron ore. I am mentioning Goa only. For other iron ores also we do not have that much capacity. Therefore, exporting is the only ...(Interruptions)... Sir, we are having a mineral policy well laid down where so many things have been mentioned. I am not referring to that. The only thing is that the mineral policy says that as per the policy we will be amending the concerned legislation, that is, mineral rules, regulations, etc. I urge upon the Government that as per this policy which is there the necessary amendment to the legislation have to be made because as Kapilji is saying policy is not a law, policy has to be incorporated in the legislation. Therefore, although we have got a mineral policy, we have not amended the concerned legislation. In this mineral policy there is a very important revolutionary change which has been made, namely, wherever we are going to hold, if we have mining leases now, henceforward the tribal and villagers will be the stakeholders. It is not only that we are going to compensate them, it is not that only we are going to resettle them but they are going to be the stakeholder. This is a revolutionary scope which has been given in the policy statement. Therefore, that has to be implemented. Then, Sir, you have to see how these iron ores of Bellary went. Did it disappear all of a sudden, whether a theft was committed or whether it was washed away by rain? Who made it disappear, this requires to be investigated. Sir, this cannot be investigated by an Inquiry Commission. The offence has already taken place. When offence of theft has already taken place,

there has to be an FIR and not only that those who have committed theft be arrested but the conspirators, even if they are in the Government, even if the highest person is there, if he is found to be a conspirator by clearing the files, by helping those persons, then the highest executive person will be a conspirator and that higher executive person in the State has to be arrested. It cannot be done by an Inquiry Commission because it takes years together.

(Contd by 4N/SSS)

SSS-MP /4N/7.40

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (CONTD.): If somebody does not want to take action, the Inquiry Commission is there. Therefore, Inquiry Commission is not a substitute for this. Therefore, I demand that CBI inquiry is the only solution for Bellary theft.

(Ends)

सुश्री सुशीला तिरिया (उड़ीसा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सबको सुन रही थी और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी।

उपसभाध्यक्ष (डा. के.केशव राव) : आपके तीन मिनट हैं।

सुश्री सुशीला तिरिया : सर, तीन मिनट तो ..... एक मिनट तो आपने ही ले लिया है। सर, मैं सबसे पहले grievance के तौर पर यह कहना चाहती हूं कि जहां भी बड़े projects होते हैं, चाहे irrigation के हों, electrification के हों या mining के हों, वहां फॉरेस्ट लैंड होता है और वहां ट्राइबल्स ज्यादा रहते हैं, तो मेरा यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम decisions होने के बावजूद भी उनका proper rehabilitation कभी नहीं होता है। They are always displaced from one place to another in the name of development, whether it is a power project, electrification work or illegal mining of minerals.

इसलिए illegal mining जो हुई है, इसमें ट्राइबल्स का 1 परसेंट भी शेयर नहीं है। वे बेचारे वहां unhygienic atmosphere में रह रहे हैं। वे उनको केवल एक लॉलीपॉप दे रहे हैं कि उनकी एजुकेशन का, हाउसिंग का, सब कुछ वे देखेंगे लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि उड़ीसा में पिछले डेढ़ साल में 35,000 करोड़ से ज्यादा का जो घपला हुआ, तो कमिशन बैठाने की बात की जा रही है। जब किसी स्टेट में illegal mining हो रही है, उसमें आप चाहे Enquiry Commision बैठाइए या सी.बी.आई. से जांच कराइए, जहां पर आपकी कोई मशीनरी न हो और आप स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी या किसी भी investigation authority को लेने जाएं और उनके ऊपर किसी किस्म का विश्वास न हो, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा?

महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि पिछले एक-डेढ़ साल में हमारे यहां क्योंझर और मयूरभंज में सबसे ज्यादा illegal mining हुई है। जहां 100 में से 90 प्रतिशत ट्राइबल्स रहते हैं और जहां जंगल है, वहां Environment Minister कहां रह गए? उनके कानून कहां रह गए? वहां water pollution कहां गया? वहां air pollution कहां गया? क्योंझर के ट्राइबल्स में ऐसी-ऐसी बीमारियां हो रही हैं कि वहां डाक्टरों के जाने के बाद भी, उनकी जांच होने के बाद भी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है। उनको पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। महोदय, Indian Constitution में जो Article 21 है - Right to Live, ट्राइबल्स के लिए मैं इसकी डिमांड करना चाहती हूं। जो सौ सालों से ज्यादा समय से जंगलों में रह रहे थे, illegal mining की वजह से अब उनको इतनी unhygienic जगह में throw करके उनका जीना मुश्किल कर रखा है। महोदय, यह national threat तो ज़रूर है लेकिन उड़ीसा में मयूरभंज में टाटा स्टील को जो iron ore बादामपहाड़, सुलईपाड़ से लेकर जमशेदपुर टाटा में जो Iron & Steel Plant है, तो यह क्यों नहीं हो सकता है जहां प्रचुर मात्रा में iron ore हो, raw manganese हो, वहां के लोगों के economic benefit के लिए कोई इंडस्ट्री वहां पर हो? यदि उस क्षेत्र से सारा आप ट्रांसपोर्ट करके बाहर भेज देंगे, export

कर देंगे, उसके बाद न उनके खेत रहेंगे, न उनके लोग रहेंगे, न आगे उनके जीने का कोई साधन रहेगा। मैं यही निवेदन करना चाहूंगी इसी पॉलिसी के तहत सरकार को या मिनिस्ट्री को सोचना चाहिए कि जहां-जहां पर प्रचुर मात्रा में रेवेन्यू सरकार को देना है, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, वहां इंडस्ट्री रखने के लिए, जैसे मयूरभंज में एक भी इंडस्ट्री नहीं है, तो क्यों नहीं वहां एक स्टील प्लांट बनाया जाए? वहां minerals भी हैं, iron ore भी है, सब कुछ वहां प्रचुर मात्रा में है, उससे आराम से प्लांट बनाया जा सकता है, यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं।

महोदय, हमारे क्योंझर और मयूरभंज में पिछले दिनों बहुत illegal mining हुई है। उड़ीसा असेंबली में Vedanta के बारे में उठा, चाहे Posco के बारे में उठा, लेकिन उनका rehabilitation सदियों से नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन यह है कि उनके लिए तो विधान सभा है, लेकिन क्योंझर और मयूरभंज के ट्राइबल्स के लिए तो विधान सभा भी नहीं है। इसीलिए मैं इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि illegal mining को, specially जो Enquiry Commission under section 3 लगाने का स्टेटमेंट मंत्री जी ने सदन में दिया है....

(4O/SC पर क्रमशः)

-mp/sc/7.45/40

सुश्री सुशीला तिरिया (क्रमागत) : उसमें इन दोनों जिलों को अच्छी तरह से कवर करके जिन लोगों ने paper tampering करके लाइन और बाउंडरी के बाहर लीज़ देने का काम किया है, उनको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए - उसमें चाहे political involvement हो, चाहे बड़े ऑफिसर्स का involvement हो, चाहे ऑफिशियल मैनेजमेंट का involvement हो या किसी कम्पनी या individual का involvement हो - जिसको भी इसमें लिप्त पाया जाता है, उसको दंडित किया जाना चाहिए क्योंकि उनको दंडित किए बिना उन पर आगे रुकावट नहीं लगायी जा सकेगी और इसी तरह से illegal mining चलती रहेगी। धन्यवाद। (समाप्त)

श्री उपसभापति : श्री राम कृपाल यादव। आपने तीन मिनट के लिए रिक्वेस्ट की थी।

श्री राम कृपाल यादव: सर, मुझे पांच मिनट का समय दे दीजिए।

श्री उपसभापति : देखिए। पहले आपने दो मिनट मांगे, फिर तीन मिनट और अब पांच मिनट कह रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव : सर, मैं एक बड़ी पार्टी को represent कर रहा हूं और यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

श्री उपसभापति : आपका नाम नहीं था, फिर भी आपको allow कर रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव (बिहार) : आपकी बड़ी कृपा है। महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री सीताराम येचुरी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने आज एक महत्वपूर्ण सबजेक्ट पर चर्चा आरम्भ की। आज पूरे देश का ध्यान खास तौर पर इस ओर है। महोदय, legal और illegal mines की चर्चा बहुत जबर्दस्त रूप से की जा रही है। मेरा साफ तौर पर यह कहना है कि जो legal mining करने वाले लोग हैं,उनकी आढ़ में ही illegal mining हो रही है। महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो लोग legal mining कर रहे हैं, जिनको हम परमिट देते हैं, जिनके पास authority है, वे सरकार को प्रति टन कितनी राशि दे रहे हैं - मात्र 21 रुपए। दूसरी ओर सारे खर्चे निकालकर उनका जो खर्चा आ रहा है - मजदूरों को देकर, गाड़ी में लगाकर, उठाकर और फिर बंदरगाह तक ले जाने के बाद मात्र 300 रुपए आ रहा है। वे maximum 21 रुपए से 26 रुपए रॉयल्टी दे रहे हैं और 300 रुपए खर्चा आ रहा है। अब उसकी बिक्री कितने में हो रही है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पांच से छः हजार रुपए टन के हिसाब से उसकी बिक्री हो रही है। क्या हम यह नहीं कह सकते कि हमने स्वयं लाइसेंस देकर हमारी जो पॉलिसी है, जो नीति है, उससे ही अवैध रुपया कमाने की व्यवस्था कर रखी है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि illegal mining करने वाले जो लोग हैं, वे कौन लोग हैं। आज legal mining करने वालों की आढ़ में ही illegal mining हो रही है और वह सब illegal mining करके legal mining के नाम पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इस पर गौर करने की

आवश्यकता है। हमारी पॉलिसी कहां है? हमने तो लूट की छूट दे रखी है। हमारी जो नीति और पॉलिसी है, उसके अनुसार हम कह रहे हैं कि लूटो, लूट सको तो लूट लो। उसी में कोई 35 हजार करोड़ रुपया और कोई 36 हजार करोड़ रुपया लूट रहा है। सब लूटते रहेंगे। देश की सम्पत्ति इसी तरह से लूटी जा रही है और चंद लोगों के हाथ में यह पैसा जा रहा है। वे कौन लोग हैं? * इन सब लोगों के पास हिम्मत और साहस है?

श्री उपसभापति : आप नाम मत लीजिए। नाम निकाल दीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : सर, यह fact है, यह सच्चाई है।

श्री एस.एस.अहलुवालिया : सर, वे आहिस्ता-आहिस्ता नाम ले रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव : आप कागजात उठाकर देख लीजिए कि legal mining करने वाले कौन लोग हैं? तमाम कम्पनियां हैं, इनके जैसे और लोग हैं। हम यह साहस नहीं कर सकते कि * पर ..(व्यवधान)..

श्री एस.एस.अहलुवालिया : धीरे-धीरे बोल कोई सुन न ले।..(व्यवधान)..

श्री राम कृपाल यादव : आप तो सुन रहे हैं न। महोदय, यह आश्चर्य की बात है। आपने एक नयी पॉलिसी बनायी है - मैं माननीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं - आप टेलीफोन की auction कर रहे हैं, आपने 3जी का auction किया, आपको हजारों करोड़ का फायदा हुआ। आप air का auction कर रहे हैं। आप क्यों नहीं ऐसी पॉलिसी बनाते कि इसका भी auction करें? इस पर गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा। नहीं तो केन्द्र और राज्य की जो पॉलिसी है, उससे इसी तरह से देश का खजाना लूटा जाता रहेगा और हम चुपचाप हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे तथा दूसरी ओर देश की गरीबी और फटेहाली में जीने वाले लोग मरते रहेंगे, जिन्हें रात-दिन कमाने के बाद भी दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है।

(4पी-एमसीएम पर क्रमशः)

---

* Not recorded.

SC/MCM-USY/4P/7-50

श्री राम कृपाल यादव (**क्रमागत**) : जिसकी चर्चा हमारी बहन कर रही थी और यही हाल होगा, पूरा देश आज उग्रवाद की चपेट में आ रहा है, माओत्स बढ़ते जा रहे हैं, पूरी कन्ट्री पर यह छा रहा है। सर, हम कहां जा रहे हैं, हमको दिमाग खोलना पड़ेगा। इसलिए मैंने यह निवेदन किया है। माननीय मंत्री जी नहीं हैं, पता नहीं कहां चले गए?.....(व्यवधान)

कुछ सम्मानित सदस्य : वे आ रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव : हमें इसकी इच्छा शक्ति जगानी होगी। सर, हमारे यहां एक कहावत है -कम्बल ओढ़ कर घी पीना। हमने तो नकाबपोश ओढ़ लिया है -लीगल माइंस, 21 रुपया टन और दस गुना फायदा और उसकी आड़ में, यही नहीं, सर, अगर लीगल माइंस करने वालों पर नजर रखा जाए, हम अगर उसको 20 किलोमीटर की परमिशन दे रहे हैं तो वह 25 किलोमीटर में फैलकर इल्लीगल माइंस करवा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो लीगल माइंस की आड़ में इल्लीगल काम कराने का काम कर रहे हैं।

श्री उपसभापति : आपने 5 मिनट मांगे थे, अब 5 मिनट हो गए हैं।

श्री राम कृपाल यादव : सर, अब मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैंने आपसे आग्रह किया, क्योंकि भविष्य में मुझे आपसे फिर समय लेना है, इसलिए मैं आपके आदेश का अक्षरशः पालन करुंगा और मैं बैठ जाऊंगा, यह बात कहते हुए कि जिस तरफ मैंने ध्यान आकर्षित कराया है, माननीय मंत्री जी, उस पर कार्रवाई करिए। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के अधिकारी, पदाधिकारी बड़े पैमाने पर उनसे मिले हुए है, जिनको मोटी रकम मिल रही है और देश की सम्पत्ति लूटी जा रही है और हम खुली आंख से देखने का काम कर रहे हैं, इसको स्टॉप करवाया जाए। धन्यवाद, सर।

(समाप्त)

श्री धीरज प्रसाद साहू (झारखंड) : उपसभापति महोदय, अवसर देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं साथ ही अपनी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ख्ाानन के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आमूल बदलाव लाने की सिफारिश की है। उपसभापति जी, हमारे यहां एक कहावत है कि -"हींग लगे फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा।" यह कहावत अवैध खनन के मामले से ज्यादा शायद ही कहीं चरितार्थ होती हो। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो या झारखंड, अवैध खनन का कारोबार हर जगह फल-फूल रहा है। अवैध खनन और झारखंड का बहुत गहरा संबंध है। हमारे यहां खनिज सम्पदा बहुत अधिक मात्रा में है और वहां अवैध खनिज भी जोरों पर चल रहा है। मैं पहले अपने गृह जिला लोहरदगा एवं गुमला और लातेहार जिला की चर्चा करुंगा जहां बाक्साइट की खानें बहुत अधिक मात्रा में हैं, जिन पर जगहों में हिन्डालको (आदित्य बिरला ग्रुप) का लीज है। अपने लीज एरिया के अलावा अगल-बगल के फोरेस्ट एरिया में अवैध खनन का काम अपने ठेकेदारों से बहुत नायाब तरीके से लिया जा रहा है। पहले माइंस को क्लोजर करा दिया जाता है और इसका श्रम मंत्रालय से फोरक्लोजर का प्रमाण पत्र भी जुगाड़ से हासिल कर लिया जाता है और बंद खानों को ठेकेदारों से अवैध खनन कराके इसका लाभ हिन्डाल्को उठा रही है। इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए और कम्पनी पर इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा लगानी चाहिए। उपसभापति महोदय, मेरे पास इसके पूरे सबूत के तौर पर फोटोग्राफ और विडियो भी है लेकिन सदन की मर्यादा का ख्याल करते हुए मैं उन सबूतों को यहां दिखा नहीं सकता। अवैध खनन के कारण माइंस को नुकसान के साथ-साथ फोरेस्ट एरियाज़ में जंगलों की बेरहमी से कटाई हो रही है, जिसका पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ रहा है। यहां रहने वाले गरीब आदिवासियों की जमीन भी अवैध खनन के कारण बर्बाद हो रही है क्योंकि इन गरीब आदिवासियों की कोई सुनने वाला कोई नहीं है। अवैध खनन के कारण कई बार यहां के स्थानीय लोग भी इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर चुके हैं लेकिन इस पर सरकार का ध्यान कभी नहीं गया। इससे सरकार को अरबों रुपए का नुकसान

हर साल हो रहा है। लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध और श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, जिससे देश को पता चल सके कि हमें कितना नुकसान हो रहा है। प्रकृति हम सब की सामूहिक धरोहर है इसलिए खनिज के रूप में प्रकृति ने हमें जो उपहार प्रदान किए हैं, उन पर देश के सभी नागरिकों का साझा अधिकार है। इसके लिए लौह अयस्क के निर्यात पर रोक और अन्य सभी खनिजों, अयस्कों के निर्यात पर अधिक टैक्स लगाने की जरूरत है।

(4Q/GS पर क्रमशः)

PK-GS/4Q/7.55

श्री धीरज प्रसाद साहू (क्रमागत) : मैं आज की चर्चा के माध्यम से अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए प्रक्रिया में सुधार का एक प्रस्ताव देना चाहता हूं। आज हमारे देश के महान नेता की याद में राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जा रहा है। अतः मेरा प्रस्ताव है कि अवैध खननकर्ताओं के लिए अवैध खनन की गई भूमि पर अनिवार्य रूप से अक्षय ऊर्जा का स्रोत विकसित करने की बाध्यता कानून में संशोधन कर बनाई जाए। इससे पैदा होने वाली बिजली नजदीक के गांव को मुहैया कराई जाए और ग्राम सभा को इस प्रावधान के पालन की देख-रेख की जिम्मेदारी दी जाए। इससे न केवल ग्रामीण जनता को लाभ होगा, बल्कि स्वरोजगार के नए साधन मिल सकेंगे। ..(समय की घंटी).. इससे नक्सलियों को अवैध खनन से होने वाली लेवी पर अंकुश लगेगा, नौजवानों के रोजगार के अभाव से पलायन में कमी आएगी और आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम स्वराज का हमारा सपना पूरा हो सकेगा। इससे हमारे देश की बिजली की जरूरत का 15 प्रतिशत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने की राष्ट्रीय नीति और हमारे जीडीपी उत्सर्जन की intensity को कम करने की अंतर्राष्ट्रीय commitment को पूरा करने में भी सहयोग मिलेगा। इस प्रकार समन्वित सतत विकास के लिए इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स को और सशक्त बनाने की जरूरत है, ताकि खनन संबंधी कानून और प्रक्रियाओं का पूरा अनुपालन हो सके। (समाप्त)

MESSAGES FROM LOK SABHA

(i) THE INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 2010

(ii) THE TRADE MARKS (AMENDMENT) BILL, 2010.

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

(I)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2010, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 20th August, 2010.

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

(II)

"In accordance with the provisions of rule 101 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that the following amendments made by Rajya Sabha in the Trade Marks (Amendment) Bill, 2009 at its sitting held on the 10th August, 2010, were taken into consideration and agree to by Lok Sabha at its sitting held on the 20th August, 2010:-

ENACTING FORMULA

1. That at page 1, line 1, **for** the word "Sixtieth", the word "Sixty-first" be **substituted**.

CLAUSE – 1

2. That at page 1, line 2, **for** the figure "2009", the figure "2010" be **substituted**.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Discussion on large-scale illegal mining is concluded. The Leader of the Opposition will speak before the reply is given. Reply will be tomorrow. The House stands adjourned till 11.00 a.m. on Saturday, the 21st August, 2010.

.....

The House then adjourned at fifty-seven minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Saturday, the 21st August, 2010.